

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 21 अगस्त 2023

उदघोषित तिथि: 06 सितंबर 2023

ले.पे.अ. 136/2023 और सि.वि.आ. 8810/2023 (स्थगित) और सि.वि.आ. 8811/2023 (पूर्ण अभिलेख का समन) और सि.वि.आ. 8813/2023 (अतिरिक्त दस्तावेज़) और सि.वि.आ. 14104/2023 (अतिरिक्त दस्तावेज़)

प्रोमोशर्ट एस.एम. एस.ए.

.....अपीलकर्ता

द्वारा:

श्री चंदर एम. लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री स्वाति सुकुमार, श्री एसेनीज़ ओभान, श्री ऋतिक रघुवंश, श्री प्रत्यूष राव, श्री नवीन नागार्जुन, सुश्री आयशा, सुश्री अमीरा धवन अधिवक्तागण।

बनाम

आर्मासुइस और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री प्रवीण आनंद, श्री श्रवण चोपड़ा, सुश्री मधु रेवारिया, सुश्री श्री मिश्रा, श्री अच्युत तिवारी और सुश्री एस. सिंह, प्रत्यर्थी-1 के लिए अधिवक्तागण।

ले.पे.अ. 137/2023 और सि.वि.आ. 8825/2023 (स्थगित)

प्रोमोशर्ट एस.एम. एस.ए

.....अपीलकर्ता

द्वारा: श्री चंदर एम. लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री स्वाति सुकुमार, श्री एसेनीज़ ओभान, श्री ऋतिक रघुवंश, श्री प्रत्यूष राव, श्री नवीन नागार्जुन, सुश्री आयशा, सुश्री अमीरा धवन अधिवक्तागण।

बनाम

आर्मासुइस और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री प्रवीण आनंद, श्री श्रवण चोपड़ा, सुश्री मधु रेवारिया, सुश्री श्री मिश्रा, श्री अच्युत तिवारी और सुश्री एस. सिंह, प्रत्यर्थी-1 के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

## आदेश

यशवंत वर्मा, न्या.

1. वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपीलस को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 04 जनवरी 2023 को दिए गए निर्णय के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। उपरोक्त निर्णय निर्विवाद रूप से उन अपीलों पर दिया गया है जिन्हें व्यापार चिन्ह के उप-पंजीयक के 25 जुलाई 2022 के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई थी, जिसके संदर्भ में आर्मासुइस द्वारा दायर विरोध के नोटिस को खारिज कर दिया गया था और प्रोमोशर्ट एस.एम. एस.ए. द्वारा किए गए व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदनों को व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए स्वीकार करने और आगे संसाधित करने का निर्देश दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 91 के अनुसार लागू किया गया, जो व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत रजिस्ट्रार के आदेश या निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है।

2. प्रत्यर्थीगण ने तत्काल ले.पे.अ. की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1983 की धारा 100-क के आलोक में इसे पोषणीयता नहीं दी जा सकती। धारा 100-क जिसे मूल रूप से 1976 में

प्रस्तावित किया गया था और जैसा कि यह वर्तमान में है, निम्नानुसार सारणीबद्ध रूप में उद्धृत किया गया है: -

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 104, 1976	सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (46/1999)	सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (22/2002)
[100क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं - किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या विधि का बल रखने वाले किसी अन्य लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अपीलीय डिक्री या आदेश से कोई	10. धारा 100-क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन - मूल अधिनियम की धारा 100-क के लिए, निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "100-क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं।— किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या विधि का बल रखने	4. धारा 100-क के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन - मूल अधिनियम की धारा 100-क के लिए [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (46/1999) की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित], निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

<p>अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी और विनिश्चित की जाती है, वहां ऐसी अपील में ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय, निर्देश या आदेश से या ऐसी अपील में पारित किसी डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।]</p>	<p>वाले किसी अन्य लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—</p> <p>(क) जहां मूल या अपीलीय डिक्री से कोई अपील या आदेश पर सुनवाई और निर्णय लिया जाता है, (ख) जहां किसी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत किसी आवेदन पर कोई रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाता है या बनाया जाता है, ऐसे</p>	<p>“100-क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं - किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या विधि के बल वाले किसी भी उपकरण में या उस समय लागू किसी अन्य विधि में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, जहां मूल या अपीलीय डिक्री से कोई अपील या आदेश की सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के</p>
---	---	--

	एकल न्यायाधीश के निर्देश, निर्णय या आदेश से आगे कोई अपील नहीं होगी।	निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी।"
--	---	---

3. प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुतियां देते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 100क के अनुसार, चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए पूर्वोक्त प्रावधान की स्पष्ट भाषा के आलोक में आगे कोई अपील नहीं हो सकती। श्री आनंद ने दलील दी कि संहिता की धारा 100-क, अपनी स्पष्ट भाषा के अनुसार, किसी भी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट या किसी भी विधिक ताकत वाले साधन या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में निहित किसी भी विपरीत बात को अधिभावी करने के लिए नियुक्त की गई है। उनका प्रस्तुतीकरण था कि संहिता की धारा 100-क, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेशों या निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सभी अंतर-न्यायालयीय अपीलों पर रोक लगा देगी। यह प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 100-क, अपील के क्षेत्र को न्यूनतम करने के विधायी इरादे को मूर्त रूप देती है, तथा इस प्रकार किसी भी

ऐसे अधिकार को समाप्त कर देती है, जो अन्यथा लेटर्स पेटेंट के आधार पर उपलब्ध हो सकता है।

4. श्री आनंद ने आगे हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 109 (5) में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के खिलाफ आगे अपील करने का प्रावधान था। विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर जोर दिया कि उपरोक्त के विपरीत, वर्तमान अधिनियम ऐसे किसी भी अधिकार का निर्माण नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया गया कि 1958 के व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 109(5) के समान प्रावधान की अनुपस्थिति भी विधानमंडल के इरादे को विश्वसनीयता प्रदान करती है, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के खिलाफ आगे की अपील के अधिकार को छीनना है।

श्री आनंद के अनुसार, यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है और कमल कुमार दत्ता एवं अन्य बनाम रूबी जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में निर्णायक रूप से सुलझा लिया गया है, जहां संहिता की धारा 100-क के दायरे और लेटर्स पेटेंट प्रावधान पर इसके अधिभावी प्रभाव की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"22. जहाँ तक विधि के सामान्य प्रस्ताव का संबंध है कि अपील एक निहित अधिकार है, प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के अधिकार को

बाद के अधिनियम द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से छीन लिया जा सकता है। संसद ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क में संशोधन करते हुए, 2002 के अधिनियम 22 में संशोधन करते हुए, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खण्ड पीठ में अपील करने के मामले में उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट शक्ति को छीन लिया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क इस प्रकार है:-

"100- क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं। —किसी भी उच्च न्यायालय के लिए या विधि के बल वाले किसी भी साधन में या उस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी भी लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां मूल या अपील्य डिक्री या आदेश से किसी भी अपील की सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।

"23. इसलिए, जहां एकल न्यायाधीश द्वारा मूल आदेश से अपील का निर्णय लिया गया है, वहां आगे कोई अपील प्रदान नहीं की गई है और वह शक्ति जो उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत होती थी, बाद में वापस ले ली गई है। वर्तमान आदेश जो सी.एल.बी. द्वारा पारित किया गया है और उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 10-च के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रदान की गई है, जो मूल आदेश से एक अपील है। फिर उस मामले में उसी उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायापीठ को कोई और लेटर पेटेंट अपील नहीं होगी। इस संशोधन ने उस मामले में लेटर्स पेटेंट की शक्ति को छीन लिया है जहां विद्वान एकल न्यायाधीश मूल आदेश से अपील की सुनवाई करता है। वर्तमान मामले में मूल आदेश सी.एल.बी. द्वारा अधिनियम की



धारा 397 और 398 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 10-च के तहत अपील की गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर दिया है, अतः अब कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि संसद ने अपने विवेक से उसकी शक्ति छीन ली है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तत्कालीन विधि मंत्री के एक पत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वह पत्र वैधानिक प्रावधान को अधिभावी नहीं कर सकता है। जब अधिनियम बहुत स्पष्ट है, तो सदन में विधि मंत्री द्वारा दिया गया कोई भी वक्तव्य शब्दों और उन शब्दों से प्रकट होने वाले आशय को नहीं बदल सकता। विधि मंत्री के पत्र को धारा 100-क के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। विधायिका का इरादा शब्दों में स्पष्ट है और इसका स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए और यह विधि मंत्री द्वारा किसी भी संचार में दिए गए किसी भी बयान के अधीन नहीं हो सकता है। शब्द अपने लिए बोलते हैं। इसे किसी भी तरह से दिए गए किसी भी बयान द्वारा आगे की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां एकल न्यायाधीश ने मूल आदेश से अपील का निर्णय किया है, लेटर पेटेंट का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय की शक्ति को हटा दिया गया है और इसे वर्तमान संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है। इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि जब सी.एल.बी. ने अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तो उसने मूल प्राधिकरण के रूप में अपनी अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया। भले ही यह न्यायालय न हो, लेकिन इसमें न्यायालय के सभी प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए, सी.एल.बी. ने अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश

पारित किया और उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के पास अपील की और उसके बाद आगे कोई अपील दायर नहीं की जा सकी।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

26. इस संबंध में, पी. एस. सतप्पन बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड [(2004) 11 एस.सी.सी. 672] मामले में संविधान न्यायपीठ के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। इस मामले में, संविधान न्यायपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एस.सी.सी. पृ. 675)

"1976 में सम्मिलित धारा 100-क सि.प्र.सं. से यह देखा जा सकता है कि जब विधायिका ने लेटर्स पेटेंट अपील को बाहर करना चाहा तो उसने विशेष रूप से ऐसा किया। 2002 में संशोधित धारा 100-क से यह देखा जा सकता है कि विधायिका ने एक विशिष्ट अपवर्जन का प्रावधान किया है। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अब धारा 100-क के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई भी लेटर पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी। हालाँकि, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जो विधि लागू होगी, वही प्रासंगिक समय की विधि होगी। प्रासंगिक समय पर न तो धारा 100-क और न ही धारा 104 (2) एक पत्र पेटेंट अपील पर रोक लगाती है। धारा 100-क में प्रयुक्त शब्द अत्यधिक सावधानी के लिए नहीं हैं। 1976 और 2002 के संशोधन अधिनियमों द्वारा एक विशिष्ट अपवर्जन प्रदान किया गया है, क्योंकि विधायिका को पता था कि ऐसे शब्दों के अभाव में लेटर्स पेटेंट अपील पर रोक नहीं लगाई जाएगी। विधायिका इस बात से अवगत थी कि उसने धारा 104 (1) में बचत खंड को शामिल किया था और धारा 4 सि.प्र.सं. को शामिल

किया था। इस प्रकार अब एक विशिष्ट अपवर्जन प्रदान किया गया था।

27. इसी तरह, सुबल पॉल बनाम मालिना पॉल [(2003) 10 एस.सी.सी. 361] में उनके प्रभुत्वों को निम्नानुसार देखा गया:(एस.सी.सी. पृ. 368, पैरा 20)

"जब भी विधि में ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क से स्पष्ट होता है।"

28. गंडला पन्नाला भुलक्ष्मी बनाम प्रबंध निदेशक, ए.पी. एस.आर.टी.सी. [ए.आई.आर. 2003 ए.पी. 458 (एफ.बी.)] मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने इस मामले में समान दृष्टिकोण अपनाया है। केशव पिल्लई श्रीधरन पिल्लई बनाम केरल राज्य [ए.आई.आर. 2004 केर 111 (एफ.बी.)] मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने भी यही विचार रखा है। इसलिए, मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि श्री नरीमन द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

5. श्री आनंद ने बताया कि कमल कुमार दत्ता में निर्णय हालांकि अपीलीय कार्यवाही के संदर्भ में दिया गया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पूर्ववर्ती कंपनी विधि बोर्ड के एक आदेश से उत्पन्न, इस प्रस्ताव के लिए एक बाध्यकारी प्राधिकरण है कि संहिता की धारा 100-क किसी भी आगे की अपील के अधिकार को छीन लेती है, भले ही वह पहले किसी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के संदर्भ में मौजूद हो। श्री आनंद ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की

पूर्ण न्यायपीठ द्वारा गंडला पन्नाला भुलक्ष्मी बनाम प्रबंध निदेशक, ए.पी. एस.आर.टी.सी. और अन्य, केरल उच्च न्यायालय द्वारा केशव पिल्लई श्रीधरन पिल्लई और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य मामलों में दिए गए निर्णयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें कमल कुमार दत्ता मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। गंडला पन्नाला में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या लेटर पेटेंट अधिनियम के तहत उपलब्ध अपील के अधिकार को विशेष अधिनियमों के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में संहिता की धारा 100-क के आधार पर छीन लिया जाएगा। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

"11. स्पष्ट रूप से, संहिता की धारा 100-क के समान कोई प्रावधान, जो लेटर पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद किसी एकल न्यायाधीश के डिक्री और निर्णय या आदेश के खिलाफ खण्ड न्यायपीठ में आगे अपील दायर करने पर रोक लगाता है, उस मामले में विचार के लिए नहीं आया था। दूसरी ओर, उक्त निर्णय में यह अंतर्निहित है कि संबंधित वैधानिक अधिनियम हमेशा सर्वोच्च चार्टर से आने वाली शक्ति को बहिष्कृत और प्रभावित कर सकता है जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के डिक्री और निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील प्रदान की जा सकती है।

12. शारदा देवी बनाम बिहार राज्य, 2002 (3) एससीसी 705 में, यह प्रश्न विचारार्थ उठा था कि क्या भूमि अधिग्रहण

अधिनियम, 1894 की धारा 54 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट पीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य थी। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "लेटर्स पेटेंट के आधार पर" उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ एक अपील "एक खण्ड न्यायपीठ के पास होगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 लेटर्स पेटेंट के तहत अपील को बाहर नहीं करती है। धारा 54 में गैर-अस्थाई खंड के तुरंत बाद आने वाला "केवल" शब्द अपील के मंच को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान करता है कि अपील उच्च न्यायालय में होगी न कि किसी अन्य न्यायालय जैसे जिला न्यायालय में। "एक अपील" शब्द इसे उच्च न्यायालय में केवल एक अपील तक सीमित नहीं रखता है। "एक अपील" शब्द अपने व्यापक दायरे में एक लेटर्स पेटेंट अपील भी ले लेगा।"

13. उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 54 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति के लेटर पेटेंट अपील दायर करने के अधिकार को प्रभावित या प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसमें कहा गया है कि "लेटर पेटेंट वह चार्टर है जिसके तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। लेटर्स पेटेंट के तहत उच्च न्यायालय को दी गई शक्तियां उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों के समान हैं। इस प्रकार जब कोई लेटर्स पेटेंट उच्च न्यायालय को एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ अपील करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अपील पर विचार करने का अधिकार तब तक बाहर नहीं होगा जब तक कि संबंधित वैधानिक अधिनियम लेटर्स पेटेंट के तहत अपील को बाहर नहीं करता है। (जोर दिया गया)।

14. हम पहले ही देख चुके हैं कि संहिता की नई सम्मिलित धारा 100-क स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में लेटर पेटेंट में कुछ भी शामिल होने के बावजूद एक विद्वान एकल न्यायाधीश के डिक्री और निर्णय या आदेश के खिलाफ खण्ड न्यायपीठ में आगे की अपील को प्रतिबंधित करती है। लेटर्स पेटेंट, जो खंड न्यायपीठ के समक्ष आगे की अपील का प्रावधान करता है, बरकरार है, लेकिन विशेष अधिनियमों या विधि के बल वाले अन्य उपकरणों के तहत उत्पन्न मामलों के संबंध में भी आगे की अपील करने का अधिकार छीन लिया गया है, चाहे वह किसी मूल या अपीलीय डिक्री या एकल न्यायाधीश द्वारा सुने और तय किए गए आदेश के विरुद्ध हो।

15. वर्तमान मामले में, मोटर वाहन अधिनियम में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश या डिक्री के विरुद्ध खण्ड न्यायपीठ में आगे अपील करने का प्रावधान नहीं है।

16. उपरोक्त सभी कारणों से, हम मानते हैं कि लेटर्स पेटेंट के तहत उपलब्ध अपील का अधिकार संहिता की धारा 100-क द्वारा छीन लिया गया है, यहां तक कि विशेष अधिनियमों या विधि के बल वाले अन्य उपकरणों के तहत उत्पन्न मामलों के संबंध में भी।"

6. श्री आनंद द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि *गंडला पन्नाला* में इस प्रकार व्यक्त किए गए विचार को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पलामनेर शाखा, तिरुपति बनाम एस. सूर्य प्रकाश रेड्डी और अन्य में उक्त उच्च न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों की एक बड़ी न्यायपीठ द्वारा फिर से दोहराया गया था। लेटर पेटेंट के तहत उपलब्ध अंतर-न्यायालय अपील के अधिकार और संहिता की

धारा 100क के प्रभाव के मुद्दे पर पुनर्विचार करते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने *यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस* में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"39. इन निर्णयों का अनुपात यह है कि सक्षम विधायिका लेटर्स पेटेंट में संशोधन कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। निर्विवाद रूप से, संहिता की धारा 100-क सक्षम विधायिका यानी संसद द्वारा अधिनियमित विधि का एक हिस्सा है। संहिता की धारा 100-क में निहित गैर-अस्थाई खंड, जैसा कि 2002 अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, अपील के अधिकार को छीनने का प्रभाव रखता है जो पहले या तो लेटर्स पेटेंट या संहिता सहित विधि के किसी भी प्रावधान के तहत उपलब्ध हो सकता है। धारा 100-क में "किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी लेटर्स पेटेंट में या उस समय लागू किसी अन्य लिखत में या किसी अन्य विधि में" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से एक मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न अपील में एकल न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील को प्रतिबंधित करने के विधायिका के इरादे का संकेत है। धारा 100-क की भाषा यह नहीं बताती है कि लेटर्स पेटेंट के तहत उपलब्ध अपील के अधिकार का अपवर्जन केवल संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों तक ही सीमित है, न कि अन्य अधिनियमों तक। इसलिए, धारा 100-क में निहित गैर-अस्थाई खंड में निहित विधायी इरादे को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए और यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि संहिता से उत्पन्न मामलों में एकल न्यायपीठ द्वारा दिया गया एक अपीलीय निर्णय, साथ ही अन्य अधिनियमों को भी, 1-7-2002 से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

40. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम, 1973 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 54 संदर्भ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 में आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है। सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित किसी पुरस्कार या आदेश के खिलाफ अपील के लिए अन्य अधिनियमों में भी इसी तरह के प्रावधान उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, ऐसी सभी अपीलों की सुनवाई एकल न्यायपीठ द्वारा की जाती है। इन अधिनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले मामले में एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है। ऐसी अपील केवल लेटर्स पेटेंट के धारा 15 के तहत दायर की जा सकती है। हालांकि, लेटर पेटेंट और अन्य सभी वैधानिक अधिनियमों के संदर्भ में धारा 100-क में निहित गैर-अस्थाई खंड के आधार पर, अब इन अधिनियमों से उत्पन्न अपील में एकल न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ लेटर पेटेंट के खंड 15 के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है।

41. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, बड़ी न्यायपीठ को भेजे गए प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:

"2002 के अधिनियम संख्या 22 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधित धारा 100-क को सम्मिलित किए जाने के पश्चात्, विशेष अधिनियम से उत्पन्न अपील में



एकल न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं है।"

7. हम केशव पिल्लई में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भी ध्यान देते हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 54 के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अपील में एक आदेश के संदर्भ में एक समान मुद्दे पर विचार करते हुए उक्त उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"10. धारा 100-क को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (46/1999) की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो 1-7-2002 से प्रभावी हुआ था। वह इस प्रकार है:

"100-क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं,— किसी भी उच्च न्यायालय के लिए या विधि के बल वाले किसी अन्य साधन में या उस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी भी पेटेंट पत्र में कुछ भी निहित होने के बावजूद,—

(क) जहाँ किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की किसी भी अपील की सुनवाई और निर्णय लिया जाता है,

(ख) जहाँ संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत किसी आवेदन पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा कोई रिट, निर्देश या आदेश जारी या किया जाता है, वहाँ ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जाएगी।

11. संशोधन के उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैं:-

"न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने पहले अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ आगे की अपील के मुद्दे की जांच की। समिति ने संहिता की धारा 100-क में उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश की ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस संबंध में आगे की अपील नहीं की जाएगी। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के खिलाफ खण्ड न्यायपीठ में अपील को उत्सादन के लिए संसद द्वारा उपयुक्त अधिनियम बनाने की भी सिफारिश की। धारा 10 एक नई धारा 100-क को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है ताकि उपरोक्त मामलों में आगे कोई अपील न की जा सके।

विधायिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत दायर रिट याचिका का निपटारा करते समय न केवल मूल डिक्री या आदेश से, बल्कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ वादकारी को दिए गए अपील के अधिकार से भी आगे की अपीलों को हटाना चाहता था। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों के मामलों में उच्च न्यायालय में दूसरी अपील पर विचार करने की प्रणाली से बचना था।

12. धारा 100-क को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (22/2002) की धारा 4 द्वारा पुनः संशोधित किया गया था जो 1-7-2002 से प्रभावी हुई थी। वर्तमान में धारा 100-क इस प्रकार है:-

"100-क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं।—

किसी भी उच्च न्यायालय के लिए या उस समय लागू विधि के बल वाले किसी भी दस्तावेज में या किसी अन्य विधि में किसी भी पेटेंट पत्र में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी मूल

या अपील की किसी भी अपील की सुनवाई की जाती है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।

2002 के अधिनियम 22 में निहित उद्देश्यों और कारणों के धारा 3 (ज) में निम्नानुसार कहा गया है:-

"(ज) संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट में उच्च न्यायालयों की खण्ड न्यायपीठ में अपील को बहाल किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 10 ने सभी मामलों में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णयों के खिलाफ अपीलों को समाप्त कर दिया।

13. धारा 100-क किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी लेटर्स पेटेंट में या उस समय लागू विधि के बल वाले किसी भी दस्तावेज में या किसी अन्य विधि में 'कुछ भी निहित होने के बावजूद' शब्दों के साथ शुरू होती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय से दूसरी अपील वर्जित है। इस अधिनियम में या अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान में या किसी विशेष अधिनियम में या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, "इस अधिनियम में या अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान में या किसी विधि में किसी विशेष प्रावधान में या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी," से शुरू होने वाला एक खंड, शुरुआत में एक खंड में जोड़ा जाता है, ताकि संघर्ष की स्थिति में धारा के अधिनियमित भाग को गैर-अस्थाई खंड में उल्लिखित प्रावधान या अधिनियम पर अधिभावी प्रभाव दिया जा सके। यह कहना समतुल्य है कि गैर-अस्थाई खंड में उल्लिखित प्रावधान या अधिनियम के बावजूद, इसके बाद आने

वाला अधिनियम अपना पूर्ण प्रभाव रखेगा। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि गैर-अस्थाई खंड का उपयोग गैर-अस्थाई खंड में उल्लिखित विधि के प्रावधान के दायरे को संशोधित करने के लिए एक विधायी उपकरण के रूप में किया जाता है। अश्विनी कुमार अरबिंदा बोस, (1952) 2 एस.सी.सी. 237: ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 369 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी विधि के अधिनियमित भाग को, जहाँ यह स्पष्ट है, गैर-अस्थाई खंड को नियंत्रित करने के लिए लिया जाना चाहिए, जहाँ दोनों को सामंजस्यपूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। *माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ*, ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 530 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैर-अस्थाई खंड निस्संदेह एक बहुत ही शक्तिशाली खंड है जिसका उद्देश्य उसी अधिनियम या अन्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विचार को बाहर करना है। *अश्विनी कुमार* के मामले (पूर्वोक्त) और *माधव राव सिंधिया* के मामले (पूर्वोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों का *ए.जी. वरदराजुलु बनाम तमिलनाडु राज्य* ए.आई.आर 1998 एस.सी. 1388 में पालन किया गया। यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:-

"यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि एक गैर-अस्थाई खंड के साथ व्यवहार करते समय, जिसके तहत विधायिका एक खंड को अधिरोही प्रभाव देना चाहता है, न्यायालय को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि विधायिका ने किस हद तक एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान पर अधिरोही प्रभाव देने का इरादा किया था। इस संबंध में विधायिका का ऐसा इरादा खंड के अधिनियमित भाग से एकत्र किया जाना है।

इसलिए, विधायिका का इरादा स्पष्ट है। संसद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर रिट याचिकाओं के

मामले को छोड़कर, एकल न्यायाधीश के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 5(ii) के तहत अंतर-न्यायालय अपील दायर करने की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहती थी।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

15. विधायिका का इरादा एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंड न्यायपीठ के समक्ष अंतर-न्यायालयीय अपील को समाप्त करना है। चूंकि सिविल न्यायालय के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने वाले वादी को आगे अपील दायर करने का अवसर नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारा विचार है कि दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अंतर-न्यायालय अपील के अधिकार को छीनने से विशेष विधि के तहत अपील दायर करने वाले वादी को कोई नुकसान नहीं होगा।

16. दोनों अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क के शब्दों से पता चलता है कि यह केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पारित मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से आगे की अपीलों से संबंधित है न कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के प्रावधानों के तहत। यह तर्क दिया जाता है कि धारा 100-क में उपयोग किए गए शब्द "मूल डिक्री या आदेश" केवल सिविल न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत पारित एक डिक्री को संदर्भित करते हैं, न कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम के तहत पारित एक पुरस्कार के तहत।

17. *आई.टी.सी. लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य* (1985 पूरक एस. सी. सी. 476) शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

".....तथापि, जहां केन्द्रीय और राज्य विधान एक ही क्षेत्र को कवर करते हैं, वहां केन्द्रीय विधान ही मान्य होगा। यह भी सर्वविदित है कि जहां दो अधिनियम, एक संसद द्वारा पारित तथा दूसरा राज्य विधायिका द्वारा, आपस में टकराते हैं तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, वहां केन्द्रीय विधि को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

*कुलवंत कौर बनाम गुरदियाल सिंह मान* (2001) 4 एस.सी.सी. 262: (ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 1273) में शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"विशेष या स्थानीय विधि केवल तब तक कार्यात्मक रहेंगी जब तक कि संसद द्वारा इसके विपरीत विधान का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जिस क्षण ऐसी विधि केन्द्रीय विधि के साथ टकराव में आती है तो यह लागू नहीं होता है और इसे निरस्त माना जाता है।" आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था:—

"विधि-पुस्तिका में सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम को शामिल करना संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 13, सूची III के तहत शक्ति प्रदान करने के आधार पर है। संविधान मूल दस्तावेज है और सर्वोच्च है जिसका सभी पर बाध्यकारी प्रभाव है और संविधान के प्रावधानों के आधार पर, सूची I या सूची III के तहत दिए गए संचालन के क्षेत्र के भीतर कानूनों के अनुकूलन के संबंध में संसदीय सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है।

उपरोक्त चर्चा किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क में निहित प्रावधान केरल उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 5 (ii) में निहित प्रावधानों पर प्रबल होंगे, जो एक एकल न्यायाधीश के निर्णय से दो न्यायाधीशों की पीठ को आगे की अपील के संबंध में हैं। हमने पहले ही पाया है कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को केरल उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (13) (ख) के तहत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री, निर्णय या आदेश के रूप में माना जाना चाहिए, न कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय के रूप में। हम केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दायर अपीलों के लिए धारा 100-क की प्रयोज्यता को सीमित करने में कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

18. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह वाद के प्रारंभ होने की तिथि से ही पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि अपील का अधिकार किसी पक्षकार को उस तिथि को प्राप्त होता है जिस दिन भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा न्यायालय को निर्देश दिया जाता है या जिस तिथि को कोई पक्षकार याचिका दायर करता है। यह तर्क दिया जाता है कि अपील का अधिकार निहित अधिकार है और इसे प्रक्रिया में संशोधन द्वारा नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अधिनियम में उच्च न्यायालय में केवल एक अपील का प्रावधान है। उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 5(ii) में निहित प्रावधान के मद्देनजर ही द्वितीय अपील संभव थी। यह अधिकार 2002 के संशोधन अधिनियम 22 द्वारा छीन लिया गया। चूंकि ऐसी अपील केवल उच्च न्यायालय अधिनियम की

धारा 5(ii) में निहित प्रावधान के मद्देनजर ही संभव थी, इसलिए हमारा विचार है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 क के संशोधन के तहत, किसी भी वादी को 1-7-2002 के बाद इस आधार पर आगे अपील करने का कोई मूल अधिकार नहीं हो सकता है कि जिस कार्यवाही से वह अपील उत्पन्न होती है वह 1-7-2002 से पहले शुरू की गई थी।

19. इसलिए हम मानते हैं कि 2002 के अधिनियम 22 द्वारा अंतःस्थापित सिविल प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 100-क को ध्यान में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 5 (ii) के तहत उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (13) (ख) के तहत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय, डिक्री या आदेश से आगे कोई अपील कायम नहीं की जा सकती है। इसलिए, दोनों अपीलों को केवल यह कहते हुए खारिज किया जाना चाहिए कि वे विचारणीय नहीं हैं।

परिणामस्वरूप, 2002 की ए.एफ.ए. संख्या 83 और 87/2002 को सीमित अवधि में खारिज कर दिया जाता है।

8. आगे बढ़ते हुए, श्री आनंद ने रऊफ अहमद जरू बनाम एम.एस.टी. शफीका में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उक्त निर्णय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1977 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से निकला। इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के खिलाफ ले.पे.आ. बनाए रखने योग्य होगा, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इस सवाल का जवाब दिया:-



"7. धारा 100-क सि.प्र.सं. का प्रभाव, जैसा कि केंद्रीय सिविल प्रक्रिया संहिता में 01.07.2002 से लागू किया गया है, एक विशेष अधिनियम के तहत अपीलीय आदेश के खिलाफ ले.पे.आ. की स्थिरता पर *कमल कुमार दत्ता बनाम रूबी जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड*, (2006) 7 एस.सी.सी. 613 मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार किया गया। उस मामले में भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 और 398 के तहत एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी। अपील की स्वीकार्यता पर इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि अपीलकर्ताओं के पास लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के पास जाने का वैकल्पिक उपाय था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि न्यायालय को अपील पर विचार नहीं करना चाहिए तथा इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपीलकर्ताओं के पास कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत वैकल्पिक उपाय मौजूद था। *गरिकापट्टी वीरया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी*, ए.आई.आर. 1957 एससी 540 के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि अपील एक निहित अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता। वैकल्पिक दलील यह भी दी गई कि यदि धारा 15 लागू नहीं होती है तो अपील कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत की जाएगी। इस संबंध में *आरती दत्ता बनाम ईस्टर्न टी एस्टेट (पी) लिमिटेड*, (1988) 1 एस.सी.सी. 523 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और *महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम दाभोल पावर कंपनी*, (2003) 117 कॉम्प कैस 651 (बॉम्बे) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया। दूसरी ओर, अपीलकर्ता की ओर

से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क पर भरोसा किया गया। यह आग्रह किया गया कि धारा 100-क सि.प्र.सं. के तहत बनाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय या डिक्री पर आगे कोई अपील नहीं की जा सकती। प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"21. लेकिन संशोधन के बाद जो शक्ति उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत प्रयोग की जा रही थी, वही शक्ति सी.एल.बी. (कंपनी लॉ बोर्ड) द्वारा अधिनियम की धारा 10-ड के तहत प्रयोग की जा रही है। सी.एल.बी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 10-च के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसलिए, 1991 में संशोधन से पहले जो स्थिति थी वह यह थी कि अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी आदेश से, अपील उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष होती थी, लेकिन संशोधन के बाद, शक्ति सी.एल.बी. को दी गई है और अधिनियम की धारा 10-च के तहत अपील प्रदान की गई है। इस प्रकार, 1-1-1964 से संशोधन द्वारा भाग I-क को शामिल किया गया। लेकिन कंपनी लॉ बोर्ड का गठन और अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने की शक्ति 31-5-1991 से सी.एल.बी. को दी गई और 31-5-1991 से अधिनियम की धारा 10-ड के तहत अपील की व्यवस्था की गई। इसलिए, अधिनियम की धारा 10-ड, 10-च, 397 और 398 को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पूर्ण संहिता है कि अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदनों का

निपटान सी.एल.बी. द्वारा किया जाएगा और सी.एल.बी. का आदेश अधिनियम की धारा 10-च के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध आगे कोई अपील उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि अपील एक निहित अधिकार है और इसलिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत, अपीलकर्ताओं को इस तथ्य के बावजूद अपील करने का वैधानिक अधिकार है कि अधिनियम के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा *गरिकापट्टी वीरया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी* में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह बताया गया है कि अपील एक निहित अधिकार है। बहुमत ने यह विचार व्यक्त किया कि अपील एक निहित अधिकार है। इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

“.....कि आवेदक का तर्क उचित है, कि उसे मुकदमे की तिथि से ही संघीय न्यायालय में अपील करने का अधिकार है और विशेष अनुमति के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। अपील का निहित अधिकार एक मौलिक अधिकार था और, हालांकि इसका प्रयोग केवल प्रतिकूल निर्णय के मामले में ही किया जा सकता था, यह मुकदमे के शुरू होने के समय प्रचलित विधि द्वारा शासित था और इसमें एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अपील के सभी क्रमिक अधिकार शामिल थे, जो वास्तव में एक कार्यवाही का गठन करते थे। इस तरह के अधिकार को केवल बाद के

अधिनियमन द्वारा, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से ही छीना जा सकता था।

22. जहाँ तक विधि के सामान्य प्रस्ताव का संबंध है कि अपील एक निहित अधिकार है, प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के अधिकार को बाद के अधिनियम द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से छीन लिया जा सकता है। संसद ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क में संशोधन करते हुए, 2002 के अधिनियम 22 में संशोधन करते हुए, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खण्ड न्यायपीठ में अपील करने के मामले में उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट शक्ति को छीन लिया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क इस प्रकार है:

'100-क...'

23. इसलिए, जहां एकल न्यायाधीश द्वारा मूल आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय किया गया है, वहां आगे कोई अपील का प्रावधान नहीं किया गया है तथा उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत जो शक्ति थी, उसे बाद में वापस ले लिया गया है। वर्तमान आदेश जो सी.एल.बी. द्वारा पारित किया गया है और उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 10-च के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है, अर्थात् मूल आदेश के विरुद्ध अपील, तो उस स्थिति में उसी उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ में आगे कोई लेटर्स पेटेंट अपील नहीं की जा सकेगी। इस संशोधन ने उस मामले में लेटर्स पेटेंट की शक्ति को छीन लिया है जहां विद्वान एकल न्यायाधीश मूल आदेश के खिलाफ अपील सुनते हैं...."

8. उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 26 में, उच्चतम न्यायालय ने पी.एस. सतप्पन बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड (2004) 11

एस.सी.सी. 672 में संविधान पीठ के निर्णय की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया और उनका हवाला दिया, जिन्हें यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"1976 में सम्मिलित धारा 100-क सि.प्र.सं. से यह देखा जा सकता है कि जब विधायिका ने लेटर्स पेटेंट अपील को बाहर करना चाहा तो उसने विशेष रूप से ऐसा किया। धारा 100-क में, जैसा कि 2002 में संशोधित किया गया था, यह कहा जाना चाहिए कि अब धारा 100-क के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई लेटर पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी। हालाँकि, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जो विधि प्रबल होगी वह प्रासंगिक समय की विधि होगी। प्रासंगिक समय पर न तो धारा 100-क और न ही धारा 104 (2) एक पत्र पेटेंट अपील पर रोक लगाती है। धारा 100-क में उपयोग किए गए शब्द अत्यधिक सावधानी के रूप में नहीं हैं। 1976 और 2002 के संशोधन अधिनियमों द्वारा एक विशिष्ट बहिष्करण प्रदान किया गया है क्योंकि विधायिका को पता था कि इस तरह के शब्दों की अनुपस्थिति में एक लेटर्स पेटेंट अपील पर रोक नहीं लगाई जाएगी। विधायिका इस बात से अवगत थी कि उसने धारा 104 (1) में बचत खंड को शामिल किया था और धारा 4 सि.प्र.सं. को शामिल किया था। इस प्रकार अब एक विशिष्ट अपवर्जन प्रदान किया गया था।

9. यहां यह उल्लेख करना सार्थक है कि *सुबल पॉल बनाम मलिना पॉल* (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती तीन न्यायाधीशों के निर्णय का, जिसका उल्लेख वर्तमान मामले में विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया था और उस पर भरोसा किया गया था, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में

भी उद्धृत किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि *सुबल पॉल बनाम मलिना पॉल* (पूर्वोक्त) मामले में उनके प्रभुत्वों का अवलोकन निम्नानुसार किया गया था:

"जब भी अधिनियम इस तरह के प्रतिबंध का प्रावधान करता है, तो उसे स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा जाता है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क से स्पष्ट होता है।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

12. वर्तमान मामले में, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत एक आवेदन पर विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21.07.2014 के आदेश के विरुद्ध अपील अधिनियम की धारा 47 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें अधिनियम के तहत अपील का प्रावधान है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित एक मूल आदेश की अपील थी। केन्द्रीय सिविल प्रक्रिया संहिता की भांति, राज्य सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क को अधिनियम संख्या VI, 2009, दिनांक 20.03.2009 द्वारा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया:

"उच्च न्यायालय के किसी भी लेटर्स पेटेंट में या राज्य में तत्काल प्रभाव वाले किसी भी दस्तावेज में या किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की किसी भी अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती है और निर्णय लिया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधान केंद्रीय सि.प्र.सं. की धारा 100-क के अनुरूप है। जैसा कि स्वयंसिद्ध है, धारा गैर-अस्थाई खंड से शुरू होती है कि 'उच्च न्यायालय के किसी भी लेटर्स पेटेंट में या विधि के बल वाले किसी भी उपकरण में या राज्य में लागू होने वाले किसी अन्य विधि में कुछ भी शामिल होने के बावजूद'। इस प्रकार, धारा 100-क सि.प्र.सं. के तहत, कोई और अपील प्रदान नहीं की गई है और उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत जो शक्ति थी, उसे विधायी अधिनियम द्वारा वापस ले लिया गया है और इस प्रकार, जहां न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, वहां अंतर-न्यायालय अपील नहीं होगी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21.07.2014 का आदेश, अधिनियम के तहत एक मूल आदेश से अपील में पारित आदेश होने के नाते, उपरोक्त चर्चा की गई विधि की सुस्थापित स्थिति के संदर्भ में, लेटर्स पेटेंट के तहत ऐसे आदेश से आगे कोई अपील/अंतर-न्यायालय अपील नहीं होगी।"

9. इसके बाद यह बताया गया कि *कमल कुमार दत्ता* के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने *मोहम्मद सऊद एवं अन्य बनाम डॉ. (मेजर) शेख महफूज एवं अन्य* में दोहराया था, जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे:-

"9. धारा 100-क सि.प्र.सं. की वैधता को *सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2003) 1 एस.सी.सी. 49: ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 189]* में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने *गंडला पन्नाला भुलक्ष्मी बनाम ए.पी. एसआरटीसी [ए.आई.आर. 2003 ए.पी. 458]*, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने *लक्ष्मीनारायण बनाम शिवलाल गुजर [ए.आई.आर. 2003 एम.पी.*

49]. और केरल उच्च न्यायालय ने केशव पिल्लई श्रीधरन पिल्लई बनाम केरल राज्य [ए.आई.आर. 2004 केर 111] में यह अभिनिर्धारित किया है कि 2002 में धारा 100-क के संशोधन के बाद किसी भी वादी को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किसी अपील में पारित निर्णय या आदेश के खिलाफ आगे अपील करने का कोई ठोस अधिकार नहीं हो सकता है। हम उपरोक्त निर्णयों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

10. कमला देवी बनाम कुशल कंवर [(2006) 13 एससीसी 295: एआईआर 2007 एससी 663] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले दायर ले.पे.आ. ही कायम रखा जा सकेगा। वर्तमान मामले में ले.पे.आ. 2002 के बाद दायर किए गए थे और इसलिए हमारी राय में वे योग्य नहीं हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

14. यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2002 में संशोधित धारा 100-क में कुछ स्पष्ट विरोधाभास प्रतीत होता है। जबकि धारा 100-क के एक भाग में यह कहा गया है कि "जहाँ मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी भी अपील की सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है" (जोर दिया गया है), निम्नलिखित भाग में कहा गया है "ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी"। इस प्रकार, जबकि धारा 100-क का एक भाग एक आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें हमारे विचार से एक अंतरिम आदेश भी शामिल होगा, धारा के बाद वाले भाग में निर्णय और डिक्री का उल्लेख है।

15. इस संघर्ष को हल करने के लिए हमें एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनानी होगी। धारा 100-क को लागू करने का पूरा उद्देश्य



अपीलों की संख्या को कम करना था क्योंकि भारत में जनता को अधिनियम में प्रदान की गई कई अपीलों द्वारा परेशान किया जा रहा था। यदि हम मामले को उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि विचाराधीन ले.पे.आ. बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि यदि इसे बनाए रखने योग्य माना जाता है तो परिणाम यह होगा कि जिला न्यायाधीश के एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ दो अपीलें हो सकती हैं, पहले - विद्वान एकल न्यायाधीश और फिर उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ में, लेकिन जिला न्यायाधीश के अंतिम निर्णय के खिलाफ केवल एक ही अपील हो सकती है। यह हमारी राय में अजीब होगा, और धारा 100-क के उद्देश्य के खिलाफ होगा, यानी अपीलों की संख्या को कम करना।

10. श्री आनंद ने विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से वसंती बनाम वेणुगोपाल (मृत) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से भी प्रेरणा लेने का प्रयास किया, जिसमें संहिता की धारा 100-क की स्थिति और उसके महत्व को इस प्रकार समझाया गया था: -

"13. 1-7-2002 से लागू यह संशोधित प्रावधान यह प्रतिपादित करता है कि किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी लेटर्स पेटेंट में या विधि के बल वाले किसी भी उपकरण में या किसी अन्य विधि में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से कोई अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी और तय की जाती है, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से कोई और अपील नहीं होगी।"

14. इस संशोधित प्रावधान का तात्पर्य और दायरा इस न्यायालय की जांच के दायरे में आया, अन्य के अलावा कमला देवी [कमला देवी बनाम कुशल कंवर, (2006) 13 एससीसी 295] और मोहम्मद सऊद [मोहम्मद सऊद बनाम एसके महफूज, (2010) 13 एससीसी 517: (2010) 4 एससीसी (सिविल) 958] में, जिसमें यह स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल लेटर्स पेटेंट अपील, जो कि 2002 के अधिनियम 22 के तहत उक्त संशोधन के लागू होने से पहले दायर की गई हो, स्वीकार्य होगी और परिणामस्वरूप, उसमें निहित प्रतिबंध के आधार पर, उसके बाद दायर लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं होगी।”

11. हमारे विचारार्थ एक और निर्णय उद्धृत किया गया, जो मेट्रो टायर्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम सतपाल सिंह भंडारी एवं अन्य का था, जो हमारे न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ द्वारा दिया गया था। कमल कुमार दत्ता मामले में दिए गए निर्णय और उसमें निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए उच्चतम न्यायालय के विभिन्न अन्य निर्णयों के बाद, खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

"16. धारा 100क को शामिल करते समय विधायिका का उद्देश्य, जैसा कि कमला देवी (पूर्वोक्त), अवतार नारायण बेहल (पूर्वोक्त) और लक्ष्मीनारायण (पूर्वोक्त) में व्याख्या की गई है, संबंधित प्रावधान को सीमित पूर्वव्यापी प्रभाव देना था। यह विचार व्यक्त किया गया है कि जो अपीलें अंतिम तिथि अर्थात् 1 जुलाई, 2002 से पहले दायर की गई हैं, उन्हें भी बचा लिया जाएगा। यह तर्क कि सि.प्र.सं. की धारा 100क में प्रयुक्त भाषा के बावजूद, एक आवेदक का लेटर्स पेटेंट अपील करने का अधिकार एक

निहित अधिकार है, निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार, सि.प्र.सं. की धारा 100 क में प्रयुक्त भाषा का स्पष्ट अर्थ है कि यदि किसी मूल आदेश या डिक्री पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अंतिम तिथि तक सुनवाई या निर्णय कर लिया जाता है, तो उसके विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जा सकेगी। यह तर्क नहीं है कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अंतिम तिथि के बाद दायर अपील खारिज कर दी जाती है और उसके बाद वह अपील को बहल करने से इनकार कर देता है, तो लेटर्स पेटेंट अपील मान्य होगी। यदि 'सुना और निर्णय लिया' शब्दों को संदर्भ से बाहर पढा जाए तो पूरा प्रावधान निरर्थक हो जाएगा। इसकी व्याख्या संदर्भ को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। धारा 100क को 1 जुलाई, 2002 से संशोधित किया गया था ताकि डिक्री या आदेश के विरुद्ध आगे अपील की संभावना समाप्त हो जाए। मूल उद्देश्य अपील के दायरे को न्यूनतम करना था। यदि श्री सिब्बल की दलील को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक वादी आदेश 43 नियम 1 के तहत अपील कर सकता है और इसे चूक के लिए खारिज होने दे सकता है या अभियोजन की कमी के कारण इसे खारिज करवाने में पूरी तरह से उदासीनता दिखा सकता है और उसके बाद अपनी मर्जी से बहाली के लिए आवेदन दायर कर सकता है और असफल होने पर लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता देते हुए तर्क दे सकता है कि यह बनाए रखने योग्य है। इस प्रकार, यह व्याख्या किसी बेईमान या लापरवाह वादी को लाभ दे सकती है। इसके अलावा, यह सि.प्र.सं. की धारा 100क की योजना के पूरी तरह विरुद्ध होगा और यह विधायी मंशा या उद्देश्य भी नहीं है। न्यायालयों से अपेक्षित है कि वे ऐसे प्रावधान की व्याख्या करें जो विधायी मंशा के उद्देश्य को पूरा करे, जब तक कि वह

असंगति की स्थिति उत्पन्न न कर दे। इस संदर्भ में, हम *मुख्य न्यायाधीश आ.प्र. बनाम एल.वी.ए. दीक्षितुलु*, (1979) 2 एससीसी 34 के निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें संविधान न्यायपीठ ने निर्णय दिया था कि विधायी मंशा को समझना न्यायालय का कर्तव्य है और उक्त उद्देश्य के लिए न्यायालय निर्माण के सुविख्यात नियमों, जैसे विधायी सिद्धांत, संपूर्ण विधि की मूल योजना और रूपरेखा, की सहायता ले सकता है। उनके प्रभुत्व ने विधि के उद्देश्य और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर जोर दिया है।"

12. श्री आनन्द ने हमारे विचारार्थ **गीता देवी और अन्य बनाम पूरन राम रैगर और अन्य** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें पुनः यह राय व्यक्त की गई थी कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अंतर-न्यायालयीय अपील संहिता की धारा 100-क के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं होगी। श्री आनन्द ने हमारा ध्यान **एन.जी. नंदा और अन्य बनाम गुरबक्श सिंह और अन्य** में हमारे न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें पुनः संहिता की धारा 100-क के दायरे और परिधि पर विचार किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा एक वाद के उपशमन को अपास्त करने के आवेदन को अस्वीकार करने तथा उस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष की गई अपील के संदर्भ में दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृतक के उत्तराधिकारियों को वाद की कार्यवाही में पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उक्त

अपील को स्वीकार कर लिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश को हमारे न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष ले.पे.आ. के माध्यम से चुनौती दी गई। वह अपील संहिता की धारा 100-क के आलोक में विचारणीय न होने के कारण खारिज कर दी गई। *एन.जी. नंदा* में हमारे विचारार्थ प्रस्तुत निर्णय वह था जो पुनर्विचार याचिका पर दिया गया था। पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई और खंड न्यायपीठ के मूल निर्णय की पुष्टि की गई।

13. यह ध्यान देने योग्य है कि खण्ड न्यायपीठ ने मूल रूप से अवतार नारायण बहल बनाम सुभाष चंद्र बहल में हमारे न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए ले.पे.आ. को खारिज कर दिया था। *अवतार नारायण बहल* में पूर्ण न्यायपीठ को इस सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया गया था कि क्या पहली अपील पर सुनाए गए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ ले.पे.आ. बनाए रखने योग्य होगा। पूर्ण न्यायपीठ ने नकारात्मक में प्रश्न का उत्तर देते हुए अभिनिर्धारित किया:-

"18. उपरोक्त टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि लेटर पेटेंट द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार को सि.प्र.सं. में उचित प्रावधान लागू करके संसद द्वारा छीन लिया जा सकता है और सि.प्र.सं. की धारा 100क में निहित प्रावधानों ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पहली अपील में निर्णय और आदेश के खिलाफ दूसरी अपील को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

19. विशेष अधिनियम के तहत अपीलीय आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील की स्वीकार्यता पर संहिता की धारा 100 क के

प्रभाव पर कमल कुमार दत्ता बनाम रूबी जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड, (2006) 7 एस.सी.सी. 613 में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के हाल के निर्णय में विचार किया गया। इस मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 और 398 के तहत एक मामले में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी। अपील की स्थिरता पर एक प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर ली गई थी कि अपीलार्थियों के पास लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ से संपर्क करने का वैकल्पिक उपाय है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि न्यायालय को अपीलों पर विचार नहीं करना चाहिए और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अपीलार्थियों के पास कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत वैकल्पिक उपाय है। गरिकापट्टी वीराया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी (पूर्वोक्त) में निर्णय पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील एक निहित अधिकार है और इसे हटाया नहीं जा सकता है। वैकल्पिक निवेदन यह भी किया गया कि यदि खंड 15 लागू नहीं होता है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत अपील की जाएगी। इस संबंध में आरती दत्ता बनाम ईस्टर्न टी एस्टेट (पी) लिमिटेड, (1988) 1 एस.सी.सी. 523 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दाभोल पावर कंपनी, (2003) 117 कॉम्प कैस 651 (बॉम्बे) में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया। दूसरी ओर, अपीलकर्ता की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क पर भरोसा किया गया। यह आग्रह किया गया कि धारा 100-क के तहत बनाए गए प्रतिबंध को देखते हुए ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय या डिक्री पर आगे कोई अपील नहीं

की जा सकती। प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 627 से 630)

"21. लेकिन संशोधन के बाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत प्रयोग की जा रही शक्ति का प्रयोग सी.एल.बी. द्वारा अधिनियम की धारा 10- ड के तहत किया जा रहा है। सी.एल.बी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 10-एफ के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। इसलिए, 1991 में संशोधन से पहले जो स्थिति प्राप्त हो रही थी, वह यह थी कि अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी आदेश से, अपील उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष होती थी। लेकिन संशोधन के बाद सी.एल.बी. को शक्ति दी गई है और अधिनियम की धारा 10-च के तहत अपील की गई है। इस प्रकार, भाग I-क को 1-1-1964 से प्रभावी संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। लेकिन कंपनी विधि बोर्ड का गठन और अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने की शक्ति सी.एल.बी. को 31-5-1991 से प्रभावी रूप से दी गई थी और 31-5-1991 से अधिनियम की खंड 10-च के तहत अपील प्रदान की गई थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 10-ड, 10-च, 397 और 398 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पूर्ण संहिता है कि अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदनों को सी.एल.बी. द्वारा निपटाया जाएगा और सी.एल.बी. का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 10-च के तहत अपील योग्य है। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। श्री नरीमन, प्रत्यर्थियों के विद्वान

वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपील एक निहित अधिकार है और इसलिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत, अपीलकर्ताओं को अपील करने का वैधानिक अधिकार है, इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने गारिकापट्टी वीराया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यह इंगित किया गया है कि अपील एक निहित अधिकार है। बहुमत का विचार था कि अपील एक निहित अधिकार है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया था:

“...कि आवेदक का तर्क उचित है, कि उसके पास वाद की तिथि से संघीय न्यायालय में अपील करने का निहित अधिकार है और विशेष अनुमति के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

अपील का निहित अधिकार एक मौलिक अधिकार था और, हालांकि इसका प्रयोग केवल प्रतिकूल निर्णय के मामले में ही किया जा सकता था, यह वाद के शुरू होने के समय प्रचलित विधि द्वारा शासित था और इसमें एक न्यायालय से दूसरी न्यायालय में अपील के सभी क्रमिक अधिकार शामिल थे, जो वास्तव में एक कार्यवाही का गठन करते थे। इस तरह के अधिकार को केवल बाद के अधिनियमन द्वारा, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से ही छीना जा सकता था।”

22. जहाँ तक विधि के सामान्य प्रस्ताव का संबंध है कि अपील एक निहित अधिकार है, प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के अधिकार को



बाद के अधिनियम द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से छीन लिया जा सकता है। संसद ने 1-7-2002 से प्रभावी अधिनियम, 22/2002 में संशोधन करके सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क में संशोधन करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध खंड न्यायपीठ में अपील के मामले में उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट शक्ति को छीन लिया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क इस प्रकार है:

" 100- क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं।—किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी लेटर्स पेटेंट में या कुछ समय के लिए लागू विधि के बल वाले किसी भी दस्तावेज में या किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की किसी भी अपील की सुनवाई की जाती है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।

23. इसलिए, जहां एकल न्यायाधीश द्वारा मूल आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय किया गया है, वहां आगे कोई अपील का प्रावधान नहीं किया गया है तथा उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत जो शक्ति थी, उसे बाद में वापस ले लिया गया है। वर्तमान आदेश जो सी.एल.बी. द्वारा पारित किया गया है और उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 10-च के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रदान की गई है, जो मूल आदेश से एक अपील है। फिर उस मामले में उसी उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ में कोई और लेटर्स पेटेंट अपील नहीं की जाएगी। इस संशोधन ने उस मामले में लेटर्स पेटेंट की शक्ति को छीन लिया है जहां विद्वान एकल न्यायाधीश मूल आदेश के विरुद्ध

अपील पर सुनवाई करता है। वर्तमान मामले में मूल आदेश सी.एल.बी. द्वारा अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 10-च के तहत अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर दिया है, अतः अब कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि संसद ने अपने विवेक से उसकी शक्ति छीन ली है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान तत्कालीन विधि मंत्री के एक पत्र की ओर आकृष्ट किया। वह पत्र वैधानिक प्रावधान को अधिभावी नहीं कर सकता। जब अधिनियम बहुत स्पष्ट है, तो विधि मंत्री द्वारा सदन में दिया गया कोई भी बयान शब्दों और उन शब्दों से निकले इरादे को नहीं बदल सकता। विधि मंत्री के पत्र को धारा 100-क के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। विधायिका की मंशा शब्दों में स्पष्ट है और उसे उसका स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए तथा वह किसी भी संचार में विधि मंत्री द्वारा दिए गए किसी भी कथन के अधीन नहीं हो सकता। शब्द अपने लिए बोलते हैं। किसी भी तरह से दिए गए किसी भी बयान द्वारा इसकी आगे कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, ऐसे मामले में लेटर्स पेटेंट का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय की शक्ति, जहां एकल न्यायाधीश ने मूल आदेश से अपील का निर्णय किया है, छीन ली गई है और इसे वर्तमान संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है। इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि जब सी.एल.बी. ने अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तो उसने मूल प्राधिकरण के रूप में अपनी अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया। यह भले ही न्यायालय न हो, लेकिन इसमें न्यायालय के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए, सी.एल.बी. ने अधिनियम की धारा 397

और 398 के तहत अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया और उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील की जा सकती है और उसके बाद कोई और अपील दायर नहीं की जा सकती।

24. इस संबंध में, हमारा ध्यान आरती दत्ता बनाम ईस्टर्न टी एस्टेट (पी) लिमिटेड के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया था और उस आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 483 के तहत उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ में अपील की गई थी। इस संदर्भ में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि मात्र प्रक्रियात्मक नियमों की अनुपस्थिति से वादी को अधिनियम द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हम पहले ही उपरोक्त स्पष्ट कर चुके हैं कि इससे पहले अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा किया जा रहा था और इसलिए, अधिनियम की धारा 483 के तहत खंड न्यायपीठ में अपील की जानी थी। यदि उच्च न्यायालय में कंपनी न्यायाधीश द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो अधिनियम की धारा 483 के तहत उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष एक अपील होगी। लेकिन वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए, यह निर्णय प्रत्यर्थियों के लिए कोई मददगार नहीं हो सकता।

25. इस संबंध में, हमारा ध्यान महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दाभोल पावर कंपनी में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि सिविल प्रक्रिया

संहिता की धारा 100-क में संशोधन के बावजूद, अधिनियम की धाराओं 397 और 398 के तहत सी.एल.बी. द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, अपील खंड न्यायपीठ के समक्ष है और उस संबंध में, खंड न्यायपीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4(1) को लागू किया जो कहता है कि इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, इस संहिता की कोई भी बात वर्तमान में लागू किसी विशेष या स्थानीय विधि या प्रदत्त किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति या किसी अन्य विधि द्वारा या उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी और, इसलिए, खंड न्यायपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि लेटर्स पेटेंट अपील एक वैधानिक अपील और विशेष अधिनियम है। इसलिए, अपील खंड न्यायपीठ के पास होगी। हमें यह कहते हुए खेद है कि यह विधि की सही स्थिति नहीं है। हमने पहले ही ऊपर दिए गए तथ्यों की व्याख्या कर दी है और हमने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क की व्याख्या यह इंगित करने के लिए की है कि शक्ति विशेष रूप से विधायिका द्वारा छीन ली गई थी। इसलिए, महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विधि का सही प्रतिपादन नहीं कहा जा सकता है।

26. इस संबंध में, हमारा ध्यान पी.एस. सथप्पन बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड में संविधान न्यायपीठ के निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया। इस मामले में, संविधान न्यायपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एस.सी.सी. पृ. 675)

"धारा 100-क सि.प्र.सं. से, जैसा कि 1976 में डाला गया था, यह देखा जा सकता है कि जब विधायिका ने लेटर्स पेटेंट अपील को बाहर करना चाहा तो उसने विशेष रूप से

ऐसा किया। पुनः, 2002 में संशोधित धारा 100-क से यह देखा जा सकता है कि विधायिका ने एक विशिष्ट अपवर्जन का प्रावधान किया है। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अब धारा 100-क के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर कोई भी लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं होगी। हालाँकि, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जो विधि लागू होगी वह प्रासंगिक समय पर लागू विधि होगी। प्रासंगिक समय पर न तो धारा 100-क और न ही धारा 104(2) ने लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबन्ध लगाया था। धारा 100-क में प्रयुक्त शब्द अत्यधिक सावधानी के लिए नहीं हैं। 1976 और 2002 के संशोधन अधिनियमों द्वारा एक विशिष्ट अपवर्जन प्रदान किया गया है क्योंकि विधायिका जानती थी कि ऐसे शब्दों की अनुपस्थिति में लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा। विधायिका जानती थी कि उसने धारा 104(1) में बचत खंड को शामिल किया था और धारा 4 सि.प्र.सं. को शामिल किया था। इस प्रकार अब एक विशिष्ट अपवर्जन प्रदान किया गया था।”

27. इसी तरह, सुबल पॉल बनाम मालिना पॉल में उनके आधिपत्य ने इस प्रकार देखा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 368, पैरा 20) "जब भी अधिनियम में ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क से पता चलता है।”

28. गंडला पन्नाला भुलक्ष्मी बनाम प्रबंध निदेशक, ए.पी. एसआरटीसी मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। केशव पिल्लई श्रीधरन पिल्लई बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने भी यही विचार रखा है।

इसलिए, मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि श्री नरीमन द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।”

20. इस प्रकार, दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि विशेष अधिनियम के तहत उत्पन्न अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 क द्वारा वर्जित है।

21. सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ ((2003) 1 एससीसी 49) में, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

“धारा 100-क दो प्रकार के मामलों से संबंधित है जिनका निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। एक वह है जहां एकल न्यायाधीश किसी अपीलीय डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करता है। ऐसे मामले में आगे कोई अपील होने के सवाल पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, जहां विचारण न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जाती है, तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या किसी और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। वर्तमान में भी मामले के मूल्य के आधार पर, मूल डिक्री की अपील या तो एकल न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है। जहां दायर की गई नियमित पहली अपील की सुनवाई खंड न्यायपीठ द्वारा की जाती है, वहां अंतर-न्यायालय अपील होने का सवाल ही नहीं उठता। केवल ऐसे मामलों में जहां मूल्य पर्याप्त नहीं है, उच्च न्यायालय के नियम एकल न्यायाधीश द्वारा नियमित प्रथम अपील की

सुनवाई का प्रावधान कर सकते हैं। ऐसे मामले में जहां शामिल राशि नाममात्र है, अपील का एक और अधिकार खंड न्यायपीठ को देना वास्तव में अनावश्यक रूप से काम का बोझ बढ़ाना होगा। हमें नहीं लगता कि अंतर-न्यायालय अपील का प्रावधान न करने से वादियों पर कोई पूर्वाग्रह पड़ेगा, भले ही इसमें शामिल मूल्य बड़ा हो। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय नियमों के अनुसार यह प्रावधान कर सकता है कि खंड न्यायपीठ नियमित प्रथम अपील की सुनवाई करेगी। इस प्रकार, संशोधित प्रावधान धारा 100-क में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

22. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100क के प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एकल न्यायाधीश की डिक्री और आदेश के खिलाफ आगे अपील दायर करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त विधायी घोषणा किसी एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के खिलाफ आगे अपील को प्राथमिकता देने पर प्रतिबंध लगाती है यदि उस समय लागू किसी अन्य विधि में अपील प्रदान की जाती है। इस प्रकार, जैसा कि धारा 100क द्वारा निषिद्ध है, एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के खिलाफ खंड न्यायपीठ में आगे अपील करना वर्जित है, न केवल किसी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत बल्कि किसी विशेष अधिनियम के तहत भी जिसके तहत ऐसी अपील प्रदान की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान किसी भी प्रावधान के अधीन हैं जो उच्च न्यायालय के संबंध में विधायिका या ऐसे प्रावधान करने की शक्ति रखने वाले अन्य प्राधिकारी द्वारा नियत दिन पर या उसके बाद बनाया जा सकता है। संहिता के 100क में गैर-अस्थाई खंड का प्रभाव अपील के अधिकार को छीनने का

हैं जो दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 10 के तहत उपलब्ध है। "किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी लेटर्स पेटेंट में या विधि के बल वाले किसी अन्य साधन या किसी अन्य विधि में निहित किसी भी बात के बावजूद" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से विधायिका के इरादे का संकेत देता है कि मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न होने वाली अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। धारा 100क की भाषा यह सुझाव नहीं देती है कि लेटर्स पेटेंट के तहत उपलब्ध अपील के अधिकार का अपवर्जन केवल संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों तक ही सीमित है, न कि किसी अधिनियम के तहत।

23. श्री अरविंद निगम का अगला निवेदन यह है कि भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 100क एक विशेष अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाएगी, फिर भी वे प्रावधान वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100क को शामिल करने से बहुत पहले शुरू हुई थी। यह सत्य है कि अपील का अधिकार प्रक्रिया का नहीं बल्कि सार का विषय है, और ऐसा अधिकार उस तिथि से निहित हो जाता है जब मूल कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। हालाँकि, अपील का निहित अधिकार किसी बाद के अधिनियम द्वारा छीना जा सकता है, यदि उसमें ऐसा स्पष्ट रूप से प्रावधान हो या आवश्यक आशय हो। भेनोव जी. डेम्बला बनाम प्रेम कुटीर (पी) लिमिटेड, (बॉम्बे), 2003 कंपनी मामले (खंड 117) 643) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ, जिसमें हम में से एक (ए.पी. शाह, मुख्य न्यायाधीश) एक पक्षकार थे, ने



अभिनिर्धारित किया कि धारा 100 क के प्रावधान इस प्रकार हैं कि जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से कोई अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी और तय की जाती है, कोई और अपील नहीं हो सकती। "हैं" शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का आशय यह था कि जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1 जुलाई, 2002 के बाद सुनी और तय की गई हो, वहां आगे कोई अपील स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए, धारा 100क का आवश्यक आशय यह है कि जहां मूल या अपीलीय डिक्री के विरुद्ध अपील का निर्णय 1 जुलाई, 2002 के बाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, वहां आगे कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी। अन्यथा अभिनिर्धारित धारा 100क के स्पष्ट आशय के साथ-साथ उद्देश्य और अंतर्निहित प्रयोजन के भी विपरीत होगा। धारा 100क के संशोधित प्रावधानों को प्रस्तुत करते समय, विधायिका को लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ इस बात की भी चिंता थी कि संशोधित प्रावधानों के लागू होने के बाद नए मामले आने से लंबित मामलों की संख्या और बढ़ जाएगी। परिणामस्वरूप, विधायिका को यह बताना अनुचित होगा कि वाद में देरी को ठीक करने के उद्देश्य से एक प्रावधान को लागू करने की मांग करते समय, विधायिका का इरादा संशोधन लागू होने की तिथि से पहले दायर किए गए सभी मामलों को इसके दायरे से छूट देने का था। जैसा कि पहले देखा गया था, कमल कुमार दत्ता बनाम रूबी जनरल हॉस्पिटल (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय ने इसी तरह की दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।

24. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 100 क को शामिल किए जाने के बाद किसी विशेष अधिनियम जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से उत्पन्न प्रथम अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, अपील स्वीकार्य न होने के कारण खारिज की जाती है।”

14. यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्ण न्यायपीठ ने अवतार नारायण बहल में अपनी राय देते हुए कमल कुमार दत्ता में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के निर्णयों पर ध्यान देने का अवसर मिला था। श्री आनंद ने हमारा ध्यान नासिक हिंग सप्लाइंग कंपनी बनाम अन्नपूर्णा गृह उद्योग भंडार, अहमदाबाद और अन्य में गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें 1958 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109(5) के संदर्भ में अपील की स्थिरता पर संहिता की धारा 100 क के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा गया था। नासिक हिंग सप्लाइंग कंपनी में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया था कि धारा 109(5) के अनुसार अपील का उपाय संहिता में प्रस्तुत धारा 100-क के बावजूद भी लागू रहेगा। जबकि प्रस्तुत किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"21.4 हम सि.प्र.सं. की धारा 100-क पर मधुसूदन वेजीटेबल मामले में खण्ड न्यायपीठ द्वारा दी गई व्याख्या से सहमत हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (जो 1-2-1977 से 30-6-2002 तक लागू रहा) द्वारा धारा 100-क में अंतःस्थापित "अपीलीय डिक्री या आदेश से कोई अपील" अभिव्यक्ति का अर्थ है "एक अपीलीय डिक्री से अपील या एक आदेश से अपील" और इसका मतलब यह नहीं था कि "किसी भी अपीलीय डिक्री से अपील या किसी अपीलीय आदेश से अपील", क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता केवल तीन प्रकार की अपीलों पर विचार करती है।

(क) मूल डिक्रीयों के विरुद्ध अपील (धारा 96)।

(ख) अपीलीय डिक्रीयों के विरुद्ध अपील (धारा 100)।

(ग) आदेशों के विरुद्ध अपील (धारा 104)।

संहिता स्वयं अपीलीय आदेश से किसी अपील की परिकल्पना नहीं करती है, जैसा कि अपीलीय डिक्री से अपील से अलग है। धारा 108 भी इस व्याख्या को पुष्ट करती है। हालाँकि, इस पर हमें और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

21.5 उपरोक्त पैरा 21.2 में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को प्रतिपादित करते समय, न्यायालय ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 आदि जैसे कुछ अन्य अधिनियमों के तहत अपील की स्थिरता के बारे में कोई राय व्यक्त करने से स्पष्ट रूप से परहेज किया। न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि उसे इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए कि क्या धारा 100-क ऐसे विशेष अधिनियमों के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीशों के निर्णयों के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाते हैं और मधुसूदन वेजीटेबल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (ए.आई.आर. 1986

गुजरात 156) के उक्त मामले में स्पष्ट किया कि न्यायालय केवल इस संक्षिप्त प्रश्न से चिंतित था कि क्या सि.प्र.सं. की धारा 100-क सि.प्र.सं. के आदेश 43, नियम 1 के साथ धारा 104 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाते हैं और प्रश्न का उत्तर यह निर्धारित करके दिया कि धारा 100-क स्पष्ट रूप से ऐसे लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाते हैं।

22. पिछले पैराग्राफों में की गई हमारी चर्चा से यह भी पता चलता है कि धारा 100-क, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलीय आदेशों और आदेशों से उत्पन्न होने वाली ऐसी अपीलों के संबंध में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन धारा 100-क, व्यापार चिन्ह अधिनियम जैसे विशेष अधिनियम प्रदत्त अपील के मूल अधिकार को छीनने का दावा नहीं करती है।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

24. हमारे विचार में, जैमिन देसाई मामले (ए.आई.आर. 2000 गुजरात 139) में, इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ केवल आदेश 43, नियम 1 के साथ पठित धारा 104 (1) के तहत आदेश की अपील में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील की स्थिरता के सवाल से संबंधित थी।

शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कनिया, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1786 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और मधुसूदन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड बनाम रूपा केमिकल्स, ए.आई.आर. 1986 गुजरात 156 में इस न्यायालय की एक अन्य खंड न्यायपीठ द्वारा बताए गए उक्त निर्णय के मद्देनजर, जैमिन देसाई मामले (ए.आई.आर. 2000 गुजरात 139) में यह निष्कर्ष कि आदेश 43, नियम 1 के साथ धारा 104(1) के तहत आदेश से अपील में इस न्यायालय के

एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील, निश्चित रूप से सही थी। हालांकि, जैमिन देसाई मामले में उक्त खंड न्यायपीठ के निर्णय के पैराग्राफ 24, 26 और 61 में की गई टिप्पणियां, पैराग्राफ 11 और 12 में विश्लेषित लेटर्स पेटेंट के खंड 15 की भाषा के विपरीत हैं और इस न्यायालय पर लागू बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं करती हैं। हम यह स्पष्ट करने के लिए ये टिप्पणियां कर रहे हैं कि लेटर्स पेटेंट अपील जो सि.प्र.सं. संशोधन अधिनियम, 1999 और 2002 के लागू होने से पहले इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए प्रथम अपीलों में निर्णय के विरुद्ध बनाए रखने योग्य थे (अर्थात् 30 जून, 2002 तक) वे उपरोक्त टिप्पणियों के कारण अक्षम नहीं माने जाते हैं, जिनकी पहली बार में आवश्यकता नहीं थी। यह केवल तभी है जब प्रथम अपील इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1-7-2002 (जो कि सि.प्र.सं. संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 के लागू होने की तिथि है) को या उसके बाद तय की जाती है, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के ऐसे निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष आगे की अपील (अर्थात् लेटर्स पेटेंट अपील) वर्जित होगी।

25. इस निर्णय के पहले भाग में वैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण और निर्णयज विधि की चर्चा यह मानने के लिए पर्याप्त है कि अपील की स्थिरता के लिए प्रारंभिक आपत्ति के समर्थन में प्रत्यर्थियों की ओर से उठाए गए पहले तर्क में कोई सार नहीं है। यह हाल ही में 1999 और 2002 के संशोधन अधिनियमों द्वारा किया गया था कि धारा 100-क को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के खिलाफ "दूसरी" अपील को प्रतिबंधित करने के लिए संशोधित किया गया है, उन मामलों में जहां ऐसी अपील का निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा 1-7-2002 पर या उसके बाद किया जाता है। चूंकि व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (2) और (4) के तहत विचाराधीन दोनों

अपीलों का निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 22-6-1998 और 6-8-1998 पर किया गया था. इसलिए 1999 और 2002 के सि.प्र.सं. संशोधन अधिनियमों द्वारा संशोधित धारा 100-क के प्रावधानों को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

अन्यथा भी व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (5) के तहत इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष अपील करने का अधिकार सि.प्र.सं. की धारा 4 (1) द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित एक विशेष विधि द्वारा प्रदान किया गया है. 1999 और 2002 में इसके संशोधन के बाद भी सि.प्र.सं. की धारा 100-क में "किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद" अभिव्यक्ति इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय से इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील करने के मूल अधिकार को प्रभावित या सीमित नहीं करती है. जहां ऐसा अधिकार एक विशेष मूल विधि द्वारा प्रदान किया जाता है न कि प्रक्रिया के सामान्य विधि द्वारा। इसलिए, धारा 100-क, सि.प्र.सं. के प्रावधान, व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (5) के स्पष्ट प्रावधानों को अधिभावी नहीं करते हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

28. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

- (i) 1999 और 2002 के संशोधन अधिनियमों द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. की धारा 100-क, सि.प्र.सं. की धारा 96, 100 और 104 के तहत अपील में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष आगे अपील करने पर प्रतिबंध लगाती है. जैसा कि इस निर्णय के पैरा 12 में स्पष्ट किया गया है।
- (ii) जहां किसी विशेष विधि में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ में अपील का प्रावधान है. वहां ऐसे विशेष विधि के प्रावधान प्रभावी होंगे, क्योंकि सि.प्र.सं. की धारा 100-क प्रक्रिया के सामान्य विधि का हिस्सा है, जो विशेष विधि द्वारा

प्रदत्त अपील के मूल अधिकार को नहीं छीनता है, भले ही धारा 100-क गैर-अस्थाई खंड से शुरू होती है।

- (iii) व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 109 की उप-धारा (2) और (4) के तहत इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 109 की उप-धारा (5) के तहत इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील, सि.प्र.सं. की धारा 100-क के प्रावधानों के बावजूद, बनाए रखने योग्य हैं, चाहे वह सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1-2-1977 से 30-6-2002 तक लागू) में सम्मिलित गया हो या 1-7-2002 से प्रभावी सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 और 2002 द्वारा संशोधित किया गया हो।
- (iv) नाहन फाउंडरी बनाम मोहनलाल खिमजिभात एंड संस, (1974) 15 गुजरात एल.आर. 897 में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के निर्णय को शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1786 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही निहित रूप से खारिज कर दिया गया है।
- (v) मधुसूदन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड बनाम रूपा केमिकल्स, ए.आई.आर. 1986 गुजरात 156 और जैमिन जे देसाई बनाम जी.सी.सी.आई, ए.आई.आर. 2000 गुजरात 139: 2000 (2) गुजरात एलएच 22 में इस न्यायालय की दो खंड न्यायपीठों के निर्णय यह निर्धारित करते हैं कि सि.प्र.सं. की धारा 104 के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलें स्वीकार्य नहीं हैं, केवल लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत अपीलों की गैर-स्वीकृति तक ही सीमित हैं। उक्त निर्णयों को व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 109 की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई अपीलों जैसे किसी विशेष या स्थानीय विधि के तहत इस न्यायालय की

*खण्ड न्यायपीठ के समक्ष प्रदान की गई अपीलों पर लागू नहीं माना जाना चाहिए।*

15. श्री आनंद के अनुसार, उपरोक्त निर्णय की सराहना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है कि यह उस समय दिया गया था जब 1958 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 (5) विधि की पुस्तक में मौजूद थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि 1999 के अधिनियम में एक समान प्रावधान पाए जाने की अनुपस्थिति में, वैधानिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और इसके परिणामस्वरूप, यह माना जाना चाहिए कि तत्काल अपीलें बनाए रखने योग्य नहीं होंगी।

16. फिर अंत में मद्रास उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. एन. अलाला सुंदरम बनाम आयुक्त, एच.आर. एवं सी.ई. और अन्य मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया, जहां एक बार फिर वही सवाल विचार के लिए आया, हालांकि यह तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संदर्भ में था। मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह ने खंड न्यायपीठ की ओर से इस प्रकार टिप्पणी की: -

*"21. सि.प्र.सं. की धारा 100-क के प्रावधानों के एक सादे अध्ययन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि एकल न्यायाधीश के डिक्री या आदेश से किसी भी उच्च न्यायालय या किसी अन्य लिखत के लिए किसी भी लेटर पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद खण्ड न्यायपीठ में आगे कोई अपील नहीं होगी। एकल*



न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ आगे की अपील दायर करने का पूर्ण निषेध है। यह एक विधायी घोषणा है। उक्त विधायी घोषणा एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के खिलाफ आगे की अपील को प्राथमिकता देने से प्रतिबंधित करती है यदि उस समय लागू किसी अन्य विधि में अपील का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, जैसा कि धारा 100-क द्वारा निषिद्ध है, एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के खिलाफ खण्ड न्यायपीठ में आगे की अपील को प्राथमिकता देना न केवल किसी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत, बल्कि किसी विशेष अधिनियम के तहत भी वर्जित है, भले ही ऐसी अपील उक्त विशेष अधिनियम में प्रदान की गई हो।

22. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. एस. सूर्य प्रकाश रेड्डी, 2006 (4) सी.टी.सी. 97 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक बड़ी न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि सि.प्र.सं. की धारा 100-क का प्रभाव लेटर पेटेंट या सि.प्र.सं. सहित विधि के किसी अन्य प्रावधान के तहत उपलब्ध अपील के अधिकार को छीनने का है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दायर अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील विचारणीय नहीं है। केशव पिल्लई श्रीधरन पिल्लई बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 2004 केर 111, में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है। पूर्ण न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एकल न्यायाधीश के निर्णय से दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष आगे की अपील के संबंध में सि.प्र.सं. की धारा 100-क में निहित प्रावधान केरल उच्च न्यायालय अधिनियम (5/1959) की धारा 5(ii) में निहित प्रावधानों पर प्रबल होंगे। इसमें यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए

निर्णय को केरल उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (13) (ख) के तहत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री/निर्णय/आदेश के रूप में माना जाना चाहिए न कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय के रूप में। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि सि.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत दायर अपील पर धारा 100-क की प्रयोज्यता को सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

24. श्री राघवाचारी और श्री दातार द्वारा फजल अली बनाम आमना खातून, 2005 (1) के.एल.टी 828 (राजस्थान) और सत्य नारायण आगीवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक, 2005 (2) बी.एल.जे.आर. 1580, मेसर्स सनी कोणार्क कंस्ट्रक्शन बनाम झारखंड राज्य, ए.आई.आर. 2006 झार. 78 में उद्धृत उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों को पी. एस. सथप्पन मामले (पूर्वोक्त) में संविधान पीठ और कमल कुमार दत्ता मामले (पूर्वोक्त) में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णयों के आलोक में अच्छी विधि नहीं मानी जा सकती है। इनमें से किसी भी निर्णय में लेटर्स पेटेंट के खंड 44 पर विचार नहीं किया गया था। खंड 44 लेटर्स पेटेंट के सभी प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 71 के तहत सपरिषद्-गवर्नर-जनरल और सपरिषद्-गवर्नर की विधायी शक्ति के अधीन बनाता है और अधिनियम की धारा 72 के तहत आपातकालीन मामलों में गवर्नर-जनरल की भी विधायी शक्ति के अधीन बनाता है और इसमें सभी तरह से संशोधन किया जा सकता है। जैसा कि भारत संघ बनाम मोहिंद्रा सप्लार्ई कंपनी (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के बाद के युग में, गवर्नर-जनरल या परिषद्-गवर्नर की विधायी शक्ति को उपयुक्त विधायिका की शक्ति

के रूप में समझा जाना चाहिए। हसिनुद्दीन खान बनाम समेकन उप निदेशक, 1980 (3) एस.सी.सी. 285 से शुरू होने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला से यह भी स्थापित होता है कि विधायिका को लेटर्स पेटेंट को उत्सादित करना का अधिकार है। सि.प्र.सं. की धारा 100क संसद द्वारा अधिनियमित विधान का एक हिस्सा है। संहिता की धारा 100-क में निहित गैर-अस्थाई खंड का प्रभाव अपील के अधिकार को छीनने का है जो या तो लेटर्स पेटेंट के तहत या संहिता सहित विधि के किसी भी प्रावधान के तहत उपलब्ध हो सकता है। "किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी लेटर्स पेटेंट में या विधि के बल वाले किसी अन्य उपकरण या किसी अन्य विधि में निहित किसी भी बात के बावजूद" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से विधायिका के मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न अपील में एकल न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाने के इरादे का संकेत देता है। धारा 100-क की भाषा यह नहीं बताती है कि लेटर्स पेटेंट के तहत उपलब्ध अपील के अधिकार का अपवर्जन केवल संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों तक ही सीमित है, न कि अन्य अधिनियमों के तहत।

25. श्री वी. राघवचारी का वैकल्पिक निवेदन यह है कि भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 100-क एक विशेष अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाएगी, फिर भी वे प्रावधान लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क को शामिल करने से बहुत पहले शुरू हुई थी। यह सत्य है कि अपील का अधिकार प्रक्रिया का नहीं बल्कि सार का विषय है, और ऐसा अधिकार उस

तिथि से निहित हो जाता है जब मूल कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। हालाँकि, अपील का निहित अधिकार किसी बाद के अधिनियम द्वारा छीना जा सकता है, यदि उसमें ऐसा स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से प्रावधान किया गया हो। भेनाँय जी. डेम्बला बनाम प्रेम कुटीर (पी) लिमिटेड, 2003 (117) कंपनी मामले 643 (बॉम्बे) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ, जिसमें हम में से एक (ए.पी. शाह, मु.न्या.) एक पक्षकार थे, ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 100-क के प्रावधान इस प्रकार हैं कि जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से कोई अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी और तय की जाती है, वहां कोई और अपील नहीं हो सकेगी। "है" शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का आशय यह था कि जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1 जुलाई, 2002 के बाद सुनी और तय की गई हो, वहां आगे कोई अपील स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए, धारा 100-क का आवश्यक आशय यह है कि जहां मूल या अपीलीय डिक्री से अपील 1 जुलाई, 2002 के बाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तय की जाती है, वहां आगे कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी। अन्यथा निर्णय देना स्पष्ट आशय के साथ-साथ धारा 100-क के उद्देश्य और अंतर्निहित प्रयोजन के भी विपरीत होगा। कमल कुमार दत्ता बनाम रूबी जनरल हॉस्पिटल (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय ने इसी तरह की दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। धारा 100क के संशोधित प्रावधानों को प्रस्तुत करते समय, विधायिका को मौजूदा लंबित मामलों के साथ-साथ लंबित मामलों में वृद्धि की भी चिंता थी, जो संशोधित प्रावधानों के लागू होने के बाद नए मामलों के आने से बढ़

जाएगी। नतीजतन, विधायिका को यह आशय देना अनुचित होगा कि वाद में देरी को ठीक करने के उद्देश्य से एक प्रावधान को लागू करने की कोशिश करते समय, विधायिका का इरादा उन सभी मामलों को इसके दायरे से बाहर रखने का होगा, जो संशोधन के लागू होने की तिथि से पहले दायर किए गए हैं।

26. परिणामस्वरूप, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि (तमिलनाडु) हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 72 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर लेटर पेटेंट अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क द्वारा वर्जित है। इसलिए, अपील को योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया जाता है।

17. हमें श्री सिब्बल और श्री लाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ-साथ सुश्री सुकुमार, विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित किया, को सुनने का सौभाग्य मिला। अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 100-क, किसी अंतर-न्यायालयीय अपील पर प्रतिबंध लगाती है, जब वह मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न अपील पर एकल न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की जाती है। विद्वान अधिवक्तागण के अनुसार, संहिता की धारा 100-क द्वारा बनाया गया प्रतिबंध केवल तभी उठाया जाएगा जब एकल न्यायाधीश ने किसी डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया हो। यह पुरजोर आग्रह किया गया कि "डिक्री" और "आदेश" अभिव्यक्तियों को संहिता के तहत विशेष रूप से परिभाषित किया गया है

और जैसा कि संहिता की धारा 2 (14) के पढ़ने से प्रकट होगा, "आदेश" शब्द को सिविल न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। संक्षेप में यह दलील दी गई कि संहिता की धारा 100-क और इसकी प्रयोज्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अपीलीय क्षेत्राधिकार संहिता के तहत परिभाषित "आदेश" के संबंध में था या नहीं।

18. विद्वान अधिवक्तागण ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थियों की ओर से उद्धृत कोई भी निर्णय प्रासंगिक या संगत नहीं होगा, जब हम इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि इन मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार किया था। यह तर्क इसलिए दिया गया क्योंकि अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय के रूप में काम करने वाला नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एंग्लो फ्रेंच ड्रग कंपनी (ईस्टर्न) प्राइवेट लिमिटेड बनाम आर.डी. तिनैकर के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गईं:-

*"14. यह आग्रह किया गया है कि जब परंतुक किसी पक्षकार के संबंध में है, तो वह उस पक्षकार के संबंध में है जो उसकी ओर से उपस्थित हो रहा है, दलील दे रहा है या कार्य कर रहा है; किन्तु जब वह किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के संबंध में है, तो वह ऐसे अभिकर्ता के संबंध में है जो उसकी ओर से उपस्थित हो*

रहा है या कार्य कर रहा है। यह भी आग्रह किया जाता है कि भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक मान्यता प्राप्त अभिकर्ता अभिवचन का हकदार नहीं है, और एक मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा अभिवचन का कार्य परंतुक के दायरे में नहीं आता है। श्री वैद्य जब यह दलील देते हैं तो वे सही हैं। लेकिन श्री वैद्य के तर्क में भ्रांति यह है कि बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट, 1920 की धारा 9, "किसी भी न्यायालय में किसी भी सिविल कार्यवाही" को संदर्भित करती है। जिस प्रश्न पर मुझे विचार करना है वह यह है कि क्या रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही को किसी भी अर्थ में किसी भी न्यायालय में सिविल कार्यवाही माना जा सकता है। रजिस्ट्रार को किसी भी अर्थ में न्यायालय नहीं माना जा सकता है। व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 70 (क) में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार को साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज और उत्पादन के लिए बाध्य करने तथा गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। विधायिका ने उस धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को कुछ प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की हैं। रजिस्ट्रार एक न्यायालय नहीं है। उसमें न्यायालय के कुछ अंश हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह न्यायालय है। यदि अधिनियम में प्रयुक्त भाषा कोई मार्गदर्शन दे सकती है, तो उसे "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 2(ढ) के अनुसार, "न्यायाधिकरण" का अर्थ है "रजिस्ट्रार, या, जैसा भी मामला हो, वह न्यायालय जिसके समक्ष संबंधित कार्यवाही लंबित है।" इस संबंध में, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के निर्णय में दिए गए एक अंश का संदर्भ देना उपयोगी हो सकता है, जो शेल

कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम फेडरल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन  
[[1931] ए.सी. 275.] में दर्ज किया गया था। लॉर्ड सेन्की  
एल.सी. ने अपने प्रभुत्व का निर्णय सुनाते हुए इस प्रकार  
टिप्पणी की (पृष्ठ 296):—

"अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि ऐसे न्यायाधिकरण हैं जिनमें न्यायालय के कई ढाँचे हैं, फिर भी, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के सख्त अर्थ में वे न्यायालय नहीं हैं।"

15. पृष्ठ 297 पर टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

"इस संबंध में इस विषय पर कुछ नकारात्मक प्रस्तावों को गिनना उपयोगी हो सकता है: 1. एक न्यायाधिकरण आवश्यक रूप से इस सख्त अर्थ में एक न्यायालय नहीं है क्योंकि यह एक अंतिम निर्णय देता है। 2. न ही इसलिए कि यह शपथ पर साक्षियों को सुनता है। 3. न ही इसलिए कि दो या दो से अधिक प्रतिद्वंद्वी पक्षकार इसके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, जिसे उसे तय करना होता है। 4. न ही इसलिए कि यह ऐसे निर्णय देता है जो विषयों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। 5. न ही इसलिए कि किसी न्यायालय में अपील की जाती है। 6. न ही इसलिए कि यह एक निकाय है जिसमें एक पदार्थ को दूसरे निकाय द्वारा संदर्भित किया जाता है।"

16. पृष्ठ 298 पर इसे आगे इस प्रकार देखा गया है:-

"एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायिक रूप से कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी वह एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण ही बना रहेगा, जैसा कि सख्ती से तथाकथित न्यायालय से अलग है।"



17. मेरा ध्यान इन री नेशनल कार्बन कंपनी, इंक. [[1934] ए.आई.आर. कैल. 725] में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पेटेंट नियंत्रक तकनीकी रूप से न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाला न्यायालय या न्यायाधिकरण नहीं है। मेरे विचार में, यद्यपि कुछ मामलों में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार की स्थिति न्यायालय के समान हो सकती है, फिर भी वह न्यायालय नहीं है, तथा धारा 9 के प्रावधान उसके समक्ष किसी कार्यवाही पर लागू नहीं होते।

18. श्री वैद्य ने आग्रह किया है कि रजिस्ट्रार को बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट, 1920 के उद्देश्य के लिए न्यायालय माना जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि यद्यपि उस अधिनियम में "न्यायालय" की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन "उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय" की परिभाषा उस अधिनियम की धारा 2(2) द्वारा दी गई है। उस अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"कोई न्यायालय, न्यायाधिकरण, या व्यक्ति जिसकी डिक्री, आदेश, निर्णय या पंचाट उच्च न्यायालय के अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के अधीन है, या इसके बाद हो सकता है;

19. उनका कहना है कि व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है और रजिस्ट्रार एक न्यायाधिकरण है जिसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा उस न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय माना जाना चाहिए। श्री वैद्य द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के उत्तर में, श्री शावक्ष ने बताया कि अभिव्यक्ति "उच्च न्यायालय"

को बॉम्बे प्लीडर्स अधिनियम की धारा 2(1) द्वारा "बॉम्बे न्यायिक उच्च न्यायालय" के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए उस अधिनियम की धारा 2(2) के अर्थ में न्यायाधिकरण वह होना चाहिए जिसके निर्णयों के खिलाफ बॉम्बे न्यायिक उच्च न्यायालय में अपील की जा सके। उन्होंने बताया कि व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76(1) के प्रावधान के तहत, यदि प्रश्नगत व्यापार चिन्ह से संबंधित कोई वाद या अन्य कार्यवाही उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो अपील उस उच्च न्यायालय में या, जैसा भी मामला हो, उस उच्च न्यायालय में की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में वह जिला न्यायालय स्थित है। उनका कहना है कि यदि पूरे भारत में किसी भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है, तो रजिस्ट्रार के निर्णय के खिलाफ केवल उस उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। उनका कहना है कि अपील आवश्यक रूप से बम्बई उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। श्री सवक्ष के तर्क में काफी बल है, यदि श्री वैद्य सही हैं, तो उस समय जब रजिस्ट्रार को यह प्रश्न तय करना होगा कि किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को उसके समक्ष दलील देने की अनुमति दी जाए या नहीं, उसे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या व्यापार चिन्ह से संबंधित कोई कार्यवाही बॉम्बे उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किसी जिला न्यायालय में उस समय लंबित है जब उसके निर्णय से अपील दायर की जा सकती है, एक ऐसी घटना जिसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। भविष्य की अप्रत्याशित घटना को ध्यान में रखते हुए उसका निर्णय सही या गलत साबित हो सकता है। यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार किया जाता है तो अंतहीन भ्रम होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट,

1920 की धारा 2 में प्रकट "उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय" अभिव्यक्ति की परिभाषा से यह अनुमान लगा सकता हूं कि रजिस्ट्रार उस अधिनियम के अर्थ के भीतर एक न्यायालय है।"

19. हमारा ध्यान खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर भी आकर्षित किया गया, जहां रजिस्ट्रार के न्यायालय न होने की स्थिति को दोहराया गया, जैसा कि निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट होता है:-

"22. इयान बार्कले निश्चित रूप से प्रत्यर्थियों के आन्तरिक सॉलिसिटर हैं। वे न केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई अन्य देशों में भी उक्त चिह्न का उल्लंघन करने वाले कई व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इयान बार्कले ने अपने प्रति-शपथपत्र में कहा:

"पहले आवेदक को व्यापार चिह्न जर्नल में उक्त चिह्न पीटर स्कॉट के विज्ञापन की सूचना तब मिली जब उसे वाइल्डबोर और गिबन्स से 20-9-1974 की एक नियमित रिपोर्ट प्राप्त हुई। अफसोस की बात है कि पहले आवेदक ने दिए गए समय के भीतर विरोध दर्ज नहीं कराया..."

इसलिए, प्रत्यर्थीगण अच्छी तरह से जानते थे कि अपीलकर्ता ने पंजीकरण के लिए आवेदन दायर किया था। प्रत्यर्थी 3 और उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 137 सुधार कार्यवाही पर लागू होगा। सकुरा बनाम तानाजी [(1985) 3 एस.सी.सी. 590: ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1279] में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रार एक न्यायालय नहीं है।"

20. यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि 1999 का व्यापार चिन्ह अधिनियम रजिस्ट्रार को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करने के लिए सशक्त कर सकता है जो अन्यथा सिविल न्यायालय को प्रदान की जाती हैं, किन्तु केवल यही उक्त प्राधिकरण को सिविल न्यायालय के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह भी कहा गया कि नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया था कि कब किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय माना जा सकता है। हमारा ध्यान उस निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ की ओर आकर्षित किया गया:

-

*"क्या न्यायाधिकरण एक सिविल न्यायालय है"*

*67. संहिता में "न्यायाधिकरण", "न्यायालय" और "सिविल न्यायालय" शब्दों का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सभी "न्यायालय" "न्यायाधिकरण" हैं, लेकिन सभी "न्यायाधिकरण" "न्यायालय" नहीं हैं। इसी तरह सभी "सिविल न्यायालय" "न्यायालय" हैं लेकिन सभी "न्यायालय" "सिविल न्यायालय" नहीं हैं। "यह बहुत अधिक विवाद में नहीं है कि "न्यायालय" और "न्यायाधिकरण" के बीच व्यापक अंतर यह है कि "न्यायालय" का निर्णय अंतिम है और "न्यायाधिकरण" का निर्णय अंतिम नहीं हो सकता है। हालाँकि, "न्यायाधिकरण", जिसे गवाहों का साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत किया गया है, उसे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अर्थ में सामान्यतः "न्यायालय" माना जाएगा। इसमें न केवल न्यायाधीश और*

मजिस्ट्रेट शामिल हैं, बल्कि मध्यस्थों को छोड़कर वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्हें साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से अधिकृत किया गया है। यह एक समावेशी परिभाषा है। ऐसे अन्य मंच भी हो सकते हैं जो उक्त परिभाषा के दायरे में आ सकते हैं।

68. मध्य प्रदेश राज्य बनाम अंशुमान शुक्ला [(2008) 7 एस.सी.सी. 487] में इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम के अर्थ में कुछ प्राधिकारियों को "न्यायालय" मानते हुए इस प्रकार टिप्पणी की थी: (एस.सी.सी. पृष्ठ 493, पैरा 19 और 21)

"19. साक्ष्य अधिनियम के तहत 'न्यायालयों' की परिभाषा संपूर्ण नहीं है (एम्प्रेस बनाम आशुतोष चकरबुट्टी [आई.एल.आर (1879-80) 4 कैल 483] देखें)। हालाँकि उक्त परिभाषा केवल उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए है, लेकिन सभी प्राधिकारियों को उक्त प्रावधान के अर्थ में न्यायालय माना जाना चाहिए जो साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से अधिकृत हैं। ...

\*\*\*

21. ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण [ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 66] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण जिसका निर्णय अंतिम है और पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है, एक न्यायालय है। उक्त निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय जांच अधिनियम के तहत एक मामले का निर्णय सुनाते हुए कहा कि जांच न्यायालय एक न्यायालय नहीं है क्योंकि इसका निर्णय न तो अंतिम है और न ही पक्षकारों पर बाध्यकारी है।"

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधिकरण में "न्यायालय की सभी सुविधाएं" होने से ही वह न्यायालय हो

जाएगा। (भारत बैंक लिमिटेड बनाम कर्मचारी [1950 एस.सी.सी. 470 : ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 188 : 1950 एस.सी.आर. 459], एस.सी.आर. पैरा 7 और 27 देखें।)

69. सिविल न्यायालय न्याय प्रशासन के लिए विधि द्वारा स्थापित एक निकाय है। हालाँकि, विभिन्न प्रकार की विधियाँ मौजूद हैं, जो विभिन्न प्रकार के न्यायालयों का गठन करते हैं। सिविल न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत कौन से न्यायालय आएंगे, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही निर्धारित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत परिकल्पित सिविल न्यायालयों का उल्लेख इसकी धारा 4 और 5 में मिलता है। कुछ वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष हो सकते हैं, कुछ वाद प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालयों के समक्ष हो सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता स्वयं यह निर्धारित करती है कि राजस्व न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं होंगे।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

71. सिविल न्यायालयों का गठन बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 जैसे अधिनियमों के तहत किया जाता है। सिविल न्यायालयों का वित्तीय और प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र इसके अनुसार तय किया जाता है। हालाँकि, वाद के विषय-वस्तु को निर्धारित करने का अधिकार संहिता की धारा 9 से प्राप्त होता है। हम अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में उक्त प्रावधान की व्याख्या पर थोड़ी देर बाद लौटेंगे।

72. पी. सारथी बनाम एसबीआई [(2000) 5 एस.सी.सी. 355: 2000 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 699] में इस न्यायालय ने कहा कि यद्यपि न्यायालय और सिविल न्यायालय के बीच अंतर होता है, लेकिन यह अभिकिर्धारित किया कि एक न्यायाधिकरण जिसके पास न केवल न्यायालय के ढाँचे हैं, बल्कि निर्णय या

निर्णय देने की शक्ति भी है, जिसमें अंतिमता और अधिकार है, वह सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के अर्थ में न्यायालय होगा। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) के संदर्भ में "न्यायालय" शब्द का व्यापक अर्थ माना जाता है। हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए भी न्यायालय और सिविल न्यायालय के बीच अंतर मौजूद है। पी. सारथी बनाम एसबीआई [(2000) 5 एस.सी.सी. 355: 2000 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 699] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 360-61, पैरा 12-13)

"12. यह ध्यान देने योग्य बात है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 में 'सिविल न्यायालय' की बात नहीं की गई है, बल्कि केवल 'न्यायालय' की बात की गई है। यह आवश्यक नहीं है कि धारा 14 में जिस न्यायालय की बात की गई है, वह 'सिविल न्यायालय' ही हो। न्यायालय के स्वरूप वाला कोई भी प्राधिकरण या न्यायाधिकरण इस धारा के अर्थ में 'न्यायालय' होगा।

13. इस शब्द के सख्त अर्थों में एक न्यायालय का गठन के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि न्यायालय के पास न्यायिक न्यायाधिकरण की कुछ विशेषताओं के अलावा, निर्णय या निश्चित निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए। जिसमें अंतिमता और प्राधिकार होता है जो न्यायिक निर्णय के लिए आवश्यक परीक्षण हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

83. राजस्थान एसआरटीसी मामले [(1997) 6 एस.सी.सी. 100] में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें भगवती देवी [1983 ए.सी.जे. 123 (एस.सी.)] में दिए गए निर्णय के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को

सिविल न्यायालय माना गया था, जिसमें संहिता के आदेश 23 में निहित सिद्धांतों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पर लागू माना गया था। संहिता में एक प्रावधान जो चरित्र में परोपकारी है और उस प्रकृति की स्थिति में सामाजिक न्याय सिद्धांत का पालन करता है, उसे लागू किया गया है, लेकिन वही, हमारी राय में, अपने आप में एक न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय नहीं बनाता है। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजन के लिए न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय क्यों माना गया है।

84. राजस्थान एस.आर.टी.सी. मामले में न्यायालय [(1997) 6 एस.सी.सी. 100] इस आधार पर आगे बढ़ा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 173 के संदर्भ में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक निर्णय से होगी, इस प्रकार यह दर्शाता है कि यह सिविल न्यायालय के पदानुक्रम का एक हिस्सा है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, इस प्रकार, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक न्यायालय है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विपरीत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाती है। दोनों न्यायालय अलग-अलग संरचित हैं और पूरी तरह से अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

89. न्यायाधिकरण को एक सिविल न्यायालय माना जा सकता था बशर्ते वह एक डिक्री पारित कर सके और इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता और/या साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में एक पूर्ण परीक्षण के उपक्रम सहित एक सिविल न्यायालय के सभी गुण थे। अब यह सामान्य विधि है कि अधिनियम के



उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि संसद ने अपने उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण शीघ्रता से वसूलने के लिए पृथक न्यायाधिकरण बनाना उचित समझा, जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में निहित प्रावधानों का सहारा लेना आवश्यक नहीं है, तो हमारी राय में, उद्देश्यपूर्ण अर्थ के सिद्धांत का सहारा लेकर, उसे एक अन्य क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता, जिससे यह न्यायालय मामले को सिविल न्यायालय से न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर सके।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

91. क्या न्यायाधिकरण यह उत्तर देगा कि सिविल न्यायालय की परिभाषा पर सिविल न्यायालय के गठन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए?

92. हमने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायाधिकरण न तो सिविल न्यायालय हैं और न ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय से आम तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र या अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संपर्क किया जा सकता है। उच्च न्यायालय न केवल न्यायालयों पर बल्कि न्यायाधिकरणों पर भी ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन न्यायाधिकरण के निर्णयों और आदेशों से अपीलों का निर्धारण करने के लिए किया गया है।

93. इसलिए, हमारे विचार में, इस मामले में उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत लागू नहीं होते। यदि संसद ने न्यायाधिकरणों को सिविल न्यायालय बनाने का इरादा किया होता, तो एक विधिक

कल्पना हो सकती थी। आंध्र प्रदेश भूमि हड़पने अधिनियम जैसे अधिनियम हैं, जहां इस तरह की विधिक कल्पना की गई है। [वी. लक्ष्मीनारसम्मा बनाम ए. यादैया [(2009) 5 एस.सी.सी. 478: (2009) 2 एस.सी.सी. (क्रि) 711: (2009) 3 स्केल 685] देखें।] जबकि उद्देश्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत एक हितकर सिद्धांत है, इसे ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता, जिससे विसंगति पैदा हो। अन्य बातों के साथ-साथ इसका सहारा तभी लिया जा सकता है, जब अस्पष्टता के कारण कठिनाई या संदेह उत्पन्न हो। इसे तब प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जब अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को बढ़ावा देना आवश्यक हो।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

117. यद्यपि यह अधिनियम एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन अधिनियम की धारा 17 और 18 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अधिकार क्षेत्र के अपवर्जन को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है। निर्विवाद रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 10 लाख रुपये से कम की राशि के अपने दावे को लागू करने के उद्देश्य से सिविल न्यायालयों के समक्ष सिविल वाद दायर करने होंगे। यह केवल उपरोक्त राशि से ऊपर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावों के लिए है कि उन्हें ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करना होगा। यह भी स्पष्ट है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अधिनियम की धारा 17 और 18 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी दावा याचिकाएं दायर करना आवश्यक है। इसका उल्टा सत्य नहीं है। देनदार अपना मुजरा या प्रतिदावा तभी दायर कर सकते हैं जब दावा आवेदन दायर किया गया हो, अन्यथा नहीं। यहां तक कि किसी दी गई स्थिति में भी

बैंक और/या वित्तीय संस्थान न्यायाधिकरण से एक सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिदावे या प्रतिदावे के दावों को प्राप्त करने के लिए एक उचित आदेश पारित करने के लिए कह सकते हैं। न्यायाधिकरण एक उच्चाधिकार प्राप्त न्यायाधिकरण नहीं है। यह एक सदस्यीय न्यायाधिकरण है। कुछ विशेष अधिनियमों के विपरीत, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय माना जाएगा।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

122. श्री देसाई का यह निवेदन कि यह न्यायालय न्यायाधिकरण को संहिता के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दे सकता है, हमारी राय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह का निर्देश अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) पर यह तर्क देने के लिए कि संहिता के प्रावधान लागू हैं, हमारी राय में, उक्त विवाद के खिलाफ है। धारा 22 की उप-धारा (2) संहिता के प्रावधानों को सीमित तरीके से लागू करने से संबंधित है।

123. धारा 22 की उप-धारा (3) एक विधिक कल्पना उठाती है कि न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर और दंड संहिता, 1860 की धारा 196 के सभी उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। यह तथ्य कि एक विधिक कल्पना बनाई गई है और न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय **XXV** के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा, स्वयं यह बताता है कि संसद का सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीनने का इरादा नहीं था। किसी भी मामले में, उक्त विधिक कल्पना का

एक सीमित अनुप्रयोग है। इसका दायरा और बढ़ाया नहीं जा सकता है। भारत बैंक लिमिटेड [1950 एस.सी.सी. 470 : ए.आई.आर 1950 एस.सी 188 : 1950 एस.सी.आर. 459] यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि हालांकि श्रम न्यायालय में न्यायालय के सभी अधिकार हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक न्यायालय नहीं है।

21. यह इस न्यायालय के लिए कुछ अतिरिक्त निर्णयों पर ध्यान देने का उपयुक्त अवसर होगा, जिनका हवाला श्री सिबबल ने अपने इस कथन के समर्थन में दिया था कि अपील लेटर्स पेटेंट के तहत स्वीकार्य होगी। श्री सिबबल ने सबसे पहले हमारा ध्यान महली देवी बनाम चंद्रभान एवं अन्य में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया गया था कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 54 के प्रावधानों के आलोक में लेटर्स पेटेंट के धारा 10 के तहत ले.पे.आ. बनाए रखा जा सकता है।

22. महली देवी मामले में, हमारे न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ को यह विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 54 में निहित प्रतिबंधात्मक नुस्खे उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के उपाय को प्रतिबंधित करेंगे, जो अन्यथा लेटर्स पेटेंट के आलोक में बनाए रखने योग्य हो सकता था। उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्ण न्यायपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

-

"12. विधि के प्रासंगिक प्रावधानों और विषय पर न्यायिक घोषणाओं की उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक कोई अधिनियम स्वयं उच्च न्यायालय में दूसरी अपील पर प्रतिबंध नहीं लगाता है या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को अंतिम नहीं बना देता है (जैसा कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 43 के मामले में है), तब तक लेटर्स पेटेंट अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय से न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष होगी। अधिनियम की धारा 54 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और इसलिए, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक अपील बनाए रखने योग्य होगी। यहां हम नेशनल सिलाई थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चैंडविक एंड ब्रदर्स मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर गौर कर सकते हैं, जिसे ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 357 में दर्ज किया गया है। न्यायालय व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर रहा था। उक्त खंड के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय का निर्णय लेटर्स पेटेंट के तहत उसकी अपीलीयता पर विचार करने के प्रयोजनार्थ एक निर्णय होगा। यह टिप्पणी की गई कि "सामान्यतः जब कोई अपील उच्च न्यायालय में पहुंचती है, तो उसका निर्धारण उस न्यायालय के नियमों या पद्धति और प्रक्रिया के अनुसार तथा चार्टर के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत वह न्यायालय गठित किया गया है और जो उसे उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की विधि और तरीके के संबंध में शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76, उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार प्रदान करती है तथा इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहती। ऐसा होने पर, उच्च

न्यायालय को धारा 76 द्वारा प्रदत्त अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है। उसे उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उसी प्रकार करना होगा जैसे वह अपने अन्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और जब ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो उसका निर्णय लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अंतर्गत अपील के अधीन हो जाता है, जबकि व्यापार चिन्ह अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी नहीं है।"

13. इन टिप्पणियों ने पूरे विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक बार जब अपील इस न्यायालय में आ जाती है तो बाकी कार्यवाही इस न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया के नियमों और चार्टर के प्रावधानों के अनुसार होगी, यानी लेटर्स पेटेंट। एकमात्र अपवाद तब होगा जब कोई अधिनियम विशेष रूप से ऐसी अपील को प्रतिबंधित करता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि इस मामले में अधिनियम, यानी अधिनियम की धारा 54 में दूसरी अपील के अधिकार पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि लेटर्स पेटेंट के तहत दूसरी अपील संबंधित पक्षकार को उपलब्ध होगी।"

23. हमारे न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ को महली देवी मामले में नेशनल सिलाई थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चांडविक एंड ब्रदर्स लिमिटेड मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देने का अवसर मिला। राष्ट्रीय सिलाई धागा मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा था कि क्या व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1940 की धारा 76 के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा

सकेगी। उक्त अधिनियम की धारा 76 में 1940 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की परिकल्पना की गई थी। उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने उचित रूप से टिप्पणी की थी:-

"9. व्यापार चिन्ह अधिनियम, उच्च न्यायालय में अपील के भविष्य के संचालन या व्यवसाय के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान या निर्धारित नहीं करता है, वास्तव में अधिनियम की धारा 77 में यह प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय चाहे तो इस मामले में नियम बना सकता है। स्पष्टतः, अपील के उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद, उसका निर्धारण उस न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया के नियमों के अनुसार तथा चार्टर के उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत वह न्यायालय गठित किया गया है और जो उसे उस अधिकारिता का प्रयोग करने की विधि और तरीके के संबंध में शक्ति प्रदान करता है। यह नियम सुस्थापित है कि जब कोई अधिनियम यह निर्देश देता है कि अपील पहले से स्थापित न्यायालय में की जाएगी, तो उस अपील को उस न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इस नियम को विस्काउंट हाल्डेन, एल.सी. ने नेशनल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड बनाम पोस्टमास्टर जनरल [नेशनल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड बनाम पोस्टमास्टर जनरल, 1913 ए.सी. 546 (एच.एल.)] में बहुत ही संक्षेप में इन शब्दों में कहा है : (ए.सी. पृ. 552)

"...जब किसी प्रश्न को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के किसी स्थापित न्यायालय को संदर्भित करने के लिए कहा जाता है, तो मेरी राय में, इसका तात्पर्य यह है कि उस न्यायालय

की प्रक्रिया की सामान्य घटनाएं जुड़ी हुई हैं, और इसके निर्णयों से अपील का कोई भी सामान्य अधिकार भी जुड़ा हुआ है।”

अडैकप्पा चेट्टियार बनाम चंद्रशेखर थेवर [अडैकप्पा चेट्टियार बनाम चंद्रशेखर थेवर, (1946-47) 74 आई.ए. 264 : 1947 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी. 53] में प्रिवी काउंसिल के माननीय सदस्यों द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया था, जिसमें कहा गया था : (आई.ए. पृष्ठ 271)

“...जहां कोई विधिक अधिकार विवाद में है और देश के सामान्य न्यायालय ऐसे विवाद से निपट रही हैं, वहां न्यायालय उन पर लागू प्रक्रिया के सामान्य नियमों द्वारा शासित होते हैं और यदि ऐसे नियमों द्वारा अधिकृत किया गया हो तो अपील की जा सकती है, भले ही दावा किया गया विधिक अधिकार किसी विशेष अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ हो जो अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है...।”

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

15. अपीलकर्तागण ने उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष इंडियन इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड बनाम व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार [इंडियन इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड बनाम व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार, ए.आई.आर. 1947 सी.ए.एल. 49: 1946 एस.सी.सी. ऑनलाइन सी.ए.एल. 155] में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा, जिसमें विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था।

16. अपील पर सुनवाई करने वाली न्यायपीठ के दोनों विद्वान न्यायाधीशों द्वारा उस मामले में दिए गए बहुत विस्तृत और संपूर्ण निर्णय पर पूर्ण विचार करने के बाद और बहुत सम्मान के साथ हम सोचते हैं कि उस मामले का निर्णय गलत तरीके से



किया गया था और यह निर्णय भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 के बहुत संकीर्ण और प्रतिबंधित अर्थ पर आधारित है और उस निर्णय में लेटर्स पेटेंट के खंड 44 के वास्तविक इरादे और उद्देश्य को पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है।

17. इंडियन इलेक्ट्रिक वर्क्स मामले [इंडियन इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड बनाम व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार, ए.आई.आर. 1947 कैल 49: 1946 एस.सी.सी. ऑनलाइन कैल 155] में दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि 1915 के अधिनियम की धारा 108(1) द्वारा न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के एक या एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग के लिए नियम बनाने का दिया गया अधिकार, अधिनियम की धारा 106(1) और लेटर्स पेटेंट के खंड 16 द्वारा न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार तक सीमित था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार के नियम 1915 के अधिनियम के प्रारंभ के बाद पारित अधिनियम द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं हो सकते हैं और न ही ऐसे अधिनियम के अनुसरण में न्यायालय द्वारा सुनी गई अपील से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी अपील पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार विशेष अधिनियम द्वारा प्रदत्त होने के बाद धारा 106(1) और लेटर्स पेटेंट के खंड 16 द्वारा न्यायालय को प्रदत्त या उसमें निहित नहीं कहा जा सकता है। यह तर्क दोहरे दोष से ग्रस्त है। सर्वप्रथम, यह भारत सरकार अधिनियम, 1915 के अन्य प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 65 और 72 में निहित प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखता है। भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 65 (1) द्वारा विधान परिषद में गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत के भीतर सभी व्यक्तियों, सभी न्यायालयों और सभी स्थानों और चीजों के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। धारा 72 के द्वारा उसे आपातकालीन मामलों में अध्यादेश जारी करने की

शक्ति भी दी गई। इसलिए, 1915 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, उच्च न्यायालय के पास वह सभी अधिकार क्षेत्र था जो अधिनियम के प्रारंभ में उसके पास था और वह ऐसे सभी अधिकार क्षेत्र का भी प्रयोग कर सकता था जो उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विधायी शक्ति द्वारा समय-समय पर उसे प्रदान किए जाते। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों का संदर्भ, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 106 (1) ने प्रतिस्थापित किया, इस प्रतिपादना को काफी स्पष्ट करता है। स्पष्ट शब्दों में धारा 9 ने उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को विधान परिषद में गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों के अधीन कर दिया। धारा 106 केवल उच्च न्यायालय को "न्यायालय के व्यवहार को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रदान करती है, जैसा कि लेटर्स पेटेंट द्वारा उनमें निहित थे, और ऐसे किसी भी लेटर्स पेटेंट के प्रावधानों के अधीन, ऐसी सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्राधिकरण जो अधिनियम के प्रारंभ में उन न्यायालयों में निहित थे। चार्टर अधिनियम, 1861 की धारा 9 में प्रयुक्त शब्द "गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों के अधीन" को इस धारा से हटा दिया गया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम, 1915 की धारा 65 द्वारा गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थीं। उच्च न्यायालयों को प्रारम्भ से ही जो अधिकारिता प्रदान की गई थी, वह सदैव उपयुक्त विधान द्वारा परिवर्तन के अधीन थी। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 (1) ने उच्च न्यायालयों को केवल उस अधिकार क्षेत्र के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया है जिसका उपयोग उन न्यायालयों ने उस अधिनियम के पारित होने पर किया था, दूसरी ओर उन्हें उन सभी अधिकार क्षेत्रों के संबंध में नियम

बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई थी जो तब प्राप्त थीं या जिनके साथ वे इसके बाद निहित हो सकते हैं।

18. लेटर्स पेटेंट का खंड 16, जिस पर कलकत्ता न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा निर्भरता रखी गई थी, इस प्रकार है:

"उच्च न्यायालय बंगाल के सिविल न्यायालयों और इसके अधीक्षण के अधीन सभी अन्य न्यायालयों से अपील और ऐसे मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो वर्तमान में लागू किसी विधि या विनियमन के आधार पर उक्त उच्च न्यायालय में अपील के अधीन हैं।"

यह खंड उचित विधानमंडल की विधायी शक्ति के अधीन भी है जैसा कि लेटर्स पेटेंट के खंड 44 में प्रदान किया गया है। यह खंड इस प्रकार है:

"लेटर्स पेटेंट के प्रावधान विधान परिषद में गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों के अधीन हैं।

ऐसा होने पर कलकत्ता निर्णय में जिस खंड "अब लागू" पर जोर दिया गया था, उसके अंतिम शब्द अपना सारा महत्व खो देते हैं, और इस बिंदु को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। लेटर्स पेटेंट के खंड 44 का वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य खंड 16 और लेटर्स पेटेंट के अन्य खंडों के प्रावधानों का पूरक होना था। इस खंड के बल पर उच्च न्यायालयों को नए अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया अपीलीय क्षेत्राधिकार लेटर्स पेटेंट द्वारा प्रदान किए गए न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में शामिल हो जाता है। 1861 के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 का संदर्भ, जिसे खंड 16 ने प्रतिस्थापित किया, इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है। इस खंड में निम्नलिखित प्रभाव का प्रावधान शामिल था:

"या सिविल प्रक्रिया से संबंधित ऐसी विधियों और विनियमों के आधार पर उक्त उच्च न्यायालय में अपील के अधीन हो जाएगा जो इसके बाद परिषद में गवर्नर द्वारा किए जाएंगे,

(जोर दिया गया)

"अब लागू विधि या विनियम" शब्दों के अतिरिक्त। उपरोक्त उद्धृत शब्दों को बाद के चार्टर के खंड 16 से हटा दिया गया था और केवल "वर्तमान में लागू विधि या विनियम" शब्दों को बरकरार रखा गया था, क्योंकि इन शब्दों को लेटर्स पेटेंट में शामिल किया गया था और एक अलग खंड द्वारा इसके सभी प्रावधानों को नियंत्रित करने के रूप में सामान्य अनुप्रयोग के लिए बनाया गया था। दूसरी ओर, कलकत्ता निर्णय देने वाले न्यायाधीशों ने इस परिवर्तन से यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 16 में निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल उस धारा में उल्लिखित सिविल न्यायालयों से अपीलों की सुनवाई करने तथा वर्ष 1865 तक पारित अधिनियमों और लागू विनियमों के तहत अपीलों की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित था। हमारी राय में विद्वान न्यायाधीश यह सोचने में गलती कर रहे थे कि 1865 के लेटर्स पेटेंट के तहत उच्च न्यायालय के पास जो अपीलीय क्षेत्राधिकार था, वह 1861 के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत उसके पास मौजूद क्षेत्राधिकार से संकीर्ण था। 1861 के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 द्वारा उच्च न्यायालय को जो भी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था, उसे 1865 के लेटर्स पेटेंट (संशोधित) में शामिल किया गया था और उसी माप में और उसी सीमा तक उस चार्टर के खंड 16 और 44 के प्रावधानों द्वारा शामिल किया गया था।"

24. श्री सिब्लल ने वि.प्र. द्वारा पी. एस. सतप्पन (मृतक) बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड और अन्य द्वारा मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के निर्णय पर भी भरोसा व्यक्त किया, हालांकि उक्त निर्णय एक ले.पे.आ. के संदर्भ में दिया गया था, जो संहिता की धारा 100-क के प्रतिस्थापन से पहले स्थापित किया गया था, क्योंकि यह 2002 के संशोधन के बाद है, इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने सही राय दी थी कि अपील अधिकार क्षेत्र में बैठे हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ ले.पे.आ. बनाए रखने योग्य नहीं होगा। यह ध्यान देने योग्य हो जाता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही स्वयं निष्पादन कार्यवाही में सिविल न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न हुई थी। सिविल न्यायालय का निर्णय अपील में लिया गया था जिसे उक्त उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था। एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त अपील को खारिज करने पर, एक ले.पे.आ. दायर किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ ने अपील पर विचार करते हुए कहा कि संहिता की धारा 104 (2) के प्रावधानों को देखते हुए यह बनाए रखने योग्य नहीं होगा। न्या. एस. एन. वरियावा ने बहुमत के लिए बोलते हुए निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न का उत्तर दिया:-

*"20. यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि, जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, माननीय न्यायाधीशों ने लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के प्रासंगिक भाग पर विचार किया, जिसे निर्णय में उद्धृत किया*

गया है, लेकिन दुर्भाग्य से खंड 15 का एक अन्य प्रासंगिक भाग छूट गया है। यदि बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 को पूरी तरह से पढ़ा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय से उक्त उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है, जो उसमें गिने गए कुछ अपवादों के अधीन है। खंड 15 के पहले भाग में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दो प्रकार के आदेशों पर विचार किया गया है जिनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी-पहला मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश का आदेश जो एक निर्णय के बराबर है; और दूसरा, निर्दिष्ट आदेशों के अधीन अपील अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश, जो अपवादात्मक थे, जैसे कि उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपील अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में की गई डिक्री या आदेश के संबंध में अपील अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित निर्णय, या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किया गया आदेश, आदि। इसलिए, स्पष्ट रूप से, लेटर्स पेटेंट के खंड 15 में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील की बात कही गई है, बशर्ते कि जिस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है वह ऐसा निर्णय न हो जो किसी अपीलीय आदेश के विरुद्ध दिया गया हो, जिसका अर्थ यह है कि द्वितीय अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में पारित आदेश के विरुद्ध कोई लेटर्स पेटेंट अपील नहीं होगी। हालांकि, खंड 15 का उत्तरार्द्ध भाग यह प्रावधान करता है कि उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित डिक्री या आदेश के संबंध में

अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में एकल न्यायाधीश के निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जहां निर्णय पारित करने वाला न्यायाधीश यह घोषित करता है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार, धारा 15 के तहत द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भी लेटर्स पेटेंट अपील सक्षम है, बशर्ते मामले पर निर्णय करने वाला न्यायाधीश यह घोषित करे कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है। इसलिए, मूलतः, बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 में अपील का प्रावधान किया गया है – (1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध; (2) अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां एकल न्यायाधीश द्वितीय अपील में बैठा हो या जहां वह पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता हो; और (3) उच्च न्यायालय का निर्णय भले ही दूसरी अपील में पारित किया गया हो, बशर्ते न्यायाधीश इसे खंड न्यायपीठ में अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित करें। चूँकि लेटर्स पेटेंट के प्रासंगिक भाग को निर्णय में निष्कर्षण नहीं किया गया था, इसलिए माननीय न्यायाधीश उपरोक्त दिए गए निष्कर्ष पर पहुँचे, जैसे: (एस.सी.सी. पृष्ठ 28, पैरा 40)

"40. लेटर्स पेटेंट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से दो आवश्यक घटनाओं का पता चलेगा – (1) कि विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उसी उच्च न्यायालय की एक बड़ी न्यायपीठ को पारित किए गए किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी, और (2) जहां विचारण न्यायालय के न्यायाधीश जिला न्यायालयों द्वारा पारित किसी निर्णय या डिक्री के खिलाफ अपील का निर्णय करते हैं, वहां आगे की

अपील केवल तभी होगी जब संबंधित न्यायाधीश इसे खण्ड न्यायपीठ में अपील के लिए उपयुक्त घोषित करते हैं। इस प्रकार, विशेष विधि, अर्थात् लेटर्स पेटेंट, केवल इन दो प्रकार की अपीलों पर विचार करता है और कोई अन्य नहीं। इसलिए, प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए कोई वारंट नहीं है कि यदि आदेश 43 नियम 1 लागू होता है, तो विचारण न्यायाधीश के अपीलीय आदेश के खिलाफ एक खण्ड न्यायपीठ में एक और अपील भी होगी। चूंकि यह न तो उपरोक्त निकाले गए लेटर्स पेटेंट के प्रावधानों द्वारा विचार किया गया है और न ही इसका समर्थन किया गया है, इसलिए इस संबंध में प्रत्यर्थी के तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

21. हमारा विचार है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के प्रासंगिक भाग को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए, इस निर्णय पर इस प्रस्ताव के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खंड न्यायपीठ में कोई अपील स्वीकार्य नहीं है।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

30. इस प्रकार यदि कोई अपील धारा 104(1) द्वारा स्पष्ट रूप से सुरक्षित है, तो उप-धारा (2) ऐसी अपील पर लागू नहीं हो सकती। धारा 104 को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उप-धारा (1) में बचत खंड की अनदेखी करके केवल उप-धारा (2) को पढ़ने से दोनों उप-धाराओं के बीच टकराव पैदा होगा। समग्र रूप से पढ़ें और व्याख्या के सुस्थापित सिद्धांतों पर यह स्पष्ट है कि



उप-धारा (2) केवल उन अपीलों पर लागू हो सकती है जो धारा 104 की उप-धारा (1) द्वारा रक्षित नहीं हैं।

उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त अंतिमता केवल धारा 104 के तहत अपील में पारित आदेशों से जुड़ी है, अर्थात् वे आदेश जिनके खिलाफ "कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य विधि" के तहत अपील की अनुमति नहीं है। इस प्रकार धारा 104 (2) एक लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। सि.प्र.सं. की धारा 4 को लागू करने के विधायी इरादे और धारा 104 (1) में "तत्काल लागू किसी भी विधि द्वारा" शब्दों को भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के विचारों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था कि धारा 104 लेटर्स पेटेंट पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। चूंकि "कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य विधि" के तहत अपीलों में निर्विवाद रूप से एक लेटर्स पेटेंट अपील शामिल है, इस तरह की अपीलों को अब विशेष रूप से रक्षित किया जाता है। खंड 104 को समग्र और समन्वयित रूप से पढा जाना चाहिए। यदि इरादा उप-धारा (1) में विशेष रूप से रक्षित चीजों को बाहर करने का था, तो एक विशिष्ट अपवर्जन होना चाहिए। इस प्रकृति का एक सामान्य अपवर्जन पर्याप्त नहीं होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक सामान्य अपवर्जन कभी भी एक लेटर्स पेटेंट अपील को नहीं हटाएगा। हालांकि, जब धारा 104 (1) विशेष रूप से एक लेटर्स पेटेंट अपील को बचाती है तो इस तरह की अपील को बाहर करने का एकमात्र तरीका धारा 104 (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि एक लेटर्स पेटेंट अपील भी निषिद्ध है। यही कारण है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 निम्नलिखित प्रावधान करती है:

"4. बचत – (1) इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, इस संहिता में अभी लागू किसी विशेष या

स्थानीय विधि या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा, या किसी अन्य विधि द्वारा या उसके तहत निर्धारित किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) विशेष रूप से तथा उप-धारा (1) में निहित प्रतिपादना की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता की कोई भी बात किसी भू-स्वामी या मकान मालिक को किसी समय प्रवृत्त विधि के अधीन कृषि भूमि के किराए की वसूली के लिए ऐसी भूमि की उपज से प्राप्त किसी उपचार को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।”

जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, एक विशिष्ट अपवर्जन किसी विधि के शब्दों से स्पष्ट हो सकता है, भले ही लेटर्स पेटेंट का कोई विशिष्ट संदर्भ न दिया गया हो। लेकिन जहां अधिनियम/धारा में ही स्पष्ट बचत है, वहां इस आशय के सामान्य शब्द कि "अपील नहीं होगी" या "आदेश अंतिम होगा" पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे मामलों में यानी जहां स्पष्ट बचत है, वहां स्पष्ट अपवर्जन भी होना चाहिए। धारा 104 की उप-धारा (2) में किसी भी स्पष्ट अपवर्जन का प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में धारा 100-क का उल्लेख किया जा सकता है। वर्तमान धारा 100-क को 2002 में संशोधित किया गया था। 1976 में शुरू की गई पूर्वर्ती धारा 100-क इस प्रकार है:

"100- क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं। – किसी भी उच्च न्यायालय के लिए या उस समय लागू विधि के बल वाले किसी अन्य दस्तावेज में या किसी अन्य विधि में किसी भी लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी भी अपील

की सुनवाई की जाती है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाता है, ऐसी अपील में ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय या आदेश या ऐसी अपील में पारित किसी डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।

इस प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि जब विधायिका एक लेटर्स पेटेंट अपील को अपवर्जित करना चाहती थी तो उसने विशेष रूप से ऐसा किया। धारा 100-क में उपयोग किए गए शब्द अत्यधिक सावधानी के रूप में नहीं हैं। 1976 और 2002 के संशोधन अधिनियमों द्वारा एक विशिष्ट अपवर्जन प्रदान किया गया है क्योंकि विधायिका को पता था कि इस तरह के शब्दों की अनुपस्थिति में एक लेटर्स पेटेंट अपील पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। विधायिका इस बात से अवगत थी कि उसने धारा 104 (1) में बचत खंड को शामिल किया था और सि.प्र.सं. की धारा 4 को शामिल किया था। इस प्रकार अब एक विशिष्ट अपवर्जन प्रदान किया गया था। 2002 के बाद, धारा 100-क इस प्रकार है:

"100-क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं— किसी भी उच्च न्यायालय के लिए या उस समय लागू विधि के बल वाले किसी भी दस्तावेज में या किसी अन्य विधि में किसी भी पेटेंट लेटर्स में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी भी अपील की सुनवाई और निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जाएगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ फिर से विधायिका ने एक विशिष्ट बहिष्करण का प्रावधान किया है। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अब धारा 100-क के आधार पर कोई भी लेटर पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी। हालाँकि, यह एक स्वीकृत

स्थिति है कि जो कानून प्रबल होगा वह प्रासंगिक समय पर कानून होगा। प्रासंगिक समय पर न तो धारा 100-क और न ही धारा 104 (2) एक पत्र पेटेंट अपील पर रोक लगाती है।

31. उपरोक्त सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, लेटर्स पेटेंट के धारा 15 के तहत अपील उस समय लागू कानून द्वारा प्रदान की गई अपील है। इसलिए, धारा 104 की उप धारा (2) द्वारा परिकल्पित अंतिमतः ऐसे कानून के तहत पारित अपील से जुड़ी नहीं थी।

25. पी.एस. सतप्पन में निर्णय एक लेटर्स पेटेंट के संबंध में एक विशिष्ट वैधानिक बार के अस्तित्व पर जोर देता है और यह इस बात का निर्धारक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील होगी या नहीं। यद्यपि पी.एस. सतप्पन के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास संहिता की धारा 100-क को नोटिस करने का अवसर था, लेकिन उसने इस तथ्य पर ध्यान दें कि जबकि उक्त प्रावधान एक लेटर्स पेटेंट को प्रतिबंधित करता प्रतीत होता है, क्योंकि उन मामलों में अपील संशोधित धारा 100-क के लागू होने से पहले शुरू की गई थी, मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया निष्कर्ष मान्य नहीं था। उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते समय, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी कीं:-

"33. यह भी तर्क दिया गया कि यदि धारा 104 सि.प्र.सं. की व्याख्या ऐसी है, तो यह एक विसंगत स्थिति पैदा कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप भेदभाव हो सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के तहत अपील होगी, जबकि ऐसी अपील उस मामले में उपलब्ध नहीं

होगी जहां आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में पारित किया जाता है। साथ एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड [ए.आई.आर. 1965 एस.सी.] में इस अदालत के समक्ष इसी तरह का तर्क दिया गया था। 1442 (1965) 2 एस.सी.आर. 756] लेकिन इसे निम्नलिखित शब्दों में निरस्त कर दिया गया था:(एस.सी.आर पृ.762 सी-जी)

" यह तर्क कि लेटर्स पेटेंट की धारा 10 और 11 के संयुक्त पठन से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 10 का पहला भाग भी केवल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलों से संबंधित है, इसमें कोई बल नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया है, धारा 11 एक न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ एक उपयुक्त विधायिका द्वारा उच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करने पर विचार करता है। शब्दों की व्यापकता से विचलित होने से बहुत दूर' उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय धारा 11 इंगित करता है कि उक्त निर्णय एक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक निर्णय को स्वीकार करता है। थोड़ा जोर देते हुए यह कहा जाता है कि यदि इस निर्माण को स्वीकार किया जाता है, तो एक विसंगति होगी, अर्थात्, जिस मामले में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री के संबंध में अपनी अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, उस न्यायालय में आगे की अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि उक्त न्यायाधीश यह घोषणा नहीं करता है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है, जबकि, यदि अपनी दूसरी अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उसने

किसी न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में निर्णय पारित किया है, तो मामले को आगे की अपील पर उक्त उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए ऐसी किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। यदि विधायिका का इरादा स्पष्ट है, तो उन संभावित कारणों पर अटकलें लगाने की अनुमति नहीं है जिन्होंने विधायिका को दो वर्गों के मामलों के बीच अंतर करने के लिए प्रेरित किया। यह हो सकता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि विधायिका ने उस मामले में एक सीमा लागू करना उचित समझा जहां 3 न्यायालयों ने निर्णय दिया था, जबकि उसने उस मामले में सीमा लागू करना उचित नहीं समझा जहां केवल एक न्यायालय ने निर्णय दिया था।

34. हम उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय के तर्क के साथ सम्मानजनक सहमति पाते हैं। यही तर्क इस निवेदन के संबंध में भी लागू होगा कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 104 (2) एक पत्र पेटेंट अपील पर रोक नहीं लगाती है तो एक विसंगत स्थिति उत्पन्न होगी जैसे कि मामला उच्च न्यायालय में आने के लिए एक और अपील की अनुमति दी जाएगी लेकिन यदि यह जिला न्यायालय में जाता है तो एक और अपील नहीं होगी। एक अपील एक संविदा जनित है। यदि कोई संविदा अपील की अनुमति देता है, तो यह झूठ होगा। यदि कोई संविदा अपील की अनुमति नहीं देता है, तो वह झूठ नहीं बोलेगा। अतः इसके लिए उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संरक्षक और वार्ड अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मामलों में आगे की अपील की अनुमति है, जबकि मध्यस्थता अधिनियम के तहत आगे की अपील पर रोक है। इस प्रकार विभिन्न कानूनों में अपीलों के संबंध में अलग-

अलग प्रावधान हैं। इसमें कोई विसंगति नहीं है। जिला न्यायालय की तुलना उच्च न्यायालय से नहीं की जा सकती है जिसके पास लेटर्स पेटेंट के आधार पर विशेष शक्तियां हैं। जिला न्यायालय को आगे की अपील पर विचार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसके पास "कुछ समय के लिए कोई कानून लागू नहीं है" जो ऐसी अपील की अनुमति देता है। किसी भी स्थिति में हमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है जो जिला न्यायालय की एक बड़ी पीठ को उस न्यायालय की एक छोटी पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता हो। फिर भी उच्च न्यायालय में भी, आदेश 43 नियम 1 सि.प्र.सं. के साथ पठित धारा 104 के तहत, एक बड़ी पीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। धारा 104 स्वयं अपील के विभिन्न अधिकारों पर विचार करती है। धारा 104 (1) द्वारा सहेजी गई अपील दायर की जा सकती है। जिन लोगों को बचाया नहीं गया है, उन्हें धारा 104 (2) द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। हम ऐसी स्थिति में कुछ भी विसंगति नहीं देखते हैं। नतीजतन, हमारे सामने भेदभाव वाली याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

26. श्री सिब्बल ने आगे कहा कि कमल कुमार दत्ता के मामले में निर्णय उच्चतम न्यायालय के इस निष्कर्ष पर आधारित था कि कंपनी लॉ बोर्ड के पास न्यायिक संस्थान के सभी गुण हैं, हालांकि यह न्यायालय नहीं है। श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि "न्यायालय प्रतीकात्मक" परीक्षण है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने संहिता की धारा 2(14) पर जोर दिया, तथा उसमें प्रयुक्त होने वाले "आदेश" शब्द को परिभाषित करते हुए "साधन" शब्द का प्रयोग किया। श्री सिब्बल के अनुसार, चूंकि

संहिता के तहत परिभाषित "आदेश" शब्द केवल सिविल न्यायालय के फैसलों की बात करता है, इसलिए इसके प्रावधानों को एक न्यायाधिकरण या अन्य न्यायिक मंच को शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसमें अदालत के निहितार्थ हो सकते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने धारा 2 (14) पर जोर दिया कोड, "अर्थ" शब्द का उपयोग करते हुए अभिव्यक्ति "आदेश" को उसमें होने के रूप में परिभाषित करता है।

27. शेल कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड बनाम प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के प्रसिद्ध निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। संघीय कराधान आयुक्त, जहाँ लॉर्ड सेंकी एल. सी. ने संक्षिप्त रूप से उस अंतर को समझाया था जिसे न्यायालय और न्यायाधिकरण के बीच मौजूद होने के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। जिन सिद्धांतों को इस विषय पर भारत में न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत किए गए विभिन्न पूर्व निर्णय में अपनाया और पुष्टि की गई है, उन्हें नीचे निकाला गया है:-

*"अधिकारी स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि न्यायालय के कई जालों के साथ न्यायालय हैं जो, फिर भी, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के सख्त अर्थ में न्यायालय नहीं हैं।*

*वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि आयुक्त ने स्वयं कोई न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। यह कहा गया था कि मूल्यांकन के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग समीक्षा बोर्ड के साथ शुरू हुआ, जो वास्तव में एक न्यायालय था।*



इस संबंध में इस विषय पर कुछ नकारात्मक प्रस्तावों को गिनना उपयोगी हो सकता है: 1. एक न्यायाधिकरण आवश्यक रूप से इस सख्त अर्थ में एक न्यायालय नहीं है क्योंकि यह एक अंतिम निर्णय देता है। 2. न ही इसलिए कि यह शपथ पर गवाहों को सुनता है। 3. न ही इसलिए कि दो या दो से अधिक प्रतिद्वंद्वी पक्ष इसके सामने उपस्थित होते हैं जिनके बीच उसे निर्णय लेना होता है। 4. न ही इसलिए कि यह ऐसे निर्णय देता है जो विषयों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। 5. न ही इसलिए कि किसी न्यायालय में अपील की जाती है। 6. न ही इसलिए कि यह एक निकाय है जिसमें एक पदार्थ को दूसरे निकाय द्वारा संदर्भित किया जाता है। रेक्स बनाम बिजली आयुक्त देखें।

28. श्री सिब्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि यदि ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड की शेल कंपनी में उल्लिखित परीक्षणों को लागू किया जाना है, तो यह स्पष्ट होगा कि पंजीयक के अधीन कार्य करते समय 1999 व्यापार चिन्ह अधिनियम को संभवतः न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि केवल इसलिए कि 1999 का व्यापार चिन्ह अधिनियम पंजीयक को कुछ शक्तियों को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है जो अन्यथा संहिता के तहत सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, जो इसे सिविल न्यायालय के समकक्ष नहीं बन पाएगा।

29. हमारा ध्यान अतिरिक्त रूप से परमजीत सिंह पाथेजा बनाम आई.सी.डी. एस. लिमिटेड के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें विचार के लिए यह

प्रश्न उठा था कि क्या मध्यस्थता पुरस्कार प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 के प्रयोजनों के लिए एक डिक्री के बराबर होगा। शब्द के "डिक्री" और "आदेश" के संबंध में संहिता में परिभाषित शब्दों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने परमजीत सिंह पाथेजा के मामले में इस प्रकार टिप्पणी की:-

"20. धारा 2(2) और 2(14) सि.प्र.सं. परिभाषित करती है कि "डिक्री" और "आदेश" का क्या अर्थ है। यह देखने के लिए कि क्या कोई निर्णय या निर्धारण एक डिक्री या आदेश है, यह आवश्यक रूप से परिभाषा की भाषा में आना चाहिए। धारा 2 (2) सि.प्र.सं. "डिक्री" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है

"किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, जो जहाँ तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने के संबंध में है, वाद में विवादग्रस्त सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्णायक मुकदमा से निर्धारित करती है और प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। यह माना जाएगा कि इसमें धारा 144 के भीतर किसी शिकायत की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा।

(क) कोई निर्णय जिसमें से कोई अपील किसी आदेश की अपील के रूप में होती है, या

(ख) चूक के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश।

स्पष्टीकरण:- एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से मुकदमा से पहले आगे की कार्यवाही की जानी होती है। यह अंतिम है जब इस तरह न्यायनिर्णयन मुकदमे का पूरी तरह से निपटारा मुकदमा है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकता है।

21. "न्यायालय", "न्यायनिर्णयन" और "वाद" शब्द निर्णायक मुकदमा से दर्शाते हैं कि केवल एक न्यायालय एक डिक्री पारित कर सकती है और वह भी केवल एक वादी द्वारा शुरू किए गए मुकदमे में और अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले द्वारा विवाद के निर्णय के बाद ही ऐसा कर सकती है। यह स्पष्ट है कि एक मध्यस्थ एक न्यायालय नहीं है, एक मध्यस्थता एक निर्णय नहीं है और इसलिए, पंचाट एक डिक्री नहीं है।

22. धारा 2 (14) "आदेश" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है

" सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो एक डिक्री नहीं है।

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

25. रामसाई बनाम जॉयलाल [ए.आई.आर. 1928 कैल 840:32 सी. डब्ल्यू. एन. 608] कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया (एयर पृ. 840)

(क) प्रेसीडेंसी नगर दिवालियापन अधिनियम, धारा 9 (ड.)- पंचाट के निष्पादन में संलिप्तता किसी डिक्री के निष्पादन में से एक नहीं है।

किसी पंचाट के निष्पादन में संलग्नक दिवालिया होने का कार्य बनाने के उद्देश्य से धारा 9 (ड.) के अर्थ के भीतर एक डिक्री के निष्पादन में संलग्नक नहीं है: पुनः दिवालियापन सूचना [(1907) के.बी 478:76 एलजे के. बी. 171:96 एल. टी. 131 (सी. ए.)], रेफ.

(ख) मध्यस्थता अधिनियम, धारा 15-पंचाट एक पंचाट केवल उस पंचाट को लागू करने के उद्देश्य से जारी किया गया आदेश है।"

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

28. इस न्यायालय के निर्णयों से यह तय होता है कि "मानो" शब्द वास्तव में दो चीजों के बीच अंतर दिखाते हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग सीमित उद्देश्य के लिए किया जाता है। वे आगे बताते हैं कि एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था।

29. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36, जो 1899 के अधिनियम की धारा 15 के समान है, नीचे दी गई है:

"36. प्रवर्तन- जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता पंचाट को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, या ऐसा आवेदन किया गया है, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया है, पंचाट को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री थी।"

(जोर दिया गया)

वास्तव में, धारा 36, 1899 अधिनियम की धारा 15 से आगे जाती है और संदेह से परे यह स्पष्ट करती है कि प्रवर्तनीयता केवल सि.प्र.सं. के तहत होनी चाहिए। यह किसी भी तर्क को खारिज करता है कि डिक्री के रूप में प्रवर्तनीयता किसी अन्य कानून के तहत मांगी जा सकती है या दिवालियापन कार्यवाही शुरू करना सि.प्र.सं. के तहत डिक्री को लागू करने का एक तरीका है। इसलिए प्रत्यर्थियों का तर्क कि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत दिए गए पंचाट को यदि अपेक्षित अवधि के भीतर चुनौती नहीं दी जाती है, तो यह धारा 35 के तहत प्रदान की गई अंतिम और बाध्यकारी हो जाती है और इसे डिक्री के रूप में लागू किया जा सकता है क्योंकि यह धारा 36 के तहत प्रदान की गई बाध्यकारी और निर्णायक है और पंचाट

और डिक्री के बीच कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है।

30. जहाँ तक, विभिन्न निर्णयों के रूप में जो प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से उद्धृत किए गए थे श्री सिब्बल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि उनमें से अधिकांश निर्णय और उनमें प्रतिपादित सिद्धांत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सराहे जाने योग्य हैं कि वे या तो दीवानी न्यायालय या न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें न्यायालय माना गया था। यह भी बताया गया कि वास्तव में उनमें से कुछ निर्णय न्यायाधिकरण को न्यायालय का दर्जा प्रदान करने वाले एक प्रावधान की पृष्ठभूमि में बताये गए थे।

31. जिन प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया था, उन पर ध्यान देने के बाद, हम पाते हैं कि जो प्रमुख मुद्दा निर्धारण के लिए आता है वह यह होगा कि क्या संहिता की धारा 100-क, यह निर्धारित करते हुए कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए मूल या अपीलिय डिक्री या आदेश से आगे कोई अपील नहीं होगी, उन अपीलों तक भी विस्तारित होगी जिन्हें पेटेंट पत्र के संदर्भ में प्राथमिकता दी जा सकती है और जो 1999 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 91 के संदर्भ में न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश से संबंधित हैं। निर्विवाद रूप से, 1999 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 91, व्यथित व्यक्ति को व्यापार चिह्न पंजीयक के किसी भी आदेश या निर्णय के खिलाफ

अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करती है। 1999 का व्यापार चिन्ह अधिनियम वर्तमान में भी धारा 109(5) के समरूप प्रावधान नहीं रखता है, जैसा कि 1958 के व्यापार चिन्ह अधिनियम में था। इस प्रकार अपील की स्थिति 1940 के टीएम अधिनियम में मौजूद स्थिति पर वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार, जहाँ तक व्यापार चिन्ह के विषय का संबंध है, एकमात्र अवधि जहाँ विशेष रूप से दूसरी अपील का प्रावधान किया गया था, वह 1958 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत थी। वास्तव में विधायी बदलाव का यह पहलू वह था जिसे श्री आनंद ने अपने इस निवेदन के समर्थन में उजागर किया कि आगे कोई अपील अब परिकल्पित नहीं है। हालाँकि, हम इस निर्णय के उचित चरण में उस निवेदन पर विचार करेंगे।

32. वर्तमान अपीलों पर लागू लेटर्स पेटेंट प्रावधान अपने विघटित रूप में निम्नानुसार होगा:-

*"10. और हम आगे आदेश देते हैं कि फैसले के खिलाफ लाहौर में उक्त उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।*

*(क) (किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में की गई डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित निर्णय नहीं होने के कारण, उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन,*

*ख) और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किया गया आदेश नहीं होने के कारण,*

- ग) और भारत सरकार अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों के तहत या आपराधिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित या बनाया गया दंड या आदेश नहीं है)
- घ) उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का या
- ड) भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के अनुसार किसी भी खंड पीठ का न्यायाधीश,
- च) और इसमें पूर्व में उपबंधित किसी बात के होते हुए भी, उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील उक्त उच्च न्यायालय में की जा सकेगी
- (i) उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश या
- (ii) भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के अनुसार किसी भी खंड पीठ का एक न्यायाधीश,
- (iii) फरवरी के पहले दिन या उसके बाद, एक हजार नौ सौ उनतीस को एक डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में बनाया गया।
- (iv) किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किया गया, जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन हो।
- (v) जहाँ निर्णय देने वाला न्यायाधीश घोषणा करता है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है,
- छ) लेकिन यह कि उक्त उच्च न्यायालय या ऐसे खंड न्याय पीठ के न्यायाधीशों के अन्य निर्णयों से अपील करने का अधिकार हमारे या उनकी प्रिवी काउंसिल में हमारे उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों के लिए होगा, जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है।”

33. जैसा कि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के पहले भाग को पढ़ने से स्पष्ट होगा, यह इस न्यायालय के समक्ष तीसरी अपील को प्रतिबंधित करता है। इसलिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या संहिता की धारा 100-क की व्याख्या या अर्थ लगाया जा सकता है कि यह दूसरी अपील को भी अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश से इसके बावजूद इस न्यायालय के समक्ष अन्यथा विचारणीय थी उत्पन्न हुआ हो, इसको बाधित करती है ।

34. यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे विचारार्थ उद्धृत किए गए अधिकांश निर्णय तथा जिनमें *कमल कुमार दत्ता* से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, वे कार्यवाही के संदर्भ में दिए गए थे, जो या तो सिविल न्यायालय से उत्पन्न हुए थे या न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से संबंधित थे, जिनके बारे में समझा जाता था कि उनमें न्यायालय के सभी निहितार्थ हैं। *कमल कुमार दत्ता* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा था कि कंपनी लॉ बोर्ड के पास न्यायालय के सभी अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय ने *गंडला पन्नाला* में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को भी मंजूरी दी थी। बाद वाला निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न कार्यवाही से संबंधित था। यह ध्यान देने योग्य है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और विशेष रूप से, इसकी धारा



169, एक डीमिंग प्रावधान के आधार पर घोषणा करती है कि ऐसे न्यायाधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय की तरह व्यवहार करेगा। *गंडला पन्नाला* में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में उस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा दोहराया गया था। हालाँकि, हम पाते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गठित न्यायाधिकरण की स्थिति को *नाहर औद्योगिक उद्यमों* में समझाया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से कहा है कि इस तरह के न्यायाधिकरण को संभवतः सिविल न्यायालय नहीं माना जा सकता है।

35. *केशव पिल्लई* में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 54 को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के खिलाफ अपील की स्थिरता के सवाल पर विचार कर रहा था। भूमि अधिग्रहण अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 54 द्वारा प्रदत्त अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ उपरोक्त अपील को प्राथमिकता दी गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केशव पिल्लई और उस निर्णय में विचार के लिए आने वाली विभिन्न कार्यवाहियां सिविल न्यायालय से उत्पन्न हुई थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि अधिग्रहण

अधिनियम, 1894 की धारा 54 के संदर्भ में लिए गए निर्णयों की प्रशंसा प्रावधान की भाषा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। धारा 54 निम्नलिखित शर्तों में तैयार की गई थी:-

*"धारा 54. न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की अपील-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अधीन, मूल फरमानों से अपीलों पर लागू होती है, और उस समय लागू किसी भी अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, केवल इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में न्यायालय के पंचाट, या पंचाट के किसी भी हिस्से से अपील की जाएगी और ऐसी अपील पर पारित उच्च न्यायालय के किसी भी डिक्री से, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 110 में निहित प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी और आदेश XLV में कहा गया है। (मूल डिक्री से अपीलों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय के पंचाट या पंचाट के किसी भाग से तथा ऐसी अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री से केवल उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकेगी, जैसा कि पूर्वोक्त है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 110 और उसके आदेश XLV में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी।)"*

36. जैसा कि उक्त प्रावधान के पढ़ने से स्पष्ट होगा, इसने सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ आगे की अपील के

लिए मंच के रूप में नामित किया। दूसरा, यह भी और स्पष्ट शब्दों में ऐसी अपील के लिए आम तौर पर अपीलों से संबंधित संहिता के प्रावधानों के अनुसार होने का प्रावधान करता है। तीसरा, प्रावधान का स्पष्ट रूप से एक गैर-बाधा खंड को अपनाकर किसी भी अन्य विशेष कानून की अवहेलना करने का इरादा था।

37. *रउफ अहमद जारू* में, जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील की पृष्ठभूमि में संहिता की धारा 100-क के लागू होने के संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया। यह ध्यान देना उचित हो जाता है कि संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 ने पहली बार में "जिला न्यायालय" के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की परिकल्पना की थी, एक वाक्यांश जिसे संहिता के तहत परिभाषित किया गया था। इस प्रकार उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही निस्संदेह एक सिविल न्यायालय से उत्पन्न हुई होगी।

38. *मोहम्मद सऊद* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहे थे कि क्या एल.पी.ए. संहिता के आदेश XLIII नियम 1 के तहत पहली अपील पर दिए गए फैसले के खिलाफ होगा। इसी तरह, वसंत, *मेट्रो टायर* और *एन.जी. नंदा* में निर्णय पहली बार में सिविल न्यायालय के समक्ष रखी गई कार्यवाही से उत्पन्न हुए।

39. अवतार नारायण बहल में हमारे न्यायालय की पूर्ण पीठ को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत स्थापित कार्यवाही में मूल रूप से जिला न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश और न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तय की गई अपील के संदर्भ में एल. पी. ए. की स्थिरता के सवाल का जवाब देने के लिए फिर से बुलाया गया था। हम इसी तरह ध्यान देते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम अंशुमन शुक्ला, के निर्णय में मध्यमस्थम अधिकारन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों पर आधारित है और जो उक्त अधिनियम की धारा 24 ने एक अनुमानक प्रावधान के आधार पर न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय का दर्जा प्रदान किया। जहाँ तक *डब्ल्यू. एन. अलाला सुंदरम* में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का संबंध है, कार्यवाही तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 के तहत एक मुकदमा पर पारित आदेशों से उत्पन्न हुई, जो आयुक्त द्वारा घोषित किया गया था। उन कार्यवाहियों को सिविल न्यायालय के समक्ष पूर्व उल्लिखित अधिनियम की धारा 70 के संदर्भ में रखा गया था। सतीश चन्द्र सभरवाल और अन्य बनाम राज्य और अन्य<sup>28</sup> मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय, एक ऐसा निर्णय भी था जिसमें एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय से कार्यवाही शुरू हुई थी अन्य जिन्होंने प्रोबेट याचिका को खारिज कर दिया था और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे।

40. इस प्रकार हमारे पास प्राधिकरणों की तीन अलग-अलग और विशिष्ट धाराएँ हैं-

- I. वे मामले जो सीधे संहिता द्वारा शासित मामलों से संबंधित थे;
- II. वे कार्यवाहियाँ जो मूल रूप से सिविल न्यायालय के समक्ष शुरू की गई थीं;
- III. तीसरा, वे जो न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा प्रदान की गई संहिता की धारा 100-क की प्रयोज्यता के प्रश्न से निपटते हैं, जिन्हें एक वैधानिक प्रावधान के आधार पर सिविल न्यायालयों के रूप में नियुक्त किया गया था या जिन्हें सिविल न्यायालय के एकप्रतीकात्मकके रूप में मान्यता दी गई थी।

41. तालिका (ओं) द्वारा निर्भर निर्णयों को अलग करती है प्रत्यर्थी संख्या 1 और मानित प्रावधानों की तुलना अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत ध्यान दें गई टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत ध्यान दें गई हैं - यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

क्रम सं.	मामला	लागू अधिनियम	न्यायालय			
			न्यायालय 1	न्यायालय 2	न्यायालय 3	न्यायालय 4
1.	कमल कुमार दत्ता एवं अन्य बनाम वी. रूबी जनरल हॉस्पिटल	कंपनी अधिनियम, 2013	कंपनी लॉ बोर्ड ("सीएलबी") सिविल न्यायालय धारा 424	उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश (सिविल न्यायालय)	सर्वोच्च न्यायालय (सिविल न्यायालय)	मान्य/नहीं

	लिमिटेड और अन्य [(2006) 7 एससीसी 613]		धारणा उपबंध		य) ने माना कि उच्च न्यायाल य की खंड न्याय पीठ के लिए एलपीए कायम रखने योग्य नहीं होगा। सीएलबी में सिविल न्यायाल य की सभी सुविधाएं मौजूद हैं	
2.	गंदला पन्नैया	मोटर वाहन	मोटर दुर्घटना	उच्च न्यायालय के एकल	उच्च न्यायाल	मान्य /नहीं

	भुलक्ष्मी बनाम प्रबंध निदेशक, एपीएसआरटी सी [2003 एससीसी ऑनलाइन एपी 525]	अधिनियम , 1988	दावा अधिकरण (जिला न्यायाधीश ) सिविल न्यायालय का धारणा उपबंध - धारा 165(3)(ख ) और 169	न्यायाधीश(सि विल न्यायालय)	य की पूर्ण न्याय पीठ (सिविल न्यायाल य )	
3.	मो. सौद और अन्य. वी. डॉ. (एमएजे) शेख महफूज एवं अन्य (2010) 13 एससीसी 517	मान्य/न हीं	अपर जिला न्यायाधीश (सिविल न्यायालय )	उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश (सिविल न्यायालय)	उच्च न्यायाल य की खंड न्याय पीठ (सिविल न्यायाल य )	सर्वोच्च न्यायालय (सिविल न्यायालय )
4.	मेट्रो टायर्स लिमिटेड और अन्य बनाम सतपाल सिंह भंडारी और	मान्य/न हीं	अपर जिला न्यायाधीश (सिविल न्यायालय )	उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश (सिविल न्यायालय)	उच्च न्यायाल य की खंड न्याय पीठ	मान्य /नहीं

	अन्य [(2011) 183 डीएलटी311 (डीबी)]				(सिविल न्यायाल य )	
5.	मध्य प्रदेश राज्य बनाम अन्शुर्नन शुक्ला [(2008) 7 एससीसी 487]	मध्य प्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम , 1983	मध्यस्थता न्यायाधिक रण को सिविल न्यायालय माना जाता है - धारा 24	उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ (सिविल न्यायालय )	उच्च न्यायाल य की पूर्ण न्याय पीठ (सिविल न्यायाल य )	सर्वोच्च न्यायालय (सिविल न्यायालय ) ने माना कि अपील उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सुनवाई योग्य नहीं है।
6.	डब्ल्यू.एन. अलाला सुंदरम बनाम आयुक्त, मानव संसाधन एवं सी.ई. प्रशासन	तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम , 1959	विचारण न्यायालय (सिविल न्यायालय )	उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश (सिविल न्यायालय)	उच्च न्यायाल य की खंड न्याय पीठ (सिविल न्यायाल य)	



विभाग, 2007 एससीसी ऑनलाइन मैड 505					
---	--	--	--	--	--

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (प्रत्यर्थियों द्वारा उद्धृत) निर्णय: गैंडला पन्नाला भुलक्ष्मी बनाम प्रबंध निदेशक,	कंपनी अधिनियम, 2013 (प्रत्यर्थियों के फैसले में उद्धृत: कमल कुमार) दत्ता एवं अन्य. वी. रूबी जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड एवं अन्य, 2006	एम.पी.मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (प्रत्यर्थियों द्वारा उद्धृत) निर्णय: मध्य प्रदेश राज्य बनाम अन्शुर्नन शुक्ला, 2008) 7 एससीसी 487)	आंध्र भूमि हडपना (निषेध) अधिनियम, 1982 (अपीलकर्ता में उद्धृत निर्णय: नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, 2009 8 एससीसी 646)	अधिकरण सुधार अधिनियम से पहले व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999, 2021	व्यापार चिन्ह अधिनिय म, 1999
--	--	--	---	--	---------------------------------------

2003 एससीसी ऑनलाइन एपी 525)	7 एससीसी 613)				
धारा 169. प्रक्रिया और शक्तियाँ का दावा अधिकरण (1) ... (2) दाव अधिकरण के पास शपथ पर साक्ष्य लेने और गवाहों की	धारा 424. अधिकरण और अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया (1) ... (2) अधिकरण और अपीलीय अधिकरण के पास, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों	धारा 24. न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध के संबंध में अधिकरण आदि का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। (1) न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के प्रयोजनों के	धारा 2. परिभाषाएँ (i-ख ) "विशेष अधिकरण " का अर्थ है संबंधित क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले जिला न्यायाधीश का न्यायालय और इसमें मुख्य न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद	अधिकरण सुधार अधिनियम एक्ट, 2021 के बाद निरस्त। धारा 2(न्यायधीश )। "अधिकरण " का अर्थ है पंजीयक या, जैसा भी मामला हो,	धारा 127 पंजीयक की शक्तियाँ पंजीयक के समक्ष इस अधिनिय म के तहत सभी कार्यवाहि यों में, -

उपस्थिति को लागू करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की खोज और उत्पादन के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।	के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5) के तहत एक सिविल न्यायालय में निहित हैं। 1908) निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे की सुनवाई करते समय,	लिए, इसके समक्ष किसी भी संदर्भ या कानूनी कार्यवाही के संबंध में अधिकरण को सिविल न्यायालय माना जाएगा और इससे पहले किसी भी संदर्भ या कानूनी कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। जहां तक यह ऐसे संदर्भ या कानूनी	सम्मिलित ।] धारा 9 . विशेष न्यायालय के पास सिविल न्यायालय और सत्र न्यायालय की शक्तियां होंगी सत्र इसमें स्पष्ट रूप से दिए गए अनुसार सेव करें अधिनियम,सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, आंध्र प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1972 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के	अपीलीय बोर्ड, जिसके समक्ष संबंधित कार्यवाही धारा 92 लंबित है। अपीलीय बोर्ड की प्रक्रिया और शक्तियां(1) .. (2) अपीलीय बोर्ड के पास, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों	(क) पंजीयक के पास साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, गवाहों की उपस्थिति को लागू करने, दस्तावेजों की खोज और उत्पादन
---	---	--	---	---	---

और ऐसे के लिए अन्य उद्देश्य जो निर्धारित किये जा सकते हैं; और अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय	अर्थात्: - (ए) से (एच) (3) ... (4) अधिकरण या अपीलीय अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही को के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा धारा 193 और 228, और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा	- कार्यवाही से जुड़ा है	प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, कार्यवाही पर लागू होंगे। विशेष न्यायालय के समक्ष और उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय को एक सिविल न्यायालय, या जैसा भी मामला हो, एक सत्र न्यायालय माना	के निर्वहन के उद्देश्य से, वही शक्तियां होंगी जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय में निहित हैं। निम्नलिखित	के लिए बाध्य करने और जारी करने के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। गवाहों की जांच के लिए
---	---	-------------------------------	---	--	--

XXVI के सभी उद्देश्यों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।	196 के प्रयोजनों के लिए, और अधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को धारा के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा 195 और अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का XXVII		जाएगा और की सारी शक्तियाँ हैं सिविल न्यायालय और सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाएगा।	मामले, अर्थात्- (क) से (घ) (3) अपीलीय बोर्ड के समक्ष कोई भी कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में और भारतीय धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी	आयोग; (ख) पंजीयक , धारा 157 के तहत इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, लागत के संबंध में ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह
---	--	--	--	---	---

				जाएगी। दंड संहिता, और अपीलीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के सभी उद्देश्यों के लिए बोर्ड को एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।	उचित समझता है, और ऐसा कोई भी आदेश सिविल न्यायाल य के डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य होगा: बशर्ते कि पंजीयक प्रमाणन व्यापार
--	--	--	--	---	---

					चिह्न के मालिक द्वारा माल या प्रावधान को प्रमाणित करने से इनकार करने के खिलाफ अपील करने पर किसी भी पक्ष को या उसके खिलाफ जुर्माना
--	--	--	--	--	--

					देने की कोई शक्ति नहीं है। सेवाएँ या करने के लिए चिह्न के उपयोग को अधिकृत करें;
--	--	--	--	--	--

42. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के बाद, हम उठाई गई आपत्ति पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे विचारार्थ प्रस्तुत की गई प्रारंभिक आपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले, खंड 10 के प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें न्यायालय की पेटेंट शक्ति सम्मिलित है। जैसा कि खंड 10 के प्रथम भाग को पढ़ने से स्पष्ट होगा, एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध



अपील की जा सकती है, बशर्ते कि वह उच्च न्यायालय के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित किया गया निर्णय न हो। इस प्रकार, उक्त प्रावधान तीसरी अपील पर रोक लगाता है और ऐसी स्थिति में लागू होता है, जहां एकल न्यायाधीश ने किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित डिक्री या आदेश के संबंध में प्रस्तुत की गई दूसरी अपील पर सुनवाई की हो और उस पर निर्णय दिया हो। खंड 10 का अंतिम भाग भी इस बारे में है - उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में। खंड 10 का उत्तरार्द्ध भाग एक वादी को उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन आने वाले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 फरवरी 1929 के बाद एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील स्थापित करने में सक्षम बनाता है और जिसने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक डिक्री या आदेश पारित किया था। खंड 10 के बाद के भाग के संदर्भ में अपील होगी बशर्ते एकल न्यायाधीश ने अपील के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया हो।

43. हम यह भी देखते हैं कि धारा 100-क, जब इसे मूल रूप से वर्ष 1976 में संहिता में 1976 के 104 के सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम द्वारा पेश

किया गया था, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय डिक्री या आदेश से आगे की अपील लेने पर रोक लगाती है। जैसा कि मूल रूप से प्रस्तुत किया गया प्रावधान, इस प्रकार एकल न्यायाधीश के फैसले से आगे की अपील करने पर रोक लगाता है बशर्ते कि उक्त न्यायाधीश एक अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई कर रहा हो। इस प्रकार यह उन स्थितियों तक ही सीमित रहा जहां उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश दूसरी अपील पर विचार कर रहा था। वर्ष 1999 में अपने संशोधन पर, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) ने आगे की अपील के प्रतिबंध को बढ़ा दिया, भले ही एकल न्यायाधीश ने मूल आदेश से उसी पर विचार किया हो। यद्यपि धारा 100-क, जिसे वर्ष 1999 में पुनर्गठित किया गया था, उन मामलों में भी प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया था जहां उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया हो सकता है, लेकिन वर्ष 2002 में इसे हटा दिया गया। किसी भी मामले में, उक्त विधायी संशोधन की बहुत कम प्रासंगिकता है जहाँ तक जो मुद्दा इन अपीलों में उठाया गया है।

44. धारा 100-क, जैसा कि अब है, स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि पत्र पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी उस समय के लिए कानून या किसी अन्य कानून का बल रखने वाला साधन जहाँ उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश किसी मामले का निर्णय करता है अपीलीय शक्तियों का प्रयोग और जो

मूल से उत्पन्न होती हैं या अपीलीय डिक्री या आदेश, आगे कोई अपील नहीं होगी। इस प्रकार संहिता की धारा 100-क के वाचन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार अपील बार में दूसरी अंतर-न्यायालयीय के तौर पर शामिल की जायेंगी ।

45. अपील के प्रावधान पर ध्यान देना भी लाभदायक होगा क्योंकि विभिन्न समय बिंदुओं पर प्रचलित व्यापार चिह्न संविदा में निहित रहता है । 1940 व्यापार चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 76,109 और 91 और जैसा कि वर्तमान में अधिनियम है, नीचे एक सारणी में पुनः प्रस्तुत किया गया है रूप:-

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1940	व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
76. अपील.- इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधन के सिवाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पंजीयक [* * *] के किसी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील, केन्द्रीय	109. अपील - (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए या जारी किए गए किसी निर्णय, आदेश या निदेश के विरुद्ध अथवा ऐसे किसी निर्णय, आदेश या निदेश को प्रभावी करने के प्रयोजन	91. [उच्च न्यायालय] में अपील - (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पंजीयक के किसी आदेश या निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीन महीने के भीतर उच्च

<p>सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय में की जा सकेगी: परन्तु यदि प्रश्नगत व्यापार चिन्ह से संबंधित कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में लंबित है, तो अपील, यथास्थिति, उच्च न्यायालय में या उस अधिकारिता के भीतर उस जिला न्यायालय में की जाएगी, जो स्थित है।</p> <p>(2) धारा 13 या धारा 14 या धारा 15 के अधीन</p>	<p>के लिए पंजीयक के किसी कार्य या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। (2) उप-धारा (1) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, इस अधिनियम या नियमों के तहत रजिस्ट्रार के किसी भी आदेश या निर्णय से निर्धारित अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी जिसके तहत बनाया गया। (3) ऐसी प्रत्येक अपील लिखित रूप में याचिका</p>	<p>न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिस तारीख को वह आदेश या निर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, अपील करने वाले ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाता है। (2) कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी यदि वह उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् की जाती है: परंतु कोई अपील उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी स्वीकार की जा सकेगी, यदि अपीलकर्ता उच्च</p>
--	--	---

<p>पंजीयक के निर्णय के विरुद्ध पंजीकरण के लिए आवेदक द्वारा की गई अपील में, न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के बिना, पंजीयक या अपील का विरोध करने वाले किसी पक्षकार को उक्त निर्णय में अभिलिखित या पंजीयक के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार द्वारा दिए गए आधारों के अलावा अन्य आधार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होगी; और जहां ऐसे कोई अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां पंजीकरण के</p>	<p>द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रारूप में होगी और इसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं। (4) ऐसी प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी: बशर्ते कि ऐसा कोई भी न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे, कार्यवाही के किसी भी चरण में अपील को उच्च न्यायालय की खंडपीठ को संदर्भित कर सकता है। (5) जहां किसी अपील की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती</p>	<p>न्यायालय को यह समाधान कर दे कि उसके पास विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था। (3) [उच्च न्यायालय] में अपील निर्धारित प्रपत्र में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी और इसके साथ उस आदेश या निर्णय की एक प्रति होगी जिसके खिलाफ अपील की गई है और ऐसा शुल्क होगा जो निर्धारित की जा सकती हो।</p>
---	--	---

<p>लिए आवेदक, निर्धारित तरीके से नोटिस देकर, पंजीयक या उसके आवेदन का विरोध करने वाले पक्षकारों की लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हुए बिना अपना आवेदन वापस ले सकता है।</p> <p>(3) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर लागू</p>	<p>है, तो आगे की अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी।</p> <p>(6) इस धारा के तहत किसी अपील का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय के पास कोई भी वैसा आदेश देने की शक्ति होगी जो पंजीयक इस अधिनियम के तहत कर सकता है।</p> <p>(7) धारा 17 या धारा 18 या धारा 21 के तहत पंजीयक के फैसले के खिलाफ पंजीकरण के लिए आवेदक द्वारा अपील में, यह पंजीयक या विरोध करने वाले किसी</p>	
---	---	--

होंगे।	<p>भी पक्ष के लिए, न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के अलावा खुला नहीं होगा। जैसा भी मामला हो, और जहां कोई अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किया जाता है, वहां पंजीकरण के लिए आवेदक निर्धारित तरीके से नोटिस देकर पंजीयक या उसके आवेदन का विरोध करने वाले पक्षों की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हुए बिना अपना आवेदन वापस ले सकता है।</p> <p>(8) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके</p>	
--------	--	--

	<p>तहत बनाए गए नियमों के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 में से 5) के प्रावधान 1908), इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर लागू होगा।</p>	
--	---	--

46. जैसा कि उन वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट होगा, एकमात्र वह समय जब दूसरी अपील के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था, वह तब था जब 1958 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार था और धारा 109(5) के आधार पर ऐसी अपील की परिकल्पना की गई थी। निर्विवाद रूप से, धारा 109(5) जैसा कोई प्रावधान न तो 1940 के व्यापार चिन्ह अधिनियम में मौजूद था और न ही 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम में कोई समान प्रावधान दिखाई देता है। महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि, दोनों अपीलीय प्रावधान जो उनमें मौजूद थे 1940 व्यापार चिन्ह अधिनियम के साथ-साथ 1958 व्यापार चिन्ह अधिनियम विशेष रूप से प्रदान किया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उन प्रावधानों के संदर्भ में दायर



अपीलें संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी। यह संबंधित कानूनों की धारा 76(3) और धारा 109(8) से स्पष्ट है। उन उप-धाराओं में स्पष्ट शब्दों में प्रावधान किया गया है कि संहिता के प्रावधान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर लागू होंगे। हालाँकि, 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 91 में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है। यह हमें इस मुख्य प्रश्न पर ले जाता है कि क्या संहिता की धारा 100-क को अपील के लेटर्स पेटेंट प्रावधान को हटाने के रूप में पढ़ा या समझा जा सकता है और जो वर्तमान में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एकल न्यायाधीश के निर्णय के बावजूद हमारे न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील की परिकल्पना करता है। अपीलों के पेटेंट प्रावधान और जो वर्तमान में एक परिकल्पना करता है, एकल न्यायाधीश के निर्णय के होने के बावजूद अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हमारे न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ के समक्ष अपील की जा रही है।

47. हम देखते हैं कि वर्ष 1953 में जब नेशनल सेविंग थ्रेड कं. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, तब यह सवाल उठा था कि क्या बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील तब तक कायम रह सकती है, जब तक कि 1940 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 में इसके विपरीत कुछ भी शामिल न हो। उस कानून में धारा 76 के अनुसार धारा 109(5) जैसा कोई प्रावधान नहीं था, जो 1958 के

व्यापार चिन्ह अधिनियम का हिस्सा था। इसके बावजूद, 1940 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 में इस संबंध में चुप्पी के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: - धारा 76, जैसा कि उस अधिनियम में मौजूद थी, में धारा 109 (5) के समान कोई प्रावधान शामिल नहीं था, जो 1958 के व्यापार चिन्ह अधिनियम का हिस्सा था। इसके बावजूद, 1940 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 इस संबंध में मौन है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निम्नलिखित टिप्पणी की है -

"6. अपीलकर्ताओं ने व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानों द्वारा अनुमत बॉम्बे उच्च न्यायालय में पंजीयक के आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी। न्यायाधीश शाह ने अपील को स्वीकार कर लिया, पंजीयक के आदेश को दरकिनार कर दिया और पंजीयक को अपीलार्थियों के चिह्न को व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश शाह के फैसले से, बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा एक अपील की गई थी। अपील को स्वीकार कर लिया गया और कुलसचिव के आदेश को पूरे खर्च के साथ बहाल कर दिया गया। इसलिए यह अपील की गई है।

\*\*\*\*                      \*\*\*\*                      \*\*\*\*

9. व्यापार चिन्ह अधिनियम उच्च न्यायालय में उस अपील के भविष्य के संचालन या करियर के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान या निर्धारित नहीं करता है, वास्तव में अधिनियम की धारा 77 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय अगर चाहे तो मामले में नियम बना सकता है। जाहिर है कि अपील उच्च न्यायालय में पहुँचने के बाद इसका निर्धारण उस न्यायालय के व्यवहार के नियमों

और प्रक्रिया के अनुसार और उस चार्टर के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसके तहत उस न्यायालय का गठन किया गया है और जो उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की विधि और तरीके के संबंध में उसे शक्ति प्रदान करता है। नियम अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई अधिनियम निर्देश देता है कि एक अपील पहले से ही स्थापित न्यायालय में होगी, तो उस अपील को उस न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इस नियम को नेशनल टेलीफोन कंपनी में विस्काउंट हाल्डेन, एल. सी. द्वारा बहुत संक्षिप्त रूप से कहा गया था। लिमिटेड वी.पोस्टमास्टर जनरल [नेशनल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड बनाम.पोस्टमास्टर जनरल, 1913 एसी 546 (एचएल)], इन शब्दों में:(ए. सी. पी. 552)

".....जहां कोई कानूनी अधिकार विवाद में है और देश की सामान्य न्यायालय ऐसे विवाद पर विचार कर रही हैं, वहां न्यायालयों में उस पर लागू प्रक्रिया के सामान्य नियमों द्वारा शासित होती हैं और यदि ऐसे नियमों द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो अपील की जा सकती है, भले ही दावा किया गया कानूनी अधिकार किसी विशेष कानून के तहत उत्पन्न हुआ हो, जो अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है..."।

*अडैकप्पा चेट्टियार बनाम चंद्रशेखर थेवर [अडैकप्पा चेट्टियार बनाम चंद्रशेखर थेवर, (1946-47) 74 आई.ए 264 में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया था:1947 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 53] जिसमें कहा गया था:(आई.ए.पृ. 271)*

" ..... जहां कोई वैधानिक अधिकार विवाद में है और देश के सामान्य न्यायालयों को ऐसे विवाद का सामना करना पड़ता है, वहां न्यायालय उस पर लागू प्रक्रिया के सामान्य

नियमों द्वारा शासित होती हैं और एक अपील होती है, यदि ऐसे नियमों द्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके बावजूद कि दावा किया गया कानूनी अधिकार एक विशेष अधिनियम के तहत उत्पन्न होता है जो शर्तों में अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

10. फिर से, *सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल बनाम चेलिकनी रामा राव [सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल बनाम चेलिकनी रामा राव, (1915-16) 43 आई ए 192 : आई एल आर (1916) 39 मद्रास 617 : 1916 एस सी सी ऑनलाइन पी सी 42]* में, मद्रास वन अधिनियम के तहत मामले से निपटते समय, उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार अवलोकन किया: (आई ए पृष्ठ 197)

" ..... अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि भारत में अदालतों में या अपील के माध्यम से आगे की सभी कार्यवाहियां अक्षम थीं, जिन्हें अभी-अभी उद्धृत अधिनियम की शर्तों द्वारा बाहर रखा गया था। उनके लॉर्डशिप्स की राय में यह आपत्ति अच्छी तरह से आधारित नहीं है। उनका विचार है कि जब इस पात्र के ऊपर कार्यवाही जिला न्यायालय तक पहुंचती है, तो उस न्यायालय को देश के सामान्य न्यायालयों में से एक के रूप में अपील की जाती है, जिसकी प्रक्रिया, आदेश और फरमान सिविल प्रक्रिया संहिता के सामान्य नियम द्वारा लागू होते हैं।

यद्यपि उपरोक्त नियम निर्धारित करने वाले मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के समान बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसमें प्रतिपादित सिद्धांत सामान्य अनुप्रयोग में से एक है और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त अनुप्रयोग है। व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 उच्च

न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है और इसके बारे में और कुछ नहीं कहती। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय को धारा 76 द्वारा प्रदत्त अपीलीय अधिकार क्षेत्र के रूप में अभिगृहीत किया जा रहा है, उसे उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उसी तरह करना होगा जैसे वह अपनी अन्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और जब ऐसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो उसका निर्णय बन जाता है लेटर पेटेंट के खंड 15 के तहत अपील के अधीन व्यापार चिह्न अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी नहीं है।

48. जैसा कि यहाँ ऊपर निकाले गए अंशों से स्पष्ट होगा, *नेशनल सेविंग थ्रेड कंपनी* ने कहा कि एक बार अपील उच्च न्यायालय में पहुँचने के बाद, उसका मार्ग उस न्यायालय के अभ्यास के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित करना होगा। इस प्रकार *नेशनल सेविंग थ्रेड कंपनी* में सर्वोच्च न्यायालय ने 1940 के व्यापार चिह्न अधिनियम में निहित कुछ भी विपरीत की अनुपस्थिति में लागू होने वाले पत्र पेटेंट प्रावधान के संदर्भ में आगे की अपील करने के लिए एक वादकारी के अधिकार को बरकरार रखा। इस प्रकार उस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक पत्र पेटेंट प्रावधान के संदर्भ में आगे की अपील किसी भी विपरीत प्रावधान या इरादे की अनुपस्थिति में बनाए रखी जा सकती है जो या तो उस अधिनियम में व्यक्त किया गया हो जिससे या तो वे कार्यवाहियां बाहर आती हैं या कोई अन्य सामान्य कानून। हमें निश्चित रूप से इस

बात को ध्यान में रखना होगा कि *नेशनल सेविंग थ्रेड कं.* संहिता की धारा 100-क की शुरुआत से पहले प्रस्तुत की गई थी।

49. सुबल पॉल बनाम मलिना पॉल और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के विचार के लिए एक पत्र पेटेंट अपील की रखरखाव का मुद्दा फिर से उठा। उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सुबल पॉल मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"16. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 में प्रावधान है कि अपील उसमें निर्दिष्ट आदेशों से होगी और संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए आदेशों को छोड़कर, किसी अन्य आदेश से नहीं। इसमें निर्दिष्ट आदेश इस प्रकार हैं:

" (च च) धारा 35-क के तहत एक आदेश;

(च-क) धारा 91 या धारा 92 के तहत आदेश जिसमें धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति का मुकदमा शुरू करने की अनुमति देने से इनकार किया गया हो, जैसा भी मामला हो;

(छ) धारा 95 के तहत एक आदेश;

(ज) इस संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत कोई आदेश जिसमें किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है या उसे सिविल जेल में गिरफ्तार या हिरासत में रखने का निर्देश दिया जाता है, सिवाय इसके कि ऐसी गिरफ्तारी या हिरासत किसी डिक्री के निष्पादन में की जाती है;

(i) नियमों के तहत जरी किया गया कोई आदेश जिससे नियमों द्वारा अपील की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है:

बशर्ते कि खंड (चच) में निर्दिष्ट किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील इस आधार पर नहीं होगी कि कोई आदेश या कम राशि के भुगतान के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था।

17. यह विवादित नहीं है कि अधिनियम की धारा 299 स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है। इसलिए, अपील का अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के तहत प्रदान नहीं किया गया है। लेटर्स पेटेंट की प्रयोज्यता के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में दिए गए विचारों के अंतर को ध्यान में रखते हुए 1908 में उक्त प्रावधानों में "किसी अन्य अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए शब्दों को छोड़कर" शब्द जोड़े गए थे। हुरीश चंद्र चौधरी बनाम काली सुंदरी देवी [आई. एल. आर. (1883) 9 कैल 482 में प्रिवी काउंसिल के फैसलों के बाद कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय:10 आई.ए. 4 (पी. सी.) ने अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 588, जैसा कि तब थी, लेटर्स पेटेंट के खंड 15 की अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनती है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बन्नो बीबी बनाम मेहदी हुसैन [आई. एल. आर. (1889) 11 ऑल 375 (1889) 9 ए. डब्ल्यू. एन. 70] मामले में इसके विपरीत अभिनिर्धारित किया गया। इसलिए इन शब्दों को कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के फैसलों को प्रभावी बनाने के लिए 1908 के अधिनियम में जोड़ा गया था।

18. यदि विधायिका का इरादा यह होता कि धारा 299 के तहत अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होती, तो विधायिका उस भाषा का उपयोग कर सकती थी जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 में किया गया है, जिसमें यह

प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत पारित सभी फरमानों और आदेशों को "उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अपील की जा सकती है"।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

20. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के कारण एक विशेष अधिनियम के तहत अपील का प्रतिबंध बचा लिया जाता है। एक साधारण पठन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 से पता चलेगा कि एक अपील एक अपील योग्य आदेश से होगी और इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए किसी अन्य आदेश के अलावा कोई अन्य आदेश नहीं होगा। संहिता की धारा 104 केवल विशेष अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपीलों को मान्यता देती है। यह इस तरह से अपील का अधिकार नहीं बनाता है। इसलिए, यह किसी भी आगे की अपील पर भी रोक नहीं लगाता है, यदि उसी के लिए किसी अन्य अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है, जो अभी लागू है। जब भी अधिनियम इस तरह के प्रतिबंध का प्रावधान करता है, तो इसे इतना स्पष्ट रूप से कहा जाता है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-क द्वारा दिखाई देगा।

21. यदि अधिनियम के तहत अपील का अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसकी सीमा भी उसमें प्रदान की जानी चाहिए। लेटर्स पेटेंट के तहत प्रदान किया गया अपील का अधिकार प्रतिबंधित नहीं कहा जा सकता। किसी कानून में किसी प्रावधान के अभाव में अपील के अधिकार की सीमा का अनुमान आसानी से नहीं लगाया जा सकता। यह अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि किसी उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को केवल इसलिए बहिष्कृत नहीं माना जाता है क्योंकि अधीनस्थ



न्यायालय अपने विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। जी.पी. सिंह के वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में, कहा गया है:

" उच्च न्यायालयों के अपीलीय और पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र को केवल इसलिए बहिष्कृत नहीं किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय एक विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसका कारण यह है कि जब उस अधिनियम द्वारा शासित मामलों पर एक विशेष अधिनियम द्वारा किसी स्थापित न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है, जैसा कि बिना किसी सीमा के, किसी व्यक्ति के पदनाम से अलग है, तब, उस न्यायालय की प्रक्रिया की सामान्य घटना जिसमें उसके निर्णय के खिलाफ अपील या संशोधन का कोई सामान्य अधिकार शामिल है, वह आकर्षित होती है।

22. लेकिन उपरोक्त नियम में एक अपवाद उन मामलों को लेकर है जहां विशेष अधिनियम एक स्व-निहित संहिता निर्धारित करता है, सामान्य कानून प्रक्रिया की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर रखा जाएगा। (देखें उपाध्याय हरगोविंद देवशंकर बनाम धीरेंद्रसिंह वीरभद्र सिंहजी सोलंकी [(1988) 2 एस. सी. सी. 1 ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 915:(1988) 2 एससीआर 1043]।)

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

37. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि "इस धारा" के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। इससे यह भी पता चलता है कि यदि किसी अन्य कानून के तहत अपील का प्रावधान किया जाता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

50. पी.एस. सतप्पन में उच्चतम न्यायालय के पाँच विद्वान न्यायाधीशों के विचार के लिए एक समान प्रश्न उत्पन्न हुआ। पी.एस. सतप्पन में कार्यवाही, निष्पादन से संबंधित कार्यवाही से निपटने के दौरान सिविल न्यायालय द्वारा पारित कुछ आदेशों से उत्पन्न हुई। संहिता की धारा 104 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:-

"22. इस प्रकार 1996 तक सभी न्यायालयों का सर्वसम्मत दृष्टिकोण यह था कि सि.प्र.सं. की धारा 104 (1) विशेष रूप से पत्र पेटेंट अपीलों को सुरक्षित रखती है और धारा 104 (2) के तहत प्रतिबंध पत्र पेटेंट अपीलों पर लागू नहीं होता है। विचार यह रहा है कि एक पत्र पेटेंट अपील को निहितार्थ से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पत्र पेटेंट के तहत अपील के अधिकार को एक उपयुक्त कानून में एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा छीन लिया जा सकता है। व्यक्त प्रावधान में "लेटर्स पेटेंट" शब्दों का उल्लेख या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि प्रावधान को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे की सभी अपीलें वर्जित हैं तो लेटर पेटेंट अपील भी वर्जित हो जाएगी।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

29. इस प्रकार, न्यायिक राय की सर्वसम्मति यह रही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 (1) स्पष्ट रूप से एक पत्र पेटेंट अपील को बचाती है। इस स्तर पर सि.प्र.सं. की धारा 104 का विश्लेषण करना उचित होगा। धारा 104 सि.प्र.सं. की उप-धारा (1) के तहत गणना किए गए आदेशों से अपील का प्रावधान करती है जो उसमें गणना किए गए आदेशों से अपील पर विचार करती है, साथ ही संहिता के मुख्य भाग में या उस

समय लागू किसी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई अपील भी करती है। अतः उप-धारा (1) तीन प्रकार के आदेशों पर विचार करती है जिनसे अपील की जाती है, अर्थात् -

- (1) उप-धारा (1) में उल्लिखित आदेश,
- (2) संहिता के मुख्य भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई अपीलें, और
- (3) उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा प्रदान की गई अपील।

यह विवादित नहीं है कि उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत प्रदान की गई अपील उस समय लागू कानून द्वारा प्रदान की गई अपील है।

30. इस प्रकार यदि कोई अपील धारा 104(1) द्वारा स्पष्ट रूप से सुरक्षित है, तो उपधारा (2) ऐसी अपील पर लागू नहीं हो सकती। धारा 104 को संपूर्ण रूप में पढ़ें। उप-धारा (1) में बचत खंड की अनदेखी करके केवल उप-धारा (2) को पढ़ने से दोनों उप-धाराओं के बीच टकराव पैदा होगा। समग्र रूप से पढ़ने और व्याख्या के सुस्थापित सिद्धांतों द्वारा यह स्पष्ट है कि उप-धारा (2) केवल उन अपीलों पर लागू हो सकती है जो धारा 104 की उप-धारा (1) द्वारा सहेजी नहीं गई हैं। उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई अंतिमतः केवल धारा 104 के तहत अपील द्वारा पारित आदेशों से जुड़ी है अर्थात् वे आदेश जिनके खिलाफ "कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून" के तहत अपील की अनुमति नहीं है। इस प्रकार धारा 104 (2) एक पत्र पेटेंट अपील पर रोक नहीं लगाएगी। सि.प्र.सं. की धारा 4 को लागू करने के विधायी इरादे और धारा 104 (1) में "कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा" शब्दों को भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के विचारों को प्रभावी बनाने के लिए

किया गया था कि धारा 104 लेटर्स पेटेंट पर रोक नहीं लगाती है। चूंकि "किसी अन्य कानून के तहत अपील जो इस समय लागू है" इनमें निस्संदेह लेटर्स पेटेंट अपील शामिल है, इसलिए ऐसी अपीलें अब विशेष रूप से सुरक्षित हैं। धारा 104 को संपूर्ण रूप से और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 104 को समग्र रूप से और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यदि इरादा उप-धारा (1) में विशेष रूप से सहेजी गई चीजों को बाहर करने का था, तो एक विशिष्ट निष्कासन होना चाहिए। इस प्रकृति का एक सामान्य निष्कासन पर्याप्त नहीं होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक सामान्य निष्कासन कभी भी एक पत्र पेटेंट अपील को नहीं हटाएगा। हालांकि, जब धारा 104 (1) विशेष रूप से एक पत्र पेटेंट अपील को बचाती है तो इस तरह की अपील को बाहर करने का एकमात्र तरीका धारा 104 (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि एक पत्र पेटेंट अपील भी निषिद्ध है। यही कारण है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 निम्नलिखित प्रावधान करती है:

"4. *बचत*.- (1) इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, इस संहिता में कुछ भी अभी लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा, या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) विशेष रूप से तथा उपधारा (1) में निहित प्रस्ताव की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता की कोई भी बात किसी ऐसे उपाय को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो किसी भू-स्वामी या मकान मालिक को कृषि भूमि के किराए की वसूली के

लिए किसी समय लागू कानून के तहत ऐसी भूमि की उपज से प्राप्त हो सकती है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम के शब्दों से एक विशिष्ट निष्कासन स्पष्ट हो सकता है, भले ही लेटर्स पेटेंट का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया गया हो। लेकिन जहां कानून/धारा में ही एक स्पष्ट बचत का प्रावधान है, तो इसके लिए सामान्य शब्दों में इसका प्रभाव यह है कि अपील नहीं होगी "या" आदेश अंतिम होगा "लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे मामलों में यानी जहां जल्दी बचत होती है, वहां जल्दी निष्कासन भी होना चाहिए। धारा 104 की उप-धारा (2) में किसी भी तरह के स्पष्ट निष्कासन का प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में धारा 100-क का उल्लेख किया जा सकता है। वर्तमान धारा 100-क को 2002 में संशोधित किया गया था। इससे पहले 1976 में शुरू की गई धारा 100-क इस प्रकार है:

“100-क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं- किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट या कानून के बल वाले किसी अन्य उपकरण या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां किसी अपीलीय डिक्री या आदेश से कोई अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी और तय की जाती है, ऐसी अपील में ऐसे एकल न्यायाधीश के न्याय, निर्णय या आदेश या ऐसी अपील में पारित किसी डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।”

यहाँ यह ध्यातव्य है कि जब विधायिका ने लेटर्स पेटेंट अपील को बाहर करना चाहा तो उसने ऐसा विशेष तौर पर ऐसा करना पड़ा। धारा 100-क में इस्तेमाल किए गए शब्द अत्यधिक सावधानी के कारण नहीं हैं। 1976 और 2002 के

संशोधन अधिनियमों द्वारा एक विशिष्ट निष्कासन की शक्ति प्रदान की गयी है क्योंकि विधायिका जानता था कि ऐसे शब्दों की अनुपस्थिति में लेटर्स पेटेंट अपील पर रोक नहीं लगेगी। विधायिका को पता है कि उसने धारा 104(1) में बचत खंड को शामिल किया था और धारा 4 सि.प्र.सं. को शामिल किया था। इस प्रकार अब एक विशिष्ट निष्कासन प्रदान किया गया था। 2002 के बाद, धारा 100-क इस प्रकार है: " 100-क. कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं।- किसी भी उच्च न्यायालय के लिए या उस समय लागू कानून के बल वाले किसी भी दस्तावेज में या किसी अन्य कानून में किसी भी लेटर पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की किसी भी अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती है और निर्णय लिया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के फैसले और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ फिर से विधायिका ने एक विशिष्ट बहिष्करण का प्रावधान किया है। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अब धारा 100-क के आधार पर कोई भी लेटर पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी। हालाँकि, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जो कानून प्रबल होगा वह प्रासंगिक समय पर कानून होगा। प्रासंगिक समय पर न तो धारा 100-क और न ही धारा 104 (2) एक पत्र पेटेंट अपील पर रोक लगाती है।

31. उपरोक्त सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, लेटर्स पेटेंट के धारा 15 के तहत अपील उस समय लागू कानून द्वारा प्रदान की गई अपील है। इसलिए, अंतिम धारा 104 की

उप-धारा (2) द्वारा अनुध्यात ऐसी विधि के अधीन पारित अपील से संबद्ध नहीं है।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

33. यह भी तर्क दिया गया कि यदि धारा 104 सि.प्र.सं. की व्याख्या इस तरह की है, तो यह एक विसंगत स्थिति पैदा कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप भेदभाव हो सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के तहत अपील उपलब्ध होगी, जबकि ऐसी अपील उस मामले में उपलब्ध नहीं होगी जहां आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में पारित किया जाता है। साउथ एशिया इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1442 (1965) 2 एस. सी. आर. 756] में इस न्यायालय के समक्ष इसी तरह के तर्क का आग्रह किया गया था, लेकिन इसे निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था:(एस. सी. आर पी.762 सी -जी)

" यह तर्क कि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 और 11 को एक साथ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि खंड 10 का पहला भाग भी केवल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों से अपील से संबंधित है, कोई बल नहीं रखता। जैसा कि हमने पहले बताया है, खंड 11 न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उपयुक्त विधायिका द्वारा उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने पर विचार करता है। "उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय" शब्दों की व्यापकता को कम करने के बजाय, खंड 11 इंगित करता है कि उक्त निर्णय न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को शामिल करता है। यह कुछ हद तक जोर देकर कहा गया है कि यदि

इस निर्माण को स्वीकार कर लिया जाए, तो एक विसंगति होगी, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के संबंध में अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, उस न्यायालय में आगे की अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि उक्त न्यायाधीश यह घोषित न कर दे कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है, जबकि, यदि अपने द्वितीय अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उसने न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील में निर्णय पारित किया है, तो उक्त उच्च न्यायालय में मामले को आगे की अपील पर ले जाने के लिए ऐसी कोई घोषणा आवश्यक नहीं है। यदि विधायिका का अभिव्यक्त इरादा स्पष्ट है, तो उन संभावित कारणों पर अटकलें लगाना जायज नहीं है, जिन्होंने विधायिका को दो प्रकार के मामलों के बीच अंतर करने के लिए प्रेरित किया। यह हो सकता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, विधायिका ने ऐसे मामले में सीमा लगाना उचित समझा जहां तीन न्यायालयों ने निर्णय दिया, जबकि उसने ऐसे मामले में सीमा लगाना उचित नहीं समझा जहां केवल एक न्यायालय ने निर्णय दिया।

34. हम उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय के तर्क से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। यही तर्क इस बात के संबंध में भी लागू होगा कि यदि यह माना जाता है कि धारा 104(2) लेटर्स पेटेंट अपील पर रोक नहीं लगाती है तो एक असामान्य स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि यदि मामला उच्च न्यायालय में आता है तो आगे की अपील की अनुमति होगी लेकिन यदि मामला जिला न्यायालय में जाता है तो आगे की अपील नहीं हो सकती। अपील



एक क़ानून का निर्माण है। यदि कोई क़ानून अपील की अनुमति देता है, तो वह मान्य होगी। यदि कोई क़ानून अपील की अनुमति नहीं देता है, तो वह मान्य नहीं होगी। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संरक्षक और वार्ड अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मामलों में आगे की अपील की अनुमति है जबकि मध्यस्थता अधिनियम के तहत आगे की अपील पर रोक है। इस प्रकार विभिन्न क़ानूनों में अपील के संबंध में अलग-अलग प्रावधान हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। जिला न्यायालय की तुलना उच्च न्यायालय से नहीं की जा सकती, जिसके पास लेटर्स पेटेंट के आधार पर विशेष शक्तियां हैं। जिला न्यायालय को आगे अपील करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास "फिलहाल लागू कोई क़ानून" नहीं है, जो ऐसी अपील की अनुमति देता हो। किसी भी स्थिति में हमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है, जो जिला न्यायालय की बड़ी न्यायपीठ को उस न्यायालय की छोटी न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता हो। फिर भी उच्च न्यायालय में भी, धारा 104 के तहत आदेश 43 नियम 1 सि.प्र.सं. के साथ, एक बड़ी न्यायपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। धारा 104 में ही अपील के विभिन्न अधिकारों पर विचार किया गया है। धारा 104(1) द्वारा बचाई गई अपीलें दायर की जा सकती हैं। जो बचाई नहीं गई हैं, उन्हें धारा 104(2) द्वारा वर्जित कर दिया जाएगा। हमें ऐसी स्थिति में कुछ भी असामान्य नहीं लगता। परिणामस्वरूप हमारे सामने पेश भेदभाव की दलील को खारिज किया जाना चाहिए।"

51. जबकि संविधान पीठ ने संहिता में धारा 100-क की शुरुआत पर ध्यान दिया और विचार किया, उसने इस मौलिक तथ्य को भी ध्यान में रखा कि उक्त मामले

में पत्र पेटेंट अपील को ऐसे समय में प्राथमिकता दी गई थी जब संहिता की धारा 100-क और धारा 104 (2) ने पत्र पेटेंट अपील पर रोक नहीं लगाई थी। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 104 ने स्पष्ट रूप से पत्रों की पेटेंट अपीलों को सुरक्षित रखा था और परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता था कि इस तरह की अपील का मार्ग समाप्त हो गया था। पी.एस. सतप्पन ने मुख्य रूप से विश्राम किया संहिता की धारा 104 (2) जो उस समय अधिनियम की पुस्तक में मौजूद थी जब अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी।

52. यह हमें सतीश चंद्र सभरवाल मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर ले जाता है। उक्त निर्णय में इस सवाल पर विचार किया गया कि क्या प्रोबेट कार्यवाही में सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील होगी। संहिता की धारा 100-क की शुरुआत पर ध्यान देते हुए, खण्ड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया है

"7. उपरोक्त प्रावधान पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया है कि एक अपील धारा 104 की उप-धारा (1) में निर्धारित आदेशों से है और किसी अन्य आदेश से नहीं है, लेकिन यह "वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा" योग्य है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि लेटर्स पेटेंट अपील लेटर्स पेटेंट में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य होगी।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

9. गरिकापति वीरया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी एवं अन्य, एआईआर 1957 एस.सी. 540 में यह माना गया कि अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और उच्च न्यायालय में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और वाद आरंभ होने की तिथि से ही अस्तित्व में रहता है और यद्यपि प्रतिकूल निर्णय सुनाए जाने पर इसका वास्तव में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अधिकार वाद या कार्यवाही की तिथि पर प्रचलित कानून द्वारा शासित होगा, न कि उसके निर्णय की तिथि पर या अपील दायर करने की तिथि पर प्रचलित कानून द्वारा। हालांकि, यह आगे स्पष्ट किया गया कि अपील का यह निहित अधिकार केवल बाद के अधिनियमन द्वारा ही वापस लिया जा सकता है, यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से प्रदान किया गया हो और अन्यथा नहीं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

17. इस संबंध में अंतिम निर्णय एल. आर. एस. बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड और अन्य, 2004 (8) स्केल 601 द्वारा पी. एस. सतप्पन (मृत) के मामले में भेजा जाना है। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई अपील उच्च न्यायालय के दिनांक 22.08.1997 के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पत्र अपीलीय अधिकार क्षेत्र में बैठे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं है। इस प्रकार, धारा 100क के संशोधन से पहले की स्थिति प्रबल होगी। ऐसे मामले में, संहिता की धारा 104 लेटर्स पेटेंट अपील को बचा लेगी क्योंकि तीन प्रकार के आदेशों में से जिनसे धारा 104 की उप-धारा (1) में अपील प्रदान की जाती है, लेटर्स पेटेंट अपील उस समय लागू किसी भी कानून

द्वारा प्रदान की गई अपील की श्रेणी में आएगी। कुछ टिप्पणियाँ हैं जो वर्तमान विवाद के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। निर्णय के पैरा 30 में संशोधन के बाद धारा 100क के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मुद्दे पर चर्चा करते हुए, यह देखा गया कि जब विधानमंडल एक पेटेंट याचिका पत्र को बाहर करना चाहता था, तो उसने विशेष रूप से धारा 100क में उक्त संशोधन द्वारा ऐसा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विधानमंडल को पता था कि उसने धारा 104 (1) में एक बचत खंड को शामिल किया था और संहिता में धारा 4 को शामिल किया था, लेकिन धारा 100क में संशोधन के विशेष शब्दों के विशिष्ट बहिष्कार के लिए, लेटर्स पेटेंट अपील को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि विधानमंडल ने एक विशिष्ट निष्कासन का प्रावधान किया था और इस प्रकार, यह कहा जाना चाहिए कि अब धारा 100क के आधार पर, कोई भी लेटर्स पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि संहिता की धारा 100क के प्रावधान में संशोधन को देखते हुए, पहली अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों से कोई भी लेटर पेटेंट अपील अब बनाए रखने योग्य नहीं होगी, जो एक अपील योग्य आदेश है, जो बदले में उक्त अधिनियम की धारा 299 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार, हमारे पास अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह विचारणीय नहीं है।

53. यह ध्यान देने योग्य है कि *सतीश चंदर सभरवाल* मामले में हमारे न्यायालय की खण्ड पीठ को सुबल पॉल और पी. एस. सतप्पन दोनों मामलों पर

ध्यान देने का अवसर मिला था। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मुद्दा स्वयं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत सिविल न्यायालय के समक्ष रखी गई कार्यवाही के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। उक्त अधिनियम की धारा 299 में जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के अनुसार संहिता के प्रावधानों के साथ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। एकल न्यायाधीश के समक्ष जो कार्यवाही शुरू की गई थी, वह न केवल एक ऐसे कारण से उत्पन्न हुई थी जो मूल रूप से एक सिविल न्यायालय के समक्ष रखा गया था, बल्कि अपीलीय प्रावधान द्वारा स्वतः अनिवार्य किया कि वे अपील संहिता द्वारा शासित होंगी। इस आलोक में देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 क्रमशः 1940 व्यापार चिन्ह अधिनियम और 1958 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 (3) और धारा 109 (8) के समान थी।

54. जबकि प्रत्यर्थियों का यह तर्क नहीं था कि 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयक एक न्यायालयकी तरह व्यवहार करता है, हमारे विचार के लिए जो आग्रह किया गया था वह यह था कि अधिनियम पंजीयक को विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है जो अन्यथा संहिता द्वारा प्रदत्त हैं और एक सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध हैं। यह उपर्युक्त पृष्ठभूमि में था कि श्री आनंद ने प्रस्तुत किया था कि ट्रेडिंग परीक्षण को लागू किया जाना चाहिए और संहिता की धारा 100-क द्वारा

बनाए गए प्रतिबंध को लागू करने के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। सिविल कोर्ट और सामान्य रूप से न्यायालयों या अधिकरणों के बीच अंतर, नाहर औद्योगिक उद्यम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संक्षेप में बताया गया था। उक्त प्रश्न से निपटने के दौरान, *नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज* में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से प्रासंगिक रूप से टिप्पणी की:

"69. सिविल न्यायालय एक ऐसा निकाय है जो कानून के द्वारा स्थापित है। हालाँकि, विभिन्न प्रकार के कानून यहाँ मौजूद हैं, जो भिन्न-भिन्न न्यायालयों का गठन करते हैं। सिविल न्यायालय की परिभाषा के भीतर कौन सी न्यायालय आएंगी, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ही निर्धारित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत विचार किए गए सिविल न्यायालयों का उल्लेख उनकी धारा 4 और 5 में मिलता है। कुछ मुकदमे राजस्व न्यायालय के समक्ष हो सकते हैं, कुछ मुकदमे प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट के समक्ष हो सकते हैं। सिविल संहिता प्रक्रिया स्वयं यह निर्धारित करती है कि राजस्व न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं होंगे।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

71. सिविल न्यायालय का गठन बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 जैसे कानूनों के तहत किया जाता है। सिविल न्यायालयों की विशिष्ट और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उनके संदर्भ में तय की जाती है। हालाँकि, मुकदमे के विषय-वस्तु को निर्धारित मुकदमाने का अधिकार क्षेत्र संहिता की धारा 9 से निकलता है। हम अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में उक्त प्रावधान की व्याख्या पर थोड़ी देर बाद लौटेंगे।

72. पी. सारथी बनाम एसबीआई [(2000) 5 एससीसी 355: 2000 एससीसी (एलएंडएस) 699] में इस न्यायालय ने कहा कि यद्यपि न्यायालय और सिविल न्यायालय के बीच अंतर होता है, लेकिन यह माना जाता है कि एक अधिकरण जिसके पास न केवल न्यायालय के ढाँचे हैं, बल्कि उसके पास अंतिम और प्रामाणिक निर्णय या निर्णय देने की शक्ति भी है, वह सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के अर्थ में न्यायालय होगा। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) के संदर्भ में "न्यायालय" शब्द का व्यापक अर्थ माना जाता है। हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए भी न्यायालय और सिविल न्यायालय के बीच अंतर मौजूद है। पी. सारथी बनाम एसबीआई [(2000) 5 एससीसी 355: 2000 एससीसी (एलएंडएस) 699] में इस न्यायालय ने माना है: (एससीसी पृ. 360-61, पैरा 12-13)

"12. ध्यातव्य है कि परिसीमन अधिनियम की धारा 14 'सिविल न्यायालय' की बात नहीं करती है, बल्कि केवल 'न्यायालय' की बात करती है। यह आवश्यक नहीं है कि धारा 14 में जिस न्यायालय का उल्लेख किया गया है, वह 'सिविल न्यायालय' हो। इस धारा के अर्थ के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण या न्यायाधिकरण 'न्यायालय' होगा।

13. .... शब्द के सख्त अर्थ में एक न्यायालय का गठन आदेश के लिए, एक आवश्यक शर्त यह है कि न्यायालय के पास न्यायिक न्यायाधिकरण के कुछ अंशों के अलावा, एक निर्णय या एक निश्चित निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें अंतिमतः और प्राधिकरण हो जो एक न्यायिक घोषणा के आवश्यक परीक्षण हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

83.. राजस्थान एसआरटीसी [(1997) 6 एससीसी 100] में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें *भगवती देवी* [1983 एसीजे 123 (एससी)] में एक निर्णय के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय माना गया था, जिसमें संहिता के आदेश 23 में निहित सिद्धांतों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पर लागू माना गया था। संहिता में एक प्रावधान जो स्वभाव में परोपकारी है और उस प्रकृति की स्थिति में सामाजिक न्याय सिद्धांत का पालन करता है, लागू किया गया है, लेकिन वही, हमारी राय में, अपने आप में एक न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय नहीं बनाता है। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजन के लिए एक न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय क्यों माना गया है।

84. राजस्थान एसआरटीसी मामले में न्यायालय [(1997) 6 एससीसी 100] इस आधार पर आगे बढ़ा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, इस प्रकार यह दर्शाता है कि यह सिविल न्यायालय के पदानुक्रम का एक हिस्सा है। इस प्रकार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विपरीत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं होती है। दोनों न्यायाधिकरण अलग-अलग तरीके से संरचित हैं और पूरी तरह से अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किए गए हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*



89. न्यायाधिकरण को एक सिविल न्यायालय माना जा सकता था बशर्ते वह एक डिक्री पारित कर सके और इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता और/या साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में एक पूर्ण परीक्षण के उपक्रम सहित एक सिविल न्यायालय के सभी गुण थे। अब यह अति सामान्य कानून है कि अधिनियम के उद्देश्य और विषय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि संसद, उसके उद्देश्य और विषय को ध्यान में रखते हुए, अलग न्यायाधिकरण का गठन करना उचित समझती है ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान शीघ्रता से ऋणों की वसूली कर सकें, जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में निहित प्रावधानों का अनिवार्य रूप से, हमारी राय में, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है; तो उसे कोई अन्य क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है ताकि इस न्यायालय को मामले को सिविल न्यायालय से न्यायाधिकरण के तौर पर स्थानान्तरित करने में इन्हें सक्षम बनाया जा सके।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

92. हमने माना है कि न्यायालय न तो सिविल न्यायालय हैं और न ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय से आम तौर पर अपने रिट का प्रयोग करते हुए संपर्क किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र या अनुच्छेद 227 के तहत इसकी अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालय न केवल न्यायालयों पर बल्कि न्यायालयों पर भी इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। न्यायालय के निर्णयों और आदेशों की अपीलों का निर्धारण करने के लिए अपीलीय न्यायालयों का गठन किया गया है।

55. श्री सिब्लल ने शुरुआत में तर्क दिया था कि यह तथ्य कि पंजीयक को एक न्यायालय नहीं माना जा सकता है, *द एंग्लो फ्रेंच ड्रग कंपनी* में बॉम्बे उच्च न्यायालय और खोडे डिस्टिलरीज में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निर्णायक तौर पर यह तय किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज में तैयार किए गए परीक्षणों को ध्यान में रखा जाना था, तब भी यह स्पष्ट होगा कि व्यापार चिह्न का पंजीयक प्रतीक परीक्षण को पूरा नहीं करेगा। श्री सिब्लल ने अतिरिक्त रूप से परमजीत सिंह पाथेजा मामले के फैसले पर भरोसा रखा था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"12. इस न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले सर्वोच्च महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं:

(i) क्या मध्यस्थता पुरस्कार प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 9 के उद्देश्य के लिए एक "डिक्री" है?

(ii) क्या प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 9 (2) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार के आधार पर दिवाला नोटिस जारी किया जा सकता है?

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

20. धारा 2(2) और 2(14) सि.प्र.सं. परिभाषित करती है कि "डिक्री" और "आदेश" का क्या अर्थ है। यह देखने के लिए कि कोई निर्णय या निर्धारण डिक्री या आदेश है या नहीं, यह आवश्यक रूप से परिभाषा की भाषा के अंतर्गत आना चाहिए। धारा 2(2) सि.प्र.सं. "डिक्री" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "न्यायालय द्वारा व्यक्त किए जाने वाले निर्णय की

औपचारिक अभिव्यक्ति, जो सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है।

(क) कोई निर्णय जिसमें से कोई अपील किसी आदेश की अपील के रूप में होती है, या

(ख) चूक के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश।

*स्पष्टीकरण-* -डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब मुकदमे का पूरी तरह से निपटारा करने से पहले आगे की कार्यवाही करनी होती है। यह तब अंतिम होती है जब ऐसा निर्णय मुकदमे का पूरी तरह से निपटारा कर देता है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकता है;"

21. "न्यायालय", "न्यायनिर्णयन" और "वाद" शब्द निर्णायक न्यायालय से दर्शाते हैं कि केवल एक न्यायालय एक डिक्री पारित कर सकती है और वह भी केवल एक वादी द्वारा शुरू किए गए मुकदमे में और न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले द्वारा विवाद के निर्णय के बाद। यह स्पष्ट है कि एक मध्यस्थ एक अदालत नहीं है, एक मध्यस्थता एक निर्णय नहीं है और इसलिए, एक पुरस्कार एक डिक्री नहीं है।

22. धारा 2 (14) "आदेश" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है

" सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो एक डिक्री नहीं है।

23. "निर्णय" और "सिविल न्यायालय" शब्द स्पष्ट रूप से मध्यस्थों द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज करते हैं।

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

25. रामसाई बनाम जॉयलाल [ए. आई. आर. 1928 कैल 840:32 सी. डब्ल्यू. एन. 608] कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:(एयर पी. 840)

(क) प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, धारा 9 (ड) आदेश के निष्पादन में संलग्नक एक डिक्री के निष्पादन में नहीं है। किसी पंचाट के निष्पादन में संलग्नक दिवालिया होने के उपाय बनाने के उद्देश्य से धारा 9 (ड.) के अर्थ के भीतर एक डिक्री के निष्पादन में संलग्नक नहीं है: पुनः दिवालियापन सूचना [(1907) 1 के बि 478 76 एल जे के बी 171:96 एल. टी. 131 (सी. ए.)], रेफ.

(ख) मध्यस्थता अधिनियम, धारा 15-पंचाट ।  
पंचाट लागू करने के उद्देश्य का एक डिक्री है

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

28. इस न्यायालय के निर्णयों से यह तय होता है कि शब्द "जैसे कि" वास्तव में दो चीजों के बीच अंतर दिखाते हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग सीमित उद्देश्य के लिए किया जाता है। वे आगे बताते हैं कि एक वैधानिक कल्पना को उस उद्देश्य तक सीमित किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था।

29. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36, जो 1899 अधिनियम की धारा 15 के समरूप है, नीचे दी गई है:

"36. प्रवर्तन- जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता पंचाट को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, या ऐसा आवेदन किए जाने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया गया है, वहां पंचाट को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत उसी तरह लागू किया जाएगा जैसे कि वह न्यायालय का आदेश हो।

(जोर दिया गया)

वास्तव में, धारा 36 1899 के अधिनियम की धारा 15 से आगे जाती है और यह संदेह से परे स्पष्ट करती है कि प्रवर्तनीयता केवल सि.प्र.सं. के तहत है। यह किसी भी तर्क

को खारिज करता है कि एक डिक्री के रूप में प्रवर्तनीयता किसी अन्य कानून के तहत मांगी जा सकती है या दिवालिया कार्यवाही शुरू करना सि.प्र.सं. के तहत एक डिक्री को लागू करने का एक तरीका है। इसलिए प्रत्यर्थिगण का यह तर्क कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत दिए गए पंचाट को यदि अपेक्षित अवधि के भीतर चुनौती नहीं दी जाती है, तो वह धारा 35 के तहत प्रदान किए गए अंतिम और बाध्यकारी हो जाता है और इसे एक डिक्री के रूप में लागू किया जा सकता है क्योंकि यह धारा 36 के तहत प्रदान किए गए बाध्यकारी और निर्णायक है और यह कि एक पंचाट और डिक्री के बीच कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

56. जिन विभिन्न निर्णयों को हमारे विचार के लिए उद्धृत किया गया था, उनसे हम पाते हैं कि उन्हें मुख्य रूप से तीन धाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक ओर, हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो विशेष अधिनियमों में निहित पूर्व निर्णयों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए गए थे, जबकि दूसरी ओर निर्णय थे जो संहिता द्वारा शासित कार्यवाहियों से उत्पन्न हुआ। *कमल कुमार दत्ता, गंडला पन्नाला भूलक्ष्मी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, रउफ अहमद ज़ारू, गीता देवी, अंशुमन शुक्ला और केशव पिल्लई* के फैसलों में पत्रों की पेटेंट अपील की स्थिरता के सवाल पर विचार किया गया और जहां मूल रूप से विशेष अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की गई थी। *कमल कुमार दत्ता* एक मूल आदेश पर काम

कर रहे थे जिसे पूर्ववर्ती कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित किया गया था। *गंडला पन्नाला भुलक्ष्मी* में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से उत्पन्न कार्यवाही की पृष्ठभूमि में एक समान प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाया गया था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में भी यही स्थिति थी। *रौफ अहमद जारू* में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय ने एक पत्र पेटेंट अपील की स्थिरता और कार्यवाही के संदर्भ में निपटाया जो शुरू में संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के तहत एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष स्थापित की गई थी। *मो. सौद, वसंथी, मेट्रो टायर और एन. जी. नंदा* ऐसे निर्णय थे जो मूल रूप से सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू होने की पृष्ठभूमि में दिए गए थे।

57. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों का समूह निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट रूप से अलग-अलग प्रतीत होता है। जहाँ तक उन मामलों का सवाल है जो संहिता के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुए हैं, वे निस्संदेह धारा 100 क के अंतर्गत आएंगे क्योंकि वे सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिसालों का दूसरा समूह उन मामलों से संबंधित है जो एक विशेष कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के प्रयोग एक सिविल न्यायालय द्वारा तय किए गए थे। हमारे पास मिसालों का एक और समूह है जो मूल रूप से न्यायाधिकरणों द्वारा तय किए

गए मामलों से निपटता है जिन्हें उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए न्यायालय माना जाता था।

58. *कमल कुमार दत्ता* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संहिता की धारा 100-क एक पत्र पेटेंट प्रावधान के संदर्भ में आगे की अपील पर रोक लगाएगी क्योंकि उसने पाया कि जबकि पूर्ववर्ती कंपनी लॉ बोर्ड एक न्यायालय नहीं हो सकता है, उसके पास उसके सभी निहितार्थ थे। हम इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 ड. (4घ) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हैं, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाहियां माना जाएगा, भले ही उनमें निर्दिष्ट सीमित उद्देश्यों के लिए हो। हम ध्यान देते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 169 के तहत भी ऐसी ही स्थिति है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण को उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। यह भी ध्यान दें योग्य है कि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड 30, जैसा कि यह न्यायालय सुधार अधिनियम, 2021 की घोषणा से पहले मौजूद था, धारा 92 के आधार पर एक समान स्थिति के साथ लिया गया था। इस प्रकार *कमल कुमार दत्ता*, *गंडला पन्नाला भूलक्ष्मी*, *रउफ अहमद ज़ारू* और *यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस* में जो निर्णय लिए गए, वे सभी एक विशेष प्रावधान के साथ विशेष कानूनों से निकले हैं। *केशव पिल्लई श्रीधरन पिल्लई* मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

का निर्णय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिनकी विशिष्ट विशेषताओं को पहले ही ऊपर समझाया जा चुका है।

59. हम आगे यह भी देखते हैं कि मोहम्मद सौद मामले में, यह प्रश्न कि क्या लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य होगी, एक सिविल मुकदमे पर विचार करते समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश से उत्पन्न हुआ था। एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील संहिता के आदेश 43 नियम 1 में किए गए प्रावधानों के अनुसार की गई थी। एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील संहिता के आदेश 43 नियम 1 में किए गए प्रावधानों के संदर्भ में ली गई थी। इसी तरह, वसंथी में विचाराधीन मुद्दा मूल वाद की सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न हुआ। मेट्रो टायर्स में इस उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश की पृष्ठभूमि में एक पत्र पेटेंट अपील की स्थिरता के प्रश्न का जवाब देने के लिए बुलाया गया था, जिसने एक मूल वाद की बहाली के लिए एक आवेदन को खारिज करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक अपील पर विचार किया था और कहा था कि यह पहले ही समाप्त हो चुका था। *एन. जी. नंदा* के मामले में भी ऐसी ही स्थिति थी। वहाँ भी एकल न्यायाधीश ने मूल वाद कार्यवाही के उपशमन को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने वाले विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के



खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की और निर्णय लिया। यह तब हमें *अवतार नारायण बहल* में हमारे न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए ले जाता है।

60. तथापि, और इससे पहले कि हम *अवतार नारायण बहल* में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, हाल के दो निर्णयों पर ध्यान देना उचित होगा जो 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के संदर्भ में दिए गए थे और क्या उपरोक्त कानून के तहत एक अपील पर विचार करते हुए एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ एक पेटेंट पत्र अपील होगी। यह प्रश्न सबसे पहले इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के विचार के लिए रेसिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड रेसिलियंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड में आया था। फोनपे प्राइवेट लिमिटेड और अन्य<sup>31</sup> जबकि संहिता की धारा 100-क को स्वीकार नहीं किया गया था, कोर्ट इन रेजिलिएंट इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड 1940 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 के साथ-साथ 1958 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 (5) को नोटिस करने का अवसर मिला था। कोर्ट इन रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

“25. इस स्तर पर हम ध्यान दें सकते हैं कि इस न्यायालय में एक अंतर-न्यायालय अपील, मोटे तौर पर, चार स्थानों में आती

है। [सी. अन्य अग्रवाल बनाम राज्य और अन्य और जसविंदर सिंह देखें]।

- (i) सबसे पहले, अपील, जो सि.प्र.सं. के तहत उपलब्ध हैं।
- (ii) दूसरा, जहां किसी दिए गए अधिनियम में अपील का प्रावधान किया गया है।
- (iii) तीसरा, डी. एच. सी. अधिनियम की धारा 10 के तहत उपलब्ध अपील, उन निर्णयों के संबंध में जो एक एकल न्यायाधीश द्वारा सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दिए जाते हैं, जैसा कि उसी अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत समझा जाता है। इस प्रकार, इस प्रावधान के तहत एक अपील यानी दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) उपलब्ध होगी जहां एक एकल न्यायाधीश सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित करता है, जो अन्यथा सि.प्र.सं. के आदेश 43 नियम 1 के साथ पठित धारा 104 के तहत उपलब्ध नहीं है, जब तक कि यह *बाबूलाल खिमजी* में प्रतिपादित "निर्णय" की कसौटी पर खरा उतरता है।
- (iv) अंत में, लेटर्स पेटेंट के धारा 10 के तहत उपलब्ध अपील।

25.1 तत्काल मामले में, रियल इस्पात पावर लिमिटेड ने अपनी अपील को अंतिम श्रेणी यानी लेटर्स पेटेंट के खंड 10 में रखा है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है; पहले तीन स्थान लागू नहीं होंगे क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहे थे; इस अपील को बनाए रखने के लिए सि.प्र.सं.में कोई प्रावधान नहीं है और 1999 (संशोधित) व्यापार चिन्ह अधिनियम अपील के लिए प्रावधान नहीं करता है।

25.2 दूसरी ओर, पी. पी. एल. ने अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर जोर दिया है कि व्यापार चिन्ह कानून के इतिहास के कारण, एक अंतर-अदालत अपील प्रावधान का बहिष्कार निहित है।

25.3 हम आम तौर पर असहमत होते हैं। हमारे दिमाग में, 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के ढांचे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता है कि विधायिका, निहितार्थ से, एक स्तर की जांच को बाहर करने की मांग करती है जो लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत पसंद की गई अंतर-अदालत अपील के माध्यम से उपलब्ध होगी।स्वीकार करते हुए, 1999 (संशोधित) व्यापार चिन्ह अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जो स्पष्ट रूप से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत प्रदान की गई अपील के लिए प्रावधान की प्रयोज्यता को बाहर करता है।

26. तब जो प्रश्न उठता है वह यह है: क्या यह तथ्य कि सि.प्र.सं. के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, इस मामले में हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा?

26.1 इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि नेशनल सेविंग थ्रेड मामले में, जब सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि क्या गुजरात उच्च न्यायालय पर लागू लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत अंतर-न्यायालय अपील की जा सकती है, तो अंतर-न्यायालय अपील की स्थिरता पर निर्णय 1940 के पेटेंट कानून की धारा 76 की उपधारा (3) के प्रावधानों पर आधारित नहीं था, जिसमें यह प्रावधान था कि सि.प्र.सं. के प्रावधान अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में की गई अपीलों पर लागू होंगे।

26.2 स्पष्ट रूप से, उक्त अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (3) और 1958 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (8) में सि.प्र.सं. के प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों को सीधे पढ़ने से पता चलेगा कि सि.प्र.सं. संबंधित अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में की गई अपीलों पर लागू होता है।

26.3 लेटर पेटेंट (इस मामले में, खंड 10) के तहत एक अपील, हालांकि, एक विशेष कानून के तहत एक अपील में, न कि अधिनियम के तहत की गई अपील है। इसलिए, 1999 (संशोधित) व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत अपील नहीं है। इसलिए, 1999 (संशोधित) व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत एक समान प्रावधान की अनुपस्थिति, हमारी राय में, तत्काल अपील की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

61. रेजिलिएंट इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने उल्लेखनीय रूप से देखा कि 1940 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 (3) के साथ-साथ 1958 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 (8) दोनों ने संहिता के प्रावधानों को लागू करने की परिकल्पना की थी। हालाँकि, इसने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि लेटर्स पेटेंट के तहत एक अपील और इसलिए जिसे 1999 व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत प्रावधान की गई अपील के विपरीत एक विशेष कानून के तहत प्राथमिकता दी जाती है, बाद के कानून में इसी तरह के प्रावधानों को अपनाए जाने की अनुपस्थिति में, एक अंतर-अदालत अपील का उपचार प्रभावित नहीं होगा। वी. आर. होल्डिंग्स बनाम हीरो इन्वेस्टोर्कॉर्प लिमिटेड और अन्य <sup>32</sup> में कानूनी

प्रस्तुतीकरण की शुद्धता के संबंध में संदेह उठाया गया था। उपर्युक्त आपत्ति इस आधार पर ली गई थी कि रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 को नोटिस करने या विचार करने में विफल रहा है। इसी आधार पर प्रत्यर्थियों ने *वी.आर. होल्डिंग* के मामले में तर्क दिया कि *रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड* में दिया गया निर्णय पुनर्विचार या बड़ी पीठ को संदर्भित करने योग्य है। ।

62. *वी. आर. होल्डिंग्स* में न्यायालय के साथ उपरोक्त आपत्ति को नकार दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 ऐसी स्थिति में लागू होती जहां एकल न्यायाधीश सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा होता। न्यायालय ने पाया कि चूंकि उस मामले में एकल न्यायाधीश एक याचिका पर विचार कर रहा था। 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 57 के लिए संदर्भित, इसे मूल क्षेत्राधिकार और इसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधों का प्रयोग करने वाला नहीं कहा जा सकता है वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 द्वारा अधिरोपित, इसका कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

63. *अवतार नारायण बहल* की ओर लौटते हुए, हम पाते हैं कि उक्त निर्णय की विषय वस्तु वे कार्यवाही थी जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत

एक जिला न्यायाधीश के समक्ष शुरू की गई थी और जो तब इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष उसकी धारा 299 के संदर्भ में अपील दायर करने के लिए आगे बढ़ी थी। इस स्तर पर यह ध्यान देना उचित है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 ने भी इस तरह की अपील के लिए संहिता के प्रावधानों को लागू किया और इस प्रकार यह 1940 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 (3) और 1958 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 109 (8) के समान था। *अवतार नारायण बहल* में हमारे न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उचित विचार करने के बाद अंततः यह निर्णय दिया कि *सुबल पॉल और पी. एस. सतप्पन* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, एक उचित विधायी उपाय द्वारा पत्रों के पेटेंट की शक्ति को छीनने पर आधिकारिक घोषणाएं थीं। अवतार नारायण बहल मामले में न्यायालय ने *कमल कुमार दत्ता* को इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में पढ़ा और व्याख्या की कि एक विशेष अधिनियम के तहत उत्पन्न अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ एक पत्र पेटेंट अपील संहिता की धारा 100-क द्वारा वर्जित होगी। इसके अलावा, यह देखा गया कि संहिता की धारा 100-क में सन्निहित सर्वोपरी खंड एक एल. पी. ए. को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के विधायिका के इरादे का एक स्पष्ट संकेत था, जिसे मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ प्राथमिकता दी जा सकती है। पूर्ण न्याय पीठ ने

आगे कहा कि संहिता की धारा 100-क की भाषा को केवल संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों तक ही निष्कासन हेतु सीमित करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता है, और न ही अन्य अधिनियमों के तहत ऐसा समझा जा सकता है ।

64. *अवतार नारायण बहल* के वास्तविक अनुपात निर्णय को समझने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुख्य कार्यवाही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से उत्पन्न हुई थी। इसलिए यह धारा 299 है जो लागू होगी और जो स्पष्ट और सीधे शब्दों में यह प्रावधान करती है कि उच्च न्यायालय में अपील "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो अपीलों पर लागू होती है"। इस प्रकार पूर्ण न्याय पीठ से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया कि एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त अपीलीय अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में कार्य करने के बाद एल.पी.ए. का प्रावधान उपलब्ध होगा या नहीं। हालाँकि धारा 299 के एक केवल पठन से प्रकट होता है, अपील का मार्ग अपीलों से संबंधित संहिता के प्रावधानों के अधीन तय किया गया था। इस प्रकार धारा 100क स्पष्ट रूप से लागू होती है। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें विशेष अधिनियम ने केवल एक अपील का प्रावधान किया और इसे उस पर छोड़ दिया। ऐसी स्थितियों में, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल सेविंग थ्रेड मामले में समझाया था कि, एक बार अपील उच्च न्यायालय के पोर्टल में प्रवेश करने के बाद यह लागू नियम होंगे

जो इस तरह की अपील के नियति को नियंत्रित करेंगे, जिसमें यह मुद्दा भी शामिल होगा कि क्या एल. पी. ए. बनाए रखने योग्य है। न तो धारा 91 और न ही 1999 व्यापार चिन्ह अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान यह निर्धारित करता है कि आगे कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसा कहना गलत होगा या जो अपील जब पसंद की जाएगी तो संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होगी क्योंकि वे अपीलों से संबंधित है।

65. विशेष अधिनियमों से उत्पन्न होने वाली अपीलों पर धारा 100 क की प्रयोज्यता से संबंधित अवतार नारायण बहेल में की गई टिप्पणियों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 के संदर्भ में समझना होगा और यह निस्संदेह एक विशेष अधिनियम था। इसके अतिरिक्त, हम यह मानेंगे कि वे टिप्पणियाँ वहाँ भी सही होंगी जहाँ विशेष कानून अपील के मार्ग को संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित और विनियमित करने का आदेश देता है। हम उन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखते हैं जो इस न्यायालय की एक पूर्व पूर्ण न्याय पीठ द्वारा महली देवी मामले में प्रतिपादित किए गए थे, जिसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 54 के संदर्भ में टिप्पणी की थी: -

*"12. कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और इस विषय पर न्यायिक घोषणाओं की उपरोक्त चर्चा से जो पता चलता है, वह यह है कि जब तक कोई कानून स्वयं उच्च न्यायालय में दूसरी अपील को प्रतिबंधित नहीं करता है या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को अंतिम नहीं बनाता है (जैसा*



कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 43 के मामले में होता है), तब तक लेटर पेटेंट अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले से लेकर न्यायालय की खण्ड न्याय पीठ तक होगी। अधिनियम की धारा 54 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और इसलिए, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक अपील बनाए रखने योग्य होगी। यहाँ हम नेशनल सेविंग थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चैंडविक एंड ब्रदर्स ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 357 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देख सकते हैं। न्यायालय व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76 के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर रहा था। उक्त खंड के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। सवाल यह था कि क्या उच्च न्यायालय का निर्णय लेटर्स पेटेंट के तहत इसकी अपील पर विचार करने के उद्देश्य से एक निर्णय होगा। यह कहा गया था कि "आम तौर पर उच्च न्यायालय में अपील पहुंचने के बाद, इसका निर्धारण उस न्यायालय के नियमों या व्यवहार और प्रक्रिया के अनुसार और उस चार्टर के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसके तहत वह न्यायालय है। जिसका गठन किया गया है और जो उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की विधि और तरीके के संबंध में उसे शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 76, उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार प्रदान करती है और इसके बारे में और कुछ नहीं कहती है। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय को धारा 76 द्वारा प्रदत्त अपीलीय अधिकार क्षेत्र के रूप में जब्त किया जा रहा है। उसे उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उसी तरह करना होगा जैसे वह अपनी अन्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और जब ऐसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एकल

न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो उसका निर्णय लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत अपील के अधीन हो जाता है, जिसके विपरीत व्यापार चिन्ह अधिनियम में कुछ भी नहीं है।

13. इन टिप्पणियों ने पूरे विवाद को पूरी तरह से शांत कर दिया। एक बार जब इस न्यायालय में अपील आती है तो बाकी कार्यवाही इस न्यायालय के व्यवहार के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार और चार्टर के प्रावधानों, यानी लेटर्स पेटेंट के अनुसार होगी। एकमात्र अपवाद तब होगा जब कोई अधिनियम विशेष रूप से ऐसी अपील को प्रतिबंधित करता है। जैसा कि पहले से ही इस मामले में अधिनियम में देखा गया है, यानी अधिनियम की धारा 54 में दूसरी अपील के अधिकार के लिए कोई विशिष्ट बाधा नहीं है। इसके बाद लेटर पेटेंट के तहत दूसरी अपील संबंधित पक्ष को उपलब्ध होगी।

66. महली देवी और अवतार नारायण बहल के मामले में बताई गई विधिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि लेटर्स पेटेंट उपाय या तो तब समाप्त हो जाएगा जब विशेष कानून स्वयं द्वितीय अपील पर रोक लगाता है या जहां उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय में की गई अपील अपीलों से निपटने वाली संहिता के प्रावधानों के अनुसार होगी।

67. उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय संसाधन आवंटन में 2012-33 के विशेष संदर्भ संख्या में बहुमत के पक्ष में बोलने वाले न्यायमूर्ति डी. के. जैन के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझाया, जो किसी निर्णय के अनुपात निर्धारण के विवेक को नियंत्रित करते हैं।-

"70. प्रत्येक मामले में तथ्यों का एक अलग समूह होता है और एक निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर एक मिसाल है: निर्णय देते समय एक न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात को पूर्ववर्ती मूल्य नहीं माना जा सकता है। एक निर्णय का सार जो पक्षकारों को मामले से जोड़ता है, वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से, निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। पूर्व निर्णय को लागू करने के मामले में, विद्वान न्यायमूर्ति बेंजामिन कार्डोजो ने द नेचर ऑफ द ज्यूडिशियल प्रोसेस में कहा था कि "यदि न्यायाधीश को इसे बुद्धिमानी से सुनाना है, तो चयन के कुछ सिद्धांत सभी संभावित निर्णयों के बीच उनका मार्गदर्शन करने के लिए होने चाहिए जो मान्यता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं" और "लगभग हमेशा उनका पहला कदम उनकी जांच और तुलना करना है;" "यह खोज, तुलना और इससे थोड़ी अधिक की प्रक्रिया है" और इसे बिल्कुल समान करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए हाथ में आये मामलों के प्रकार कई नमूने के तौर पर देखे गये मामलों के विपरीत हो सकते हैं " क्योंकि उन मामलों में "वह व्यक्ति जिसके पास सबसे अच्छा कार्ड सूचकांक रहा हो वह इस मामले में भी सबसे बुद्धिमान न्यायाधीश कहा जायेगा। किसी मामले के पूर्व निर्णय के साथ दूसरे मामले के पूर्व निर्णय की तुलना करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए, उन्होंने निम्नलिखित प्रज्ञात्मक शब्दों में इस प्रक्रिया का सारांश दिया, यदि दोनों मामलों के प्रकार समान नहीं हुए तब :

" यह तब होता है दोनों मामले मेल नहीं खाते हैं, जब सूचकांक में संदर्भ विफल हो जाते हैं, जब कोई निर्णायक उदाहरण नहीं होता है, तो न्यायाधीश का गंभीर कार्य शुरू होता है। फिर उसे अपने सामने वादियों के लिए कानून

बनाना होगा। उनके लिए इसे बनाने में, वह इसे दूसरों के लिए बनाएगा। बेकन का उत्कृष्ट कथन है: 'कई बार, निर्णय के लिए अनुमान की गई चीजें मामूली और शून्य हो सकती हैं, जब इसका कारण और परिणाम संपत्ति के बिंदु तक फासले बनाते हों। आज की सजा आज को सही और कल गलत बना देगी। "

71. निर्णयों के पूर्ववर्ती मूल्य के संदर्भ में, उड़ीसा राज्य बनाम मो.इलियास [(2006) 1 एस. सी. सी. 275:2006 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 122] इस न्यायालय ने कहा:(एससीसीपी। 282, पैरा 12) निर्णय( (i) प्रत्यक्ष और अनुमानित भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष तक तथ्यों का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष, या बोधगम्य तथ्यों से प्राप्त करता है; (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयान; और (iii) उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय। निर्णय एक प्राधिकरण है जो वास्तव में क्या निर्णय लेता है। ए में क्या सार है निर्णय उसका अनुपात है और न ही उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से क्या प्रवाहित होता है।

72. हाल ही में, भारत संघ बनाम अमृत लाल मनचंदा [(2004) 3 एस. सी. सी. 75 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 662] मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:(एससीसी पृ. 83, पैरा 15)

"15. न्यायालयों के अवलोकन को न तो यूक्लिड के सिद्धांतों के रूप में पढा जाना चाहिए और न ही अधिनियम के प्रावधानों के रूप में और वह भी उनके संदर्भ से बाहर नहीं लिया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढा जाना चाहिए जिसमें वे बताए गए प्रतीत होते हैं। न्यायालयों

के फैसलों को कानून के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी अधिनियम के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं। वे विधियों के शब्दों की व्याख्या करते हैं; उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

73. एक निर्णय को समग्र रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना भी महत्वपूर्ण है कि यह संक्षिप्त सार्वभौमिक प्रयोज्यता के साथ एक अमूर्त विद्या सम्बन्धी प्रवचन नहीं है, बल्कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर बहुत अधिक आधारित है। निर्णय के प्रत्येक भाग को दूसरे भागों से जटिल रूप से जोड़ा जाता है जो एक बड़े पूरे का गठन करते हैं और इस प्रकार, तार्किक धागे को अक्षुण्ण रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में, इस्लामी शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक राज्य [(2003) 6 एस. सी. सी. 697] मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: (एससीसी पृ. 719, पैरा 2)

"2. पूरे निर्णय को पढ़ने के बाद ही फैसले के अनुपात का पता लगाना होता है। वास्तव में, निर्णय का अनुपात वही है जो निर्णय में ही निर्धारित किया गया है। सवाल के जवाब को अनिवार्य रूप से फैसले में जो बताया गया है, उसके संदर्भ में पढ़ना होगा, न कि अलग से। किसी भी अवलोकन, कारणों और सिद्धांतों के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, निर्णय के दूसरे भाग पर विचार किया जाना चाहिए। निर्णय की एक पंक्ति को इधर-उधर पढ़ने से निर्णय के पूरे अनुपात का पता नहीं चल सकता है।"

68. उन तथ्यों को ध्यान में रखने का महत्व जिनके संदर्भ में कोई निर्णय दिया गया हो सकता है मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन मामले में निम्नलिखित शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोर दिया गया: -

"64. न्यायालय को इस बात पर चर्चा किए बिना किसी निर्णय पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वास्तविक स्थिति निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति के साथ कैसे मेल खाती है, जिस पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि इसका पता सभी भौतिक तथ्यों और मामले में शामिल मुद्दों का विश्लेषण करके लगाया जाना चाहिए और दोनों पक्षों की ओर से तर्क दिया जाना चाहिए। किसी दिए गए मामले में निर्णय का पालन नहीं किया जा सकता है यदि इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। तथ्यों या अतिरिक्त तथ्यों में थोड़ा सा अंतर निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य में बहुत अंतर ला सकता है। न्यायालय के किसी निर्णय को अधिनियम के रूप में नहीं पढा जाना चाहिए, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों को स्थापित करने में किए गए हैं। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है। किसी निर्णय पर आंख मूंदकर भरोसा करके मामलों का निपटारा करना उचित नहीं है। (एम. सी. डी. बनाम गुरनाम कौर [(1989) 1 एस. सी. सी. 101:ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 38], कर्नाटक सरकार बनाम गौरम्मा [(2007) 13 एस. सी. सी. 482:ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 863] और हरियाणा राज्य बनाम धरम सिंह [(2009) 4 एस. सी. सी. 340 (2011) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 112]।"

69. स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है। जिन विभिन्न निर्णयों को हमारे विचार के लिए उद्धृत किया गया है और जिन पर ऊपर ध्यान दिया गया है, उनमें से जिन लोगों ने संहिता की धारा 100-क को एक अपील के मार्ग को प्रतिबंधित करने के रूप में मान्यता दी थी, जो अन्यथा पत्र पेटेंट प्रावधानों के संदर्भ में उपलब्ध हो सकता है, या तो सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों या निर्णयों से उत्पन्न हुआ था या जहां यह सिविल न्यायालय थी जिसने निर्णय के प्रमुख स्तर का गठन किया था, हालांकि यह एक विशेष अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।

70. जहाँ तक *गंडला पन्नाला भूलक्ष्मी* और *यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस* के निर्णयों का प्रश्न है, वे पूर्ण पीठ उन मामलों से उत्पन्न हुए थे जो मूल रूप से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष रखे गए थे। जहाँ तक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थिति का प्रश्न है, हम पाते हैं कि *नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस* मामले में, यह संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या ऐसे अधिकरण को सिविल न्यायालय के समान दर्जा दिया जा सकता है। उपर्युक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया था कि ऋण वसूली अधिकरण को भी सिविल न्यायालय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के संबंध में संभवतः यही कहा जा सकता है कि मोटर यान अधिनियम,

1988 में ऐसे उपबंध सम्मिलित हैं जो उन्हें सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, यद्यपि वे शक्तियाँ उसमें निर्दिष्ट सीमित उद्देश्यों के लिए ही हैं।

71. हालाँकि, यह स्पष्ट है कि हमारे विचारार्थ उद्धृत किए गए किसी भी निर्णय में संहिता में उल्लिखित "डिक्री" या "आदेश" शब्दों की परिभाषा पर ध्यान नहीं दिया गया है। संहिता की धारा 2(2) में "डिक्री" शब्द को न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्णायक रूप से पक्षकारगण के अधिकारों का निर्धारण करता है। संहिता की धारा 2(14) में "आदेश" शब्द को सिविल न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो डिक्री नहीं है। यद्यपि, वाक्यांश, "सिविल न्यायालय" को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति संहिता की धारा 2(4) से इसके लिए लागू होने वाले अर्थ को आसानी से समझ सकता है, जो "जिला" शब्द को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार क्षेत्र के एक प्रमुख सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को संदर्भित करता है।

72. इसलिए, निस्संदेह, संहिता में जहाँ भी "आदेश" शब्द आता है, उसे संहिता की धारा 2(14) को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए। संहिता की धारा 100-क उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय से आगे की अपील दायर करने को प्रतिपादित करती है, जहाँ ऐसा एकल न्यायाधीश किसी मूल



या अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई कर रहा हो। इस प्रकार इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि जहाँ किसी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार कर लिया है, वहाँ आगे कोई अपील नहीं होगी। आगे की अपील करने पर रोक उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के बावजूद लागू रहेगी।

73. हालाँकि, हम पाते हैं कि जब संहिता की धारा 100-क किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की बात करती है, तो इसे अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 2(14) के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, जो स्पष्ट शब्दों में इसे डिक्री के अतिरिक्त किसी अन्य आदेश के रूप में परिभाषित करता है, जो एक सिविल न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के बराबर है। जैसा कि हम संहिता की धारा 100-क की व्याख्या करते हैं, यह केवल उस स्थिति में दूसरी अपील पर वर्जन लगाती प्रतीत होती है, जहाँ एकल न्यायाधीश ने संहिता द्वारा परिभाषित डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई की हो। *कमल कुमार दत्ता* ने पाया था कि कंपनी विधि बोर्ड के पास न्यायालय के सभी अधिकार मौजूद थे और इसके परिणामस्वरूप संहिता की धारा 100-क लेटर्स पेटेंट के संदर्भ में आगे की अपील पर वर्जन लगाती है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ *गंडला पन्नाला भूलक्ष्मी* मामले में यह देखने में विफल रही कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एक

सिविल न्यायालय नहीं है, तथा संहिता की धारा 100-क और उसके अनुसार आगे की अपील पर वर्जन केवल संहिता द्वारा परिभाषित डिक्री या आदेशों पर ही लागू होगी। *यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस* में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि संहिता की धारा 100-क को केवल संहिता के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों तक ही अपील के अधिकार को सीमित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन वह संहिता की धारा 2(14) पर ध्यान देने या उस पर विचार करने में भी विफल रही। *मोहम्मद सऊद, वसंथी, मेट्रो टायर्स, एन.जी. नंदा* के मामले में निर्णय उन मामलों से उत्पन्न हुए जो मूल रूप से सिविल न्यायालय के समक्ष रखे गए थे।

74. हमारे द्वारा ऊपर देखे गए निर्णय, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है और प्राक्कल्पना की गई है कि संहिता की धारा 100-क लेटर्स पेटेंट उपाय पर वर्जन लगाएगी, इस प्रकार सभी या तो संहिता से उत्पन्न कार्यवाहियों के संबंध में दिए गए हैं, या ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में दिए गए हैं, जहाँ एक सिविल न्यायालय को किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकारी माना गया हो और इस प्रकार वे स्पष्ट रूप से एक अलग आधार पर खड़े हों। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के संदर्भ में दिए गए निर्णयों की आवश्यक रूप से उनमें निहित अपीलीय उपबंधों के प्रकाश में विवेचना की जानी चाहिए, तथा ऐसी

अपीलों को संहिता के उपबंधों के अधीन बनाया जाना चाहिए। ऐसे अन्य निर्णय भी थे जो अधिकरणों या निकायों द्वारा सुनाए गए थे, जिन्हें वैधानिक रूप से न्यायालय का दर्जा प्राप्त था।

75. इन अपीलों में प्राप्त तथ्यों पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि निर्विवाद रूप से, व्यापार चिह्न पंजीयक एक सिविल न्यायालय नहीं है। यद्यपि सिविल न्यायालय को उपलब्ध कुछ शक्तियाँ उसके हाथों में दी जा सकती हैं और वह उनका प्रयोग कर सकता है, फिर भी इससे वह सिविल न्यायालय नहीं बन जाता। हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एंग्लो-फ्रेंच ड्रग कंपनी और खोडे डिस्टिलरीज के निर्णयों के आलोक में यह मामला "प्रतीकात्मक न्यायालय " की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। 1999 के व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 91 में अपीलीय उपाय को संहिता के उपबंधों द्वारा शासित करने का प्रावधान नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर पाया है, यह 1940 के व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 76 और 1958 के व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 109 के साथ-साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 से विचलन है, जिसके आधार पर पूर्ण पीठ ने अवतार नारायण बहल के मामले में निर्णय सुनाया था। उपरोक्त सभी बातें यह संकेत देती हैं कि धारा 91 की शक्ति का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ले.पे.अ. पर रोक नहीं होगी।

76. यद्यपि संहिता निस्संदेह लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत उपलब्ध उपचार पर वर्जन लगा सकती थी, फिर भी इसके उपबंधों को अनिवार्यतः इसके द्वारा शासित मामलों और अपीलों के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए। हमें संदेह है कि संहिता की धारा 100क के उपबंधों को या तो बढ़ाया जा सकता है या इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है कि उनका उद्देश्य उन सभी अपीलों को शामिल करना है जो अन्यथा प्रस्तुत की जा सकती हैं या विशेष अधिनियमितियों में निहित उपबंधों के अनुसार शुरू की जा सकती हैं। यह निश्चित रूप से उन कानूनों में निहित अपीलीय उपबंधों के अधीन है तथा इस बात पर निर्भर करता है कि आगे की अपीलें संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होंगी या नहीं। जहाँ अपीलीय उपबंध विशेष रूप से अपील के अधिकार को अपील से संबंधित संहिता के उपबंधों के अधीन करते हैं, वहाँ धारा 100 क स्पष्ट रूप से लागू होगी और ले.पे.अ. के उपाय पर वर्जन लगाएगी।

77. ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 100क का उद्देश्य अंतर-न्यायालय अपील के उपाय को प्रभावहीन करना और समाप्त करना है, जो अन्यथा संहिता द्वारा शासित मामलों के संबंध में लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत उपलब्ध हो सकता है। जैसा कि संहिता की उद्देशिका से ही स्पष्ट है, इसका उद्देश्य "सिविल न्यायालयों" की प्रक्रिया से संबंधित विधियों को समेकित करना है। संहिता की धारा 4 और 104 के आधार पर उच्च न्यायालयों की लेटर्स पेटेंट शक्तियाँ निस्संदेह सुरक्षित रहें। यद्यपि यह शक्ति निस्संदेह छीनी जा सकती है, जैसा कि *सुबल पॉल* और *पी.एस. सथप्पन* के

मामले में अभिनिर्धारित किया गया था, फिर भी धारा 100क को अपील के मार्ग या अधिकार के एक निबंध के रूप में देखना गलत हो सकता है, जैसा कि सामान्य रूप से कानूनों द्वारा प्रावधान किया गया है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो सिविल न्यायालय की डिक्रियों या आदेशों से संबंधित नहीं हैं। उपर्युक्त अनिवार्यतः इस चेतावनी के अधीन होगा कि जहाँ विशेष कानून संहिता के उपबंधों को अपनाता है और उन्हें अपीलों पर लागू करता है, वहाँ धारा 100क के आधार पर ले.पे.अ. उपाय समाप्त हो जाएगा।

78. हमारा मानना है कि धारा 100क का आशय द्वितीय अपील तक ही सीमित होगा, जब वह अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हो, बशर्ते वह संहिता द्वारा परिभाषित डिक्री या आदेश से संबंधित हो। इस प्रकार यह वर्जन केवल तभी लागू होगा जब वह डिक्री या आदेश, जिसके विरुद्ध एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई थी, सिविल न्यायालय का हो। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि धारा 2(14) में "सिविल न्यायालय" शब्द का उपयोग किया गया है, न कि "न्यायालय"। इस प्रकार यह संदेहास्पद होगा कि क्या आम तौर पर तैयार किए गए "न्यायालय के दिखावे" के परीक्षण का कोई अनुप्रयोग होगा। हालाँकि, यदि हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि इस तरह के परीक्षण को धारा 100क के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से लागू किया जा

सकता है, तो भी व्यापार चिह्न पंजीयक मानकों को निर्धारित रूप में योग्य नहीं ठहराएगा।

79. उपरोक्त के अतिरिक्त, ले.पे.अ. उपाय भी उपलब्ध नहीं होगा, जहाँ विशेष कानून अपील उपाय को अपील पर लागू नियमों का पालन करने के अधीन करता है और संहिता में सन्निहित है। एक बार जब अपील को संहिता में शामिल नियमों के अधीन कर दिया जाता है, तो धारा 100 क सहित अपील पर सभी प्रतिबंध आकर्षित और संलग्न हो जाएँगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मामले में अपील उपबंध को संहिता के अंतर्गत लगाए गए सभी प्रतिबंधों को जानबूझकर अपनाने वाला माना जाएगा और यह लेटर्स पेटेंट उपबंध को अभिभावी करेगा। यह *अवतार नारायण बहल* के अनुपात निर्णय के अनुरूप होगा।

80. अवतार नारायण बहल मामले में पूर्ण पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि धारा 100क संहिता से उत्पन्न मामलों तक ही सीमित रहेगी तथा इसका बहिष्करण अन्य अधिनियमितियों पर लागू नहीं होगा। इस प्रस्तुति को सही रूप से अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि धारा 299 के अनुसार अपील "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार होगी, जो अपीलों पर लागू होती है।" इस प्रकार धारा 100क के उपबंध स्पष्ट रूप से ऐसी कार्यवाहियों के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। संभवतः इन मामलों में स्थिति ऐसी ही होती यदि 1999 के व्यापार चिह्न अधिनियम में 1940 के व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 76 (3) या 1958 के

व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 109 (8) जैसे उपबंध जारी रहते। वर्तमान में जो अपीलीय उपबंध है, उसमें यह अनिवार्य नहीं है कि अपील का रास्ता संहिता के उपबंधों के अधीन होगा या उसके द्वारा शासित होगा। 1999 के व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 91 में अपील के अधिकार को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाले किसी भी उपबंध के अभाव में, ले.पे.अ. उपाय संहिता की धारा 100 क द्वारा वर्जित नहीं होगा और लागू होगा।

81. तदनुसार, तथा उपरोक्त सभी कारणों से, हम उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करते हैं। इसलिए अपीलों को 19.09.2023 को विचारार्थ रखा जाए।

न्या. यशवंत वर्मा

न्या. धर्मेश शर्मा

सितंबर 06,2023

एसयू/आरएसके

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में आदेश का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।